चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 09 मई–15 मई 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भ्रष्टाचार की उड़ान

पनामा से इटली

दीनबंधु क़बीर

काले धन की जांच करने और निगरानी रखने के लिए बनी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को पनामा मामले की भनक क्यों नहीं लग पाई? अख़बारों की सुर्ख़ियां बनने के बाद ही पीएमओ को इस बारे में जानकारी हुई और जांच का आदेश जारी हुआ. पीएमओ ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि आख़िर एसआईटी क्या कर रही थी? यह सवाल अहम है, लेकिन इसे पूछने और इसकी वजह जानने के बजाय पूरा देश बेमानी बहस में लगा है. देश के काले धन मामले की जांच कितनी सटीक तरीके से चल रही होगी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है. लोगों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा कि कितने शातिराना तरीके से पानी की किल्लत और किसानों की तबाही के मसले को विचार के केंद्र से खिसका कर पनामा होते हुए इटली ले जाया गया.

बहरहाल, रिश्वत लेकर हेलिकॉप्टर खरीदने और काले धन को विदेशों में निवेश करने के दो पुराने, लेकिन ताजा खुले मामलों पर चल रही बहस में पूरा देश मुब्तिला है. पनामा लीक्स का मसला हो या अगस्टा हेलिकॉप्टर डील में हुई भारी रिश्वतखोरी का, ऐसे मामलों को अलग करके नहीं देखा जा सकता. भ्रष्टाचार के मामलों में भेदभाव बरत कर देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाया जा सकता. पनामा लीक्स मामले में कौन-कौन बड़ी हस्तियां लिप्त हैं, उनके नाम अभी उजागर नहीं हुए हैं. अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कुछ बड़ी कंपनियों के नाम उजागर हुए, लेकिन जैसे ही भाजपा नेता एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का नाम सामने आया, वैसे ही चर्चा बदल गई. अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील फिर से सामने आ गई और इसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अलमबरदारों के नाम आधिकारिक तौर पर पटल पर आ गए. विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया से गुज़र रहा देश असली मुद्दों से भटक कर घपलों-घोटालों के आरोप-प्रत्यारोपों में उलझा हुआ है. किसी भी घोटाले में निर्णायक क़ानूनी कार्रवाई शक्ल में आती हुई नहीं दिख रही है. केंद्र की सत्ता पर आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी घपलों-घोटालों का राजनीतिक फ़ायदा उठाने से आगे क़दम बढ़ाती हुई दिखाई नहीं देती है.

देश की मुख्य धारा में चल रही बहस में शामिल होते हुए हम पहले पनामा लीक्स के बारे में और फिर अगस्टा हेलिकॉप्टर डील की परतें खोलेंगे. पनामा लीक्स पर बात करने के लिए जॉन डो के छद्म नाम से मशहूर शख़्स के इर्द-गिर्द जाना होगा, जिसने वर्ष 2015 की शुरुआत में जर्मनी के एक अख़बार को कुछ कागजात उपलब्ध कराए, जो पनामा देश और उसके ज़रिये होने वाले एक विशालकाय वैश्विक घोटाले के दस्तावेज़ थे. इस मामले ने एक ही झटके में पनामा का नाम पूरी दुनिया, खासकर भारत में जबर्दस्त चर्चा में ला दिया. पनामा लीक्स सवा करोड़ से भी ज़्यादा गोपनीय दस्तावेज़ों का पुलिंदा है, जिसमें 2.14 लाख कंपनियों के बारे में सनसनीख़ेज जानकारियां शामिल हैं. इन दस्तावेज़ों को मोस्सैक फोंसेका नामक कंपनी ने संकलित किया है. इनमें कंपनी के शेयर होल्डर्स और निदेशकों की पहचान भी है. इन दस्तावेज़ों में बताया गया है कि किस तरह रईसों और सरकारी अधिकारियों ने लोगों की नज़रों से संपत्ति छुपाई. जब ये दस्तावेज़ पहली बार प्रकाशित हुए, तो इनमें पांच देशों अर्जेंटीना, आइसलैंड, सऊदी अरब, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख शामिल थे. उनके साथ 40 दूसरे देशों के प्रमुखों के नज़दीकी रिश्तेदार, सरकारी अधिकारी और इन राष्ट्र प्रमुखों के नज़दीकी सहयोगी शामिल थे. इनमें शामिल कंपनियों में से आधी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स से हैं और ज़्यादातर बैंक, क़ानूनी कंपनियां एवं दलाल हॉन्गकॉन्ग में हैं.

यह बात भी सामने आई कि मोस्सैक फोंसेका के ज़रिये अस्तित्व में आईं कुछ कंपनियां संबद्ध देशों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नशीले द्रव्यों के व्यापार, धोखाधड़ी और कर चोरी में शामिल रही हैं. एक अनजाने व्हिसिल ब्लोअर द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल कागजात 2.6 टेरा बाइट के थे और उनमें 1970 तक के सौदों का ब्यौरा है. इस लीक के दस्तावेज़ों का भारी-स्वरूप देखकर अख़बार ने इसके लिए खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय समूह की सेवाएं लीं और 76 देशों के 400 पत्रकारों एवं 107 मीडिया संगठनों को दस्तावेज़ों की जांच करने का काम सौंपा. इसकी पहली रिपोर्ट तीन अप्रैल 2016 को प्रकाशित हुई. मई 2016 तक पूरे दस्तावेज़ प्रकाशित करने की योजना है. भारत से जो कुछ बड़े नाम उजागर हुए, उनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएएफ के सीईओ कुशल पाल सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी और नेताओं में पश्चिम बंगाल के शिशिर बाजोरिया, दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के अनुराग केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह आदि शामिल हैं. पनामा प्रकरण में भारत के 50 बड़े लोगों के नाम शामिल हैं. आप हैरत करेंगे कि इन बड़े लोगों की लिस्ट में इकबाल मिर्ची का नाम भी शामिल है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास माना जाता था, जिसकी मौत तीन वर्ष पहले हो चुकी है. यानी पनामा लीक्स का विस्तार प्रशांत महासागर से भी ज़्यादा और गहरा है, जिसने धरती के बहुत बड़े भूभाग को अपने घेरे में ले लिया है. जनता के दबाव पर आइसलैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सफाई हम देख चुके हैं, लेकिन भारत में इस तरह की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. भारत में सारा प्रभाव चर्चा से अधिक नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिल मार्च तक जा सकता है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच का आदेश दे दिया है और कई एजेंसियों को मिलाकर केंद्र सरकार ने जांच समूह भी बनाया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जांच इकाई, उसके विदेशी कर और कर शोध विभाग, वित्तीय जांच इकाई और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया आदि शामिल हैं. लेकिन, भारत में होने वाली जांच और उसके परिणाम को लेकर कोई उम्मीद नहीं जगती. बोफोर्स से लेकर व्यापमं तक जांचों का क्या हश्र हुआ या हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है. इस खुलासे में जिन भारतीय हस्तियों के नाम सामने आए हैं, उनकी इज्जत पर थोड़ा दाग लगने के अलावा क़ानूनी कार्रवाई कितनी आगे बढ़ेगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

भारत में कार्रवाई के नाम पर आयकर विभाग ने पनामा पेपर्स मामले में महानायक अमिताभ बच्चन को सवालों की नई लिस्ट भेजी है. बच्चन ने विदेश में कंपनियां खोलने के आरोप से इंकार किया था, जिनका उल्लेख पनामा पेपर्स में था. अमिताभ बच्चन ने हाल में आयकर विभाग को भेजे गए अपने जवाब में उन चार कंपनियों से किसी तरह का संबंध होने या उनमें हिस्सेदारी से इंकार किया था, जिनके बारे में पनामा की विधि सेवा प्रदाता कंपनी मोस्सैक फोंसेका के लीक दस्तावेज़ों में दावा किया गया था. अमिताभ ने कहा था कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है और वह सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड और ट्रैम्प शिपिंग लिमिटेड के बारे में कुछ नहीं जानते. वह कभी भी इनमें से किसी कंपनी के निदेशक नहीं रहे. लेकिन, बाद में पनामा लीक्स से मिले कागजातों के आधार पर अमिताभ बच्चन के दावे ग़लत पाए गए. अमिताभ बच्चन की एबीसीएल लॉन्च होने से दो वर्ष पहले ही उक्त चारों कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थीं. चारों कंपनियां उमेश सहाय और डेविड माइकल पेट ने स्थापित की थीं.

इसी तरह अमिताभ बच्चन की बहू एवं मशहूर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का नाम भी पनामा-गेट से जुड़ा पाया गया. मोस्सैक फोंसेका के रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि ऐश्वर्या राय रजिस्टर्ड कंपनी की डायरेक्टर थीं. गोपनीयता बरतने के इरादे से नाम को ए. राय कर दिया गया था. ऐश्वर्या राय और उनका परिवार तीन वर्षों तक ऐसी कंपनी का हिस्सा रहे, जो टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड की गई थी. ऐश्वर्या राय, उनके पिता कृष्णराज राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय 14 मई 2005 को एमिक पार्टनर्स लिमिटेड नामक कंपनी में डायरेक्टर बनाए गए थे. 18 जून 2005 को एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में बोर्ड प्रस्ताव लाकर ऐश्वर्या राय को शेयर होल्डर बना दिया गया था. पांच जुलाई 2005 को फोंसेका के कर्मचारियों की आंतरिक बातचीत में भी ऐश्वर्या राय के नाम का जिक्र आया, जिसमें गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनका नाम छोटा करके ए. राय किया गया था. दस्तावेज़ों के मुताबिक, वर्ष 2008 में अभिषेक बच्चन से शादी के बाद कंपनी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. दस्तावेज़ों में ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से 18 जून 2005 को दुबई में हुई बोर्ड बैठक में पास किए गए एक प्रस्ताव का भी जिक्र मिलता है, जिसमें ऐश्वर्या राय और उनकी मां ने डायरेक्टर पद छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वे शेयर होल्डर बने रहे थे. इस बैठक की अध्यक्षता ऐश्वर्या राय के पिता ने की थी और प्रस्ताव पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

देखिए कर चोरों के चेहरे

दुनिया में सबसे ज़्यादा गोपनीय ढंग से काम करने वाली कंपनियों में से एक पनामा की मोस्सैक फोंसेका के एक करोड़ 10 लाख गोपनीय दस्तावेज़ लीक हो गए. इन दस्तावेज़ों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के परिवार के सदस्य, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडर गुनलॉन्गसॉन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के क़रीबियों से लेकर मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं के नाम हैं. इन लोगों ने टैक्स हेवन देशों में अकूत संपत्ति जमा की. इनमें क़रीब 500 भारतीयों के भी नाम हैं. इन गोपनीय दस्तावेज़ों से पता चला है कि अमीर और शक्तिशाली लोग किस तरह टैक्स की चोरी करते हैं या उन तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे उन्हें कम टैक्स भरना पड़े. इससे पता चलता है कि मोस्सैक फोंसेका ने किस तरह अपने ग्राहकों के काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और कर चोरी में मदद की. लीक हुए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मोस्सैक फोंसेका ने किस तरह अपने ग्राहकों को अवैध धंधों की सीख दी और संरक्षण दिया. यह कंपनी पिछले 40 वर्षों से बेधड़क काम कर रही थी. मोस्सैक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेज़ 70 से ज़्यादा वर्तमान और पूर्व राष्ट्राध्यक्षों एवं तानाशाहों से जुड़े हैं. दस्तावेज़ों से पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ एवं हसन नवाज शरीफ और बेटी मरियम सफदर ने टैक्स हेवन माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में कम से कम चार कंपनियां खोलीं. इन कंपनियों ने लंदन में कम से कम छह बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी. शरीफ परिवार ने इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर डॉएचे बैंक से सात मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी क़रीब 70 करोड़ रुपये का लोन हासिल किया. इसके अलावा अन्य दो अपार्टमेंट्स खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने वित्तीय मदद की.

अफरातफरी और अव्यवस्था का महाकुम्भ | P-4

राजनीतिक मुद्दा बनने लगी शराबबंदी | P-5

आरोपी ने धमकाया तो क्लीन चिट दे दी | P-7

भ्रष्टाचार की उड़ान

पनामा से इटली

पृष्ठ 1 का शेष

आरबीआई नियमों का सहारा लेकर खोली गईं कंपनियां

पनामा लीक्स से सामने आए भारतीयों के कुल खातों में से 90 प्रतिशत आरबीआई की लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत खोले गए हैं. पनामा पेपर्स के ज़रिये सामने आए क़रीब 500 भारतीयों के विदेशी खातों में से क़रीब 90 प्रतिशत खाते नियमों के तहत सही पाए गए हैं. शुरुआती जांच में पाया गया है कि आशंका के विपरीत इस मामले में बड़े पैमाने पर वैसी गड़बड़ी नहीं है. पनामा पेपर्स से सामने आए ज़्यादातर विदेशी खातों के मामले में आरबीआई के नियमों का पालन किया गया है. आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि क़रीब 90 प्रतिशत खातों में आरबीआई की लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) का इस्तेमाल किया गया है. बाकी बचे जो खाते नियम विरुद्ध खोले गए हैं, उनकेखाता धारकों पर ही अब कार्रवाई की जाएगी. 2004 में लागू की गई एलआरएस स्कीम के तहत भारतीय नागरिक अपनी आय का वह हिस्सा विदेश भेज सकते हैं, जिस पर भारत में आयकर चुका दिया गया हो. इस पैसे से विदेशों में खाते खोले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है और साथ ही विदेशी शेयर बाज़ारों में निवेश किया जा सकता है. हालांकि, इस स्कीम के तहत विदेशों में धन भेजने की कुछ सीमा भी है. 2004 में जब यह स्कीम शुरू की गई थी, तब एक वित्तीय वर्ष में केवल 25 हज़ार डॉलर यानी 15 लाख रुपये ही बाहर ले जाए जा सकते थे. अब इसे बढ़ाकर दो लाख पचास हज़ार डॉलर यानी 1.63 करोड़ रुपये किया जा चुका है. इससे पहले पनामा लीक्स पर हो रहे बवाल के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हुए कहा था कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए. उनका कहना था कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि विदेश में खाते खोलने की वाजिब वजह भी होती है और ये नियमों के तहत खोले जा सकते हैं. पनामा लीक्स मामले में सरकार द्वारा बनाई गई जांच टीम में आरबीआई भी शामिल है. वहीं उन लोगों पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत मिले हैं, जिन्होंने देश में काला धन क़ानून लागू होने से पहले वन टाइम एमनेस्टी स्कीम के तहत विदेशों में रखी अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा नहीं किया था. पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर तक चली इस योजना में भारत सरकार ने लोगों को विदेशों में रखी अपनी अघोषित संपत्ति घोषित करने का मौक़ा दिया था. इस योजना के ज़रिये लोग अपनी अघोषित संपत्तियों पर 30 प्रतिशत टैक्स और 30 प्रतिशत पेनल्टी देकर सजा से बच सकते थे. सरकार ने यह भी कहा था कि जो लोग इस योजना के तहत अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा नहीं करेंगे, उन्हें काला धन क़ानून के तहत अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है.

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

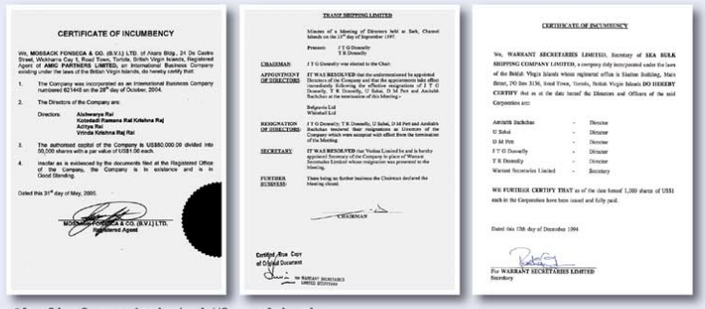

We, MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD. of Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Registered Agent of AMIC PARTNERS LIMITED, an International Business Company existing under the laws of the British Virgin Islands, do hereby certify that:

1. The Company was incorporated as an International Business Company numbered 621448 on the 28th day of October, 2004.
2. The Directors of the Company are:
   Directors: Aishwarya Rai, Kotedadi Ramana Rai Krishna Raj, Aditya Rai, Vrinda Krishna Raj Rai
3. The authorised capital of the Company is US$50,000.00 divided into 50,000 shares with a par value of US$1.00 each.
4. Insofar as is evidenced by the documents filed at the Registered Office of the Company, the Company is in existence and is in Good Standing.

Dated this 31st day of May, 2005.

MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent

TRAMP SHIPPING LIMITED

Minutes of a Meeting of Directors held at Sark, Channel Islands on the 13th day of September 1997.

Present: J T G Donnelly, T R Donnelly

CHAIRMAN: J T G Donnelly was elected to the Chair.

APPOINTMENT OF DIRECTORS: IT WAS RESOLVED that the undermentioned be appointed Directors of the Company and that the appointments take effect immediately following the effective resignations of J T G Donnelly, T R Donnelly, U Sahai, D M Pett and Amitabh Bachchan at the termination of this Meeting:-

Belgravia Ltd
Whitehall Ltd

RESIGNATION OF DIRECTORS: J T G Donnelly, T R Donnelly, U Sahai, D M Pett and Amitabh Bachchan tendered their resignations as Directors of the Company which were accepted with effect from the termination of the Meeting.

SECRETARY: IT WAS RESOLVED that Vestina Limited be and is hereby appointed Secretary of the Company in place of Warrant Secretaries Limited whose resignation was presented to the Meeting.

FURTHER BUSINESS: There being no further business the Chairman declared the Meeting closed.

CHAIRMAN

Certified True Copy of Original Document

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, WARRANT SECRETARIES LIMITED, Secretary of SEA BULK SHIPPING COMPANY LIMITED, a company duly incorporated under the laws of the British Virgin Islands whose registered office is Skelton Building, Main Street, PO Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands DO HEREBY CERTIFY that as at the date hereof the Directors and Officers of the said Corporation are:

Amitabh Bachchan	-	Director
U Sahai	-	Director
D M Pett	-	Director
J T G Donnelly	-	Director
T R Donnelly	-	Director
Warrant Secretaries Limited	-	Secretary

WE FURTHER CERTIFY THAT as of the date hereof 1,000 shares of US$1 each in the Corporation have been issued and fully paid.

Dated this 12th day of December 1994

For WARRANT SECRETARIES LIMITED
Secretary

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय से संबंधित पनामा लीक के दस्तावेज.

सार्वजनिक होंगे पनामा लीक्स के दस्तावेज़

दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा करने वाले पनामा लीक्स से जुड़े दस्तावेज़ों के भंडार को नौ मई को सार्वजनिक किए जाने की संभावना है. इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने कहा है कि डाटाबेस में हॉन्गकॉन्ग से लेकर अमेरिका के नेवाडा तक 21 कर पनाहगाहों (टैक्स हेवन) में स्थित 2,00,000 गोपनीय कंपनियों, न्यासों और फाउंडेशनों के बारे में सूचना है. अप्रैल की शुरुआत में क़रीब 100 मीडिया संगठनों के माध्यम से आईसीआईजे कोर्डिनेटेड लिमिटेड द्वारा पनामा कागजातों को जारी किए जाने से दुनिया भर का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद कई देशों में जांच बैठाई गई और आइसलैंड के प्रधानमंत्री और स्पेन के मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा. पनामा की विधि कंपनी मोस्सैक फोंसेका के लीक हुए 1.15 करोड़ दस्तावेज़ों से कर चुराने के लिए विदेशी कंपनियों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का खुलासा होता है.

हैलो, मैं जॉन डो बोल रहा हूं!

पनामा-लीक्स का मामला इस संदेश के साथ शुरू होता है कि हैलो, मैं जॉन डो बोल रहा हूं. पनामा पेपर्स ने जर्मन अख़बार ज़्युइडडोएचे-त्साइटुंग के दो युवा पत्रकारों को दुनिया में मशहूर कर दिया. दक्षिणी जर्मनी में म्यूनिख से प्रकाशित होने वाला यह दैनिक जर्मनी के सबसे बड़े अख़बारों में से एक है. 38 वर्षीय बास्टियान ओबरमायर और 32 वर्षीय फ्रेडरिक ओबरमायर का नाम भाइयों जैसा है, लेकिन वे भाई नहीं, बल्कि सहकर्मी हैं. तीन अप्रैल 2016 को 76 देशों के 109 अख़बारों, टेलीविज़न चैनलों और ऑनलाइन मीडिया में पनामा पेपर्स का एक साथ प्रकाशन शुरू होने से पहले वर्ष भर की छानबीन और तैयारियों पर उक्त दोनों पत्रकारों ने मिलकर एक किताब भी लिखी है. 350 पृष्ठों की इस किताब के जर्मन नाम का हिंदी मतलब है, एक विश्वव्यापी भंडाफोड़ की कहानी. अपने काम वाले कमरे को दोनों पत्रकार वार रूम कहते हैं. इसी वार रूम में वर्तमान एवं पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों सहित विश्व के143 देशों केनेताओं, 50 अरबपति धनकुबेरों, सैकड़ों बड़े-बड़े मैनेजरों, कई नामी खिलाड़ियों, अभिनेताओं, कलाकारों, तस्करों, माफियाओं और कारोबारी बैंकों की पोल खोलने की भूमिका तैयार हुई. उल्लेखनीय है कि अमेरिका में 1941 में बनी जॉन डू नामक एक फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई थी. तभी से अपने आपको गुमनाम रखकर खुफिया कामों में लगे अमेरिकी लोग अपना परिचय अक्सर इसी नाम से देते हैं. दोनों पत्रकारों को 21 देशों में चल रही 2,14,000 फर्जी फर्मों की पोल खोलने वाले एक करोड़ 15 लाख दस्तावेज़ मुफ्त में सौंपने वाले कौन लोग थे, इस बारे में वे कुछ नहीं बताते. बास्टियान ओबरमायर का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिस अज्ञात स्रोत ने संदेश भेजा था, वह न सिर्फ़ बदले में एक पैसा तक नहीं लेगा, बल्कि तरह-तरह की ऐसी असाधारण जानकारियों का अंबार लगा देगा कि दुनिया में भूकंप आ जाएगा. उन्होंने यह कतई नहीं सोचा था कि वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो देखते ही देखते उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर देगा. बास्टियान और फ्रेडरिक ने वॉशिंगटन स्थित खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स-आईसीआईजे) से संपर्क किया. आईसीआईजे 65 देशों के लगभग 200 पत्रकारों का एक ऐसा नेटवर्क है, जो खोजी पत्रकारिता के सामूहिक हित में 1997 में बना था. ■

जर्मन अख़बार ज़्युइडडोएचे-त्साइटुंग के युवा पत्रकार बास्टियान ओबरमायर और फ्रेडरिक ओबरमायर.

कर चोरों का स्वर्ग

केमन द्वीप समूह : यह द्वीप समूह विश्व की कुल बैंकिंग संपदा के मद्देनज़र 15वें स्थान पर आता है और बड़ी हस्तियों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कर चोरी का क़ानूनी रास्ता मुहैया कराता है.

स्विट्ज़रलैंड : यह देश लंबे समय से काले धन के लिए गोपनीय बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया के काले धन का भंडार बन गया है. भारत का भी अकूत धन स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा है, लेकिन भारत की सरकारें उसे निकालने में नहीं, बल्कि केवल चुनावी मुद्दा बनाने में दिलचस्पी लेती रहती हैं.

जर्सी : इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित यह द्वीप अपने न्यूनतम कर ढांचे के कारण ब्रिटेन और अमेरिका के कर चोरों के बीच खासा लोकप्रिय है. यहां कॉरपोरेट कर, उत्तराधिकार कर और कैपिटल गेन जैसे टैक्स लगभग शून्य हैं.

आयरलैंड : कर चोरी के लिए आयरलैंड का नाम तब चर्चा में आया, जब अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों जैसे फाइज़र और एप्पल ने आयरलैंड की कंपनियों के साथ साझेदारी की और इस तरह वे सैकड़ों बिलियन डॉलर का कर बचाने में सफल हो गईं.

मोनाको : छोटा-सा देश मोनाको अपने कर क़ानूनों के कारण अकूत संपदा से भर गया है. वहां के कर क़ानून केमुताबिक, यदि आप वहां के रहने वाले हैं, तो अपना सारा धन अपने पास रख सकते हैं और इसी क़ानून ने कुछ हज़ार की नागरिकता वाले इस देश को आर्थिक महाशक्ति बना दिया है. मोनाको दुनिया का सबसे महंगा रीयल स्टेट बाज़ार है.

बरमूडा : इसके लचीले कर क़ानूनों के चलते 2014 के आंकड़ों के मुताबिक, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से एक चौथाई ने वहां अपनी सहायक कंपनियां खोलकर कर चोरी का साधन खोज रखा है.

मॉरिशस : हिंद महासागर का यह छोटा-सा देश द्विकर संधि द्वारा कॉरपोरेट कर में छूट, कैपिटल गेन और ब्याज को कर से बाहर रखने के कारण पूरी दुनिया के कर चोरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

बहामास : कैपिटल गेन टैक्स, उत्तराधिकार टैक्स, व्यक्तिगत आयकर और उपहार कर में छूट के कारण बहामास कर बचाने का एक बढ़िया स्रोत बना हुआ है. बड़ी संख्या में बड़ी आयु के लोग, जिनके पास अकूत संपत्ति है, यहां निवेश करके अपना आलीशान रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं.

आईल ऑफ़ मैन : बहुत कम करों के कारण इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच स्थित यह द्वीप समूह काले धन के एक जाने-माने गढ़ के रूप में विकसित हो गया है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 10
09 मई-15 मई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील में भारी–भरकम कमीशनखोरी की पुष्टि

भारत टटोलता रह गया इटली ने मुहर लगा दी

दीनबंधु कबीर

अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील में कमीशन खोरी के आरोप–प्रत्यारोप तो लगते रहे और उस पर सियासत भी होती रही, लेकिन भारत सरकार को जांच में कुछ ठोस सबूत हासिल नहीं हो पाए. भारतीय एजेंसियां अंधेरे में टटोलती रह गईं और इटली की अदालत ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में 125 करोड़ रुपये कमीशन के बतौर लिए गए थे. अदालत ने अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर कंपनी के मालिक उर्सी और कंपनी फिनमेक्कैनिका को घूस देने का दोषी करार दिया है. उर्सी को साढ़े चार वर्ष कैद की सजा भी सुनाई गई है. अगस्टा–वेस्टलैंड कंपनी ने वर्ष 2010 में भारत से 3,600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों का सौदा किया था. इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने माना है कि हेलिकॉप्टर डील में भ्रष्टाचार हुआ और इसमें भारतीय वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी शामिल थे. सरकार ने अब रोम स्थित भारतीय दूतावास से कोर्ट के फ़ैसले का पूरा ब्यौरा मांगा है. यह साबित हो गया है कि हेलिकॉप्टर डील में भारतीय अफसरों को 10 से 15 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई थी. इटली की अदालत के 225 पृष्ठों के फैसले में अलग से 17 पृष्ठ सिर्फ़ पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के बारे में हैं.

इटली की अदालत ने यह साबित कर दिया कि तीन वर्षों तक जिस घोटाले की भारत सरकार को भनक तक नहीं लगी, उस मामले के अहम किरदार आख़िर कौन–कौन लोग थे. अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील प्रकरण का पहला किरदार क्रिश्चियन मिशेल है. ब्रिटेन निवासी मिशेल हथियारों का एजेंट है और अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में बिचौलिया था. मिशेल फिलहाल फरार है. इस मामले में दूसरा अहम किरदार अगस्टा–वेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेक्कैनिका का पूर्व सीईओ जूसेप्पे उर्सी है. हेलिकॉप्टर डील में घूस देने के आरोप में उर्सी को साढ़े चार वर्ष कैद की सजा मिली है. तीसरा प्रमुख रोल ब्रूनो स्पैन्योलीनी का था. अगस्टा–वेस्टलैंड का पूर्व सीईओ ब्रूनो हेलिकॉप्टर डील मामले में ही गिरफ्तार हुआ था और उसे चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है. चौथे मुख्य किरदार तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं. फिनमेक्कैनिका के पूर्व सीईओ जूसेप्पे उर्सी ने अपने लोगों से कहा था कि वे इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो मोंटी या राजदूत टेरासियानो से संपर्क करें, जो उनकी तरफ़ से मनमोहन सिंह से सौदे के बारे में बात कर सकते हैं. इटली की अदालत में चली कार्यवाही में कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम प्रमुखता से आया. अदालत के फ़ैसले में चार जगह सोनिया गांधी के नाम का ज़िक्र है. क्रिश्चियन मिशेल ने अगस्टा–वेस्टलैंड को लिखी चिट्ठी में कहा है कि सोनिया गांधी ही नए हेलिकॉप्टर्स के पीछे असली ड्राइविंग फोर्स हैं. इस वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में छठवें महत्वपूर्ण किरदार के बतौर कांग्रेस नेता एवं सोनिया गांधी परिवार के वफादार अहमद पटेल का नाम आया है. इटली की अदालत में चली कार्यवाही में अहमद पटेल का नाम तीन बार आया है. सातवें किरदार के रूप में कांग्रेस नेता एवं सोनिया के करीबी ऑस्कर फर्नांडीज का नाम आया है.

दलाली में पूर्व कांग्रेसी मंत्री का भाई भी शामिल!

हेलिकॉप्टर डील घोटाले में पूर्व केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री संतोष बागरोडिया के भाई सतीश बागरोडिया का नाम भी आया है. सतीश बागरोडिया चंडीगढ़ की उस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं, जिसने अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील में रिश्वत देने के लिए पैसे लिए थे. सतीश बागरोडिया चंडीगढ़ की सॉफ्टवेयर कंपनी आईडीएस इंफोटेक के डायरेक्टर हैं. इटैलियन जांचकर्ताओं ने आईडीएस को अगस्टा–वेस्टलैंड से हुए सौदे में रिश्वत की रकम भारत पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार बताया है. आरोप है कि कंपनी ने फर्जी सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाकर इटली की कंपनी से भारत में पैसा मंगवाया था. इटैलियन जांचकर्ताओं का मानना है कि एक मार्च 2007 को दोनों फर्मों के बीच हुआ करार दलाली की रकम भारत पहुंचाने के लिए किया गया था.

हेलिकॉप्टर डील में बिचौलिया रहे गाइडो हेश्के ने इटली की अदालत में कहा कि ऑस्कर फर्नांडीज भी सौदे का हिस्सा थे. डील के तहत अगस्टा–वेस्टलैंड के तीन हेलिकॉप्टर भारत आ चुके थे, लेकिन विवाद के कारण तीनों हेलिकॉप्टर्स को इस्तेमाल में नहीं लाया गया.

उल्लेखनीय है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इटली की मशहूर कंपनी फिनमेक्कैनिका की सहयोगी ब्रिटिश कंपनी अगस्टा–वेस्टलैंड से यूपीए सरकार ने वर्ष 2010 में 12 हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था. दर्जन भर हेलिकॉप्टरों के बदले 3,600 करोड़ रुपये

देने का करार किया गया था. तीन हेलिकॉप्टरों की डिलीवरी भी हो गई, लेकिन आसमान में जाने से पहले ही उनकी उड़ान पर ब्रेक लग गया. 2013 में फिनमेक्कैनिका के सीईओ जूसेप्पे उर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर भारतीय वायुसेना से हेलिकॉप्टर सौदा तय करने के लिए घूस देने का आरोप था. इटली की पुलिस ने उर्सी की फोन बातचीत को टैप किया था, जिससे घूस कांड का खुलासा हुआ. अगस्टा–वेस्टलैंड के सीईओ ब्रूनो स्पैन्योलीनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. स्पैन्योलीनी की गिरफ्तारी के बाद यूपीए सरकार ने हेलिकॉप्टर खरीद पर रोक लगा दी और रक्षा मंत्री एके एंटनी ने जांच बैठा दी थी.

अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील में कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत पर इटली की अदालत द्वारा मुहर लगा देने से भारत में सियासत अचानक गर्मा गई है. लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राजपथ से लेकर जनपथ तक इस मामले पर बहसा–बहसी और गरमा–गरमी हो रही है. बात बहादुरी में माहिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो यहां तक बोल गए कि यूपीए सरकार ने ही अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, जबकि मोदी सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद कंपनी को प्रतिबंधित करने की औपचारिकता आगे बढ़ाई. इसी तरह राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी क्रिश्चियन मिशेल की लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए झेंप मिटाने की कोशिश की. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि वह आरोपों से नहीं डरतीं. सोनिया कहती हैं कि इस मामले में केवल झूठ बोला जा रहा है. अगर सरकार को सच्चाई सामने लानी होती, तो दो वर्षों में जांच पूरी कर ली गई होती. ■

...और इस तरह परवान चढ़ा हेलिकॉप्टर डील घोटाला

1. अगस्त 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एमआई–8 हेलिकॉप्टरों के पुराने होने के कारण नए हेलिकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा था.
2. मार्च 2002 में हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर डाला गया, ताकि नए वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदे जा सकें. इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल भारत की अति महत्वपूर्ण हस्तियों (वीवीआईपी) के लिए होना था.
3. 2004 में अटल बिहारी सरकार जाती रही. केंद्र में आई कांग्रेस–यूपीए सरकार ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद प्रक्रिया फिर शुरू की. इसी वर्ष यूपीए सरकार एक प्रावधान (इंटेग्रिटी क्लॉज) लागू करती है, जिसके मुताबिक, हर रक्षा सौदे से पहले क्लॉज पर साइन किया जाना ज़रूरी किया गया कि अगर डील के दौरान किसी बिचौलिए का इस्तेमाल हुआ, तो डील रद्द कर दी जाएगी. यही क्लॉज आगे जाकर यूपीए के फंसने की बड़ी वजह बना.
4. 2005 में शुरू हुई प्रक्रिया धीरे–धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन इसे वर्ष 2010 में तब हरी झंडी मिली, जब यूपीए कैबिनेट कमेटी ने 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव पास कर दिया.
5. प्रस्ताव पास होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने 2010 में इटली की हेलिकॉप्टर कंपनी अगस्टा–वेस्टलैंड से सौदा तय किया. अगस्टा–वेस्टलैंड ने यह ठेका अमेरिकी कंपनी सिकोर्सिकी एयरक्राफ्ट समेत कई कंपनियों को पछाड़ कर हासिल कर लिया.
6. फरवरी 2012 में इटली की जांच एजेंसियों ने कहा कि अगस्टा–वेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेक्कैनिका ने डील हासिल करने के लिए भारत के कुछ नेताओं और अफसरों को रिश्वत दी है. जांच अधिकारियों ने डील को अवैध बताया. डील कराने में तीन दलालों क्रिश्चियन मिशेल, गाइडो हेश्के और पीटर हुलैट के शामिल होने का पता चला. यानी निर्धारित प्रावधान के मुताबिक प्रथम दृष्टया ही डील ग़लत साबित हुई. हालांकि, बिचौलिया गाइडो हेश्के ने घोटाले से जुड़ी सभी सूचनाएं और तथ्य अपने कंप्यूटर से मिटा दिए थे, लेकिन जांचकर्ताओं ने उसके हार्डडिस्क से उन सभी जानकारियों को हासिल कर लिया. साथ ही उसकी मां के घर में छुपाए गए कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी बरामद किए थे. जांचकर्ताओं ने उसके कंप्यूटर ड्राइव में मिले दस्तावेज़ों को भानुमती का पिटारा करार दिया था. इसमें गाइडो हेश्के ने इटली एवं लुगानो में भारतीय मध्यस्थों से मुलाकात और फिनमेक्कैनिका सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लेन–देन का विस्तृत ब्यौरा भी दर्ज कर रखा था.
7. इटली की अदालत में 2012 में केस हुआ.
8. फरवरी 2013 में फिनमेक्कैनिका के सीईओ ब्रूनो स्पैन्योलीनी को इटली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कंपनी पर आरोप लगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए क़रीब 375 करोड़ रुपये रिश्वत में दिए.
9. आगे की जांच में पता चला कि कंपनी और भारत सरकार के बीच सौदा कराने के लिए दलालों ने कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल किए, जो भारत के राजनीतिज्ञों, अफसरों, रिश्तेदारों और दलालों को परिलक्षित करते थे.
10. 2013 में इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई. सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की. पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 12 लोगों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई. लेकिन, सीबीआई की जांच काफी धीमी रफ्तार से चलती रही.
11. जनवरी 2014 में यूपीए–2 सरकार ने अगस्टा– वेस्टलैंड के साथ सौदा रद्द कर दिया.
12. अक्टूबर 2014 में इटली में गिरफ्तार फिनमेक्कैनिका के सीईओ ब्रूनो स्पैन्योलीनी को बरी कर दिया गया. कहा गया कि डील में हुई रिश्वतबाजी प्रकरण में ब्रूनो निर्दोष हैं.
13. अप्रैल 2016 में इटली की मिलान अदालत ने निचली अदालत के फ़ैसले को रद्द कर दिया. मिलान अदालत ने फिनमेक्कैनिका के सीईओ स्पैन्योलीनी को दोषी माना. अगस्टा–वेस्टलैंड के पूर्व प्रमुख को भी दोषी माना गया.
14. अप्रैल 2016 में इटली की मिलान अदालत से इस प्रकरण में आख़िरी फैसला आया, जिसने अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील की पूरी अंतर्कथा को उजागर करके रख दिया. ■

वायुसेना की पीठ में छुरा भोंका था त्यागी ने

अगस्टा–वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले में इटली की अदालत ने अपने फ़ैसले में यह माना है कि डील में हुए भ्रष्टाचार में भारत के तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी शामिल थे. वायुसेना प्रमुख रहते हुए त्यागी ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की अधिकतम फ्लाइंग हाइट 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 मीटर करने की मंज़ूरी दे दी थी. फ्लाइंग हाइट कम करने की वजह से ही अगस्टा–वेस्टलैंड को कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन यह मंज़ूरी सुरक्षा मानकों के मुताबिक ग़लत और ग़ैर क़ानूनी थी. अगर फ्लाइट की हाइट कम न की जाती, तो अगस्टा–वेस्टलैंड कंपनी बोली में शामिल ही नहीं हो पाती. भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय से लगातार मांग कर रही थी कि उसे ऐसे हेलिकॉप्टर दिए जाएं, जो सियाचिन जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाने में सक्षम हों और 6,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकें. परीक्षण में पाया गया कि अगस्टा के हेलिकॉप्टर 6,000 मीटर के बजाय सिर्फ़ 4,572 मीटर तक जा पा रहे थे. बिचौलियों ने 6,000 मीटर तक उड़ पाने में अक्षम पाए जाने के बावजूद वायुसेना प्रमुख को घूस देकर मंज़ूरी हासिल कर ली. त्यागी को वायुसेना की पीठ में छुरा भोंकते हुए न देर लगी और न शर्म आई. तकनीकी शर्तों में बदलाव के लिए अगस्टा–वेस्टलैंड ने विभिन्न स्तरों पर तीन करोड़ यूरो की घूस दी. आज यह रकम 225 करोड़ रुपये के क़रीब है. इटली की अदालत ने कहा कि इस सौदे के दौरान एक–डेढ़ करोड़ डॉलर का अवैध फंड केवल अफसरों तक पहुंचा. अदालत के 225 पृष्ठीय फैसले के 17 पृष्ठों में बताया गया है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी किस तरह घोटाले का हिस्सा रहे. अदालत ने कहा कि त्यागी के परिवार को घूस के पैसे कैश और वायर के ज़रिये दिए गए. इसमें त्यागी के तीन रिश्तेदार शामिल थे. हालांकि, इटली की अदालत ने त्यागी को पेशी के लिए इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि भारत में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा उनके ख़िलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जा रही थी. इटली की अदालत में यह साबित नहीं हुआ कि भारत में घूस किसे–किसे दी गई, लेकिन आरोप है कि घूस का अच्छा–खासा हिस्सा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के साथ उनके तीन रिश्तेदारों को दिया गया. शुरुआती जांच में आरोप लगा कि त्यागी के क़रीबी रिश्तेदार जूली, संदीप और डॉस्का के ज़रिये घूस दी गई. घूस की रकम सीधे न देकर दो कंपनियों आईडीएस ट्यूनीशिया और आईडीएस इंडिया के मार्फत दी गई. इटली की अदालत के उक्त ताज़ा फ़ैसले में त्यागी का नाम कई बार लिया गया है. फ़ैसले में आरोप लगाया गया है कि सौदे के लिए त्यागी परिवार को सीधे एक करोड़ पांच लाख यूरो यानी लगभग 80 करोड़ रुपये दिए गए थे. ■

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की कम आमद भी अलमबरदारों को कर रही चिंतित

अफरातफरी और अव्यवस्था का महाकुम्भ

सिंहस्थ की तैयारी के पूर्व यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पिछले सिंहस्थ की तरह इस सिंहस्थ में साधुओं और प्रशासन के बीच कोई न कोई टकराव होगा, वह स्थिति सिंहस्थ के कुछ ही दिनों बाद सामने आ गई और यह साफ हो गया कि प्रशासनिक अधिकारियों और साधुओं में व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी टकराव कायम है और इसको लेकर साधुओं में आक्रोश व्याप्त है. एक तरफ सरकार सिंहस्थ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा कर रही थी, उसका वह दावा भी कुछ ही दिनों में हवा हवाई साबित होता नज़र आ रहा है. जनता की बात तो छोड़िए, साधु-संतों के डेरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है.

सोरिन शर्मा

मध्य प्रदेश शासन ने उज्जैन में प्रारंभ हुए सिंहस्थ पर करोड़ों रुपये खर्च तो कर दिए, परंतु पहले शाही स्नान के दिन ही भारी निराशा हाथ लगी. कहां सरकार प्रचार कर रही थी कि करोड़ों लोग सिंहस्थ में पहुंचेंगे और कहां पहले शाही स्नान में आंकड़ा पांच लाख को भी नहीं छू सका. प्रशासन और सरकार ने अपनी पूरी ताकत उज्जैन में झोंक दी, परंतु फिर भी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद नहीं हो सकीं. साधुओं से लेकर आने वाले श्रद्धालुओं तक में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है. और तो और जिन दुकानदारों ने भारी भरकम रकम खर्च करके दुकानें लगाई हैं, उनके मन में भी भय व्याप्त हो गया है कि कहीं इस बार सारा मेला फ्लॉप न हो जाए.

सिंहस्थ प्रारंभ होने के पहले से ही उज्जैन में भारी अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन सरकार ने अपने प्रचार के दम पर उन्हें दबा दिया. जैसे ही कुम्भ शुरू हुआ, फिर से परतें खुलने लगीं. सरकार की तरफ से उज्जैन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी, इसके बाद भी वहां व्यवस्थाओं के नाम पर सबसे अधिक शौचालय ही शौचालय दिखाई दे रहे थे, उनमें भी पानी की आपूर्ति नगर निगम नहीं कर पा रहा था. सड़कें बनाने का दावा तो बहुत किया गया था, लेकिन कुछ पुलों को छोड़कर उज्जैन में कोई नई सड़क नहीं दिखाई दी. पुरानी सड़कों की ही लीपापोती कर दी गई और मेला क्षेत्र में मिट्टी डालकर सड़कें बना दी गईं, जिनमें शुरुआती दौर में ही कीचड़ होने लगा. पूरे मेला क्षेत्र में शौचालय और पुलिस कर्मियों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था. एक बार मेला घूमने वालों के कपड़ों पर धूल की परत चढ़ती दिखाई दी. शाम के बाद तो आधे रास्ते बंद कर दिए जाते, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में से अधिकांश बाहरी होने के कारण वहां आने वालों को रास्ता तक नहीं बता पा रहे थे. अधिकांश लोग पुलिस व्यवस्था से त्रस्त नज़र आ रहे थे. रामघाट क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों की मौज का स्थल अधिक बना हुआ था. साधुओं के लिए तो पूरा कुम्भ भरा है, लेकिन इसका सही आनंद प्रशासनिक अधिकारी और उनके परिजन व रिश्तेदार ही उठा रहे थे. सामान्य व्यक्ति को तो भटकना ही पड़ रहा था. कोई रामघाट में स्नान करना चाहता था तो उसे भूखी माता मंदिर क्षेत्र में भेज दिया जा रहा था. वीआईपी वाहनों के अलावा किसी को कोई सुविधा नहीं थी. प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी लाल बत्ती जलाकर सायरन बजाते हुए घूमने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे थे. उनके पास किसी समस्या का हल नहीं था. उनके जिम्मे शायद साधु-संतों के पंडालों में फीता काटने के अलावा जैसे कोई काम ही नहीं था. सुविधाओं या व्यवस्थाओं की बात करने पर वे अधिकारियों की ओर संकेत कर देते थे. साथ ही यह भी कहते सुने गए कि अब इतना बड़ा मेला है तो कुछ अव्यवस्थाएं तो होना स्वाभाविक है.

जैसा कि सिंहस्थ की तैयारी के पूर्व यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पिछले सिंहस्थ की तरह इस सिंहस्थ में साधुओं और प्रशासन के बीच कोई न कोई टकराव होगा, वह स्थिति सिंहस्थ के कुछ ही दिनों बाद सामने आ गई और यह साफ हो गया कि प्रशासनिक अधिकारियों और साधुओं में व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी टकराव कायम है और इसको लेकर साधुओं में आक्रोश व्याप्त है. एक तरफ सरकार सिंहस्थ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा कर रही थी, उसका वह दावा भी कुछ ही दिनों में हवा हवाई साबित होता नज़र आ रहा है. कहने को तो सरकार और प्रशासन ने सिंहस्थ की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश से बुलाए गए लगभग 25 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों और अफसरों की तैनाती कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा की स्थिति यह है कि जनता की बात तो छोड़िए, साधु-संतों के डेरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है. सिंहस्थ में जहां पुलिस सुरक्षा के नाम पर सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं चोर-लुटेरे भी साधुओं के डेरों से लूट और चोरी चपाटी करने में अपने हाथ की सफाई दिखा रहे हैं. सिंहस्थ के कुछ ही दिनों बाद सुरक्षा की जहां पोल खुली, वहीं पुलिस की सुरक्षा के नाम पर जो भय का वातावरण सिंहस्थ क्षेत्र में निर्मित किया गया उससे साधु-संतों में आक्रोश व्याप्त है. सिंहस्थ की सुरक्षा के लिए हजारों पुलिस जवान तैनात किए गए उसके बावजूद गत दिनों महंत विजयगिरि फौजी बाबा ने एक चोर को पकड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया. महंत वासुदेवानंद गिरि के डेरे से डेढ़ लाख रुपये और महंत रजनीशानंदगिरि के पंडाल से दो लाख रुपये की चोरी होने की घटनाएं घटित हुईं. वहीं महंत नरेन्द्र गिरि के यहां से साढ़े तीन लाख रुपये गायब होने की घटना बताई गई. चोरी की इन घटनाओं के साथ-साथ एक पंडाल में किसी ने जलता अखबार डाल दिया. आग बुझाने में वृंदावन के भरत गिरि के हाथ जल गए. कुल मिलाकर इन घटनाओं को देखते हुए यह साफ हो गया है कि सिंहस्थ में दिखावे के लिए पुलिस की भले ही व्यवस्था की गई हो, लेकिन यह स्पष्ट है. मेला क्षेत्र में चोर-लुटेरे और बदमाश सक्रिय हैं. सिंहस्थ प्रशासन ने पहले शाही स्नान के दौरान भारी भरकम पुलिस बल तैनात कर भय का वातावरण निर्मित किया था, जिसकी वजह से प्रथम शाही स्नान में दर्शनार्थी डुबकी नहीं लगा सके, इसको लेकर भी साधुओं में आक्रोश व्याप्त है. सवाल यह उठता है कि जब सिंहस्थ में आए साधु-संतों की सुरक्षा इतनी भारी भरकम पुलिस नहीं कर पा रही है तो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की क्या स्थिति होगी.

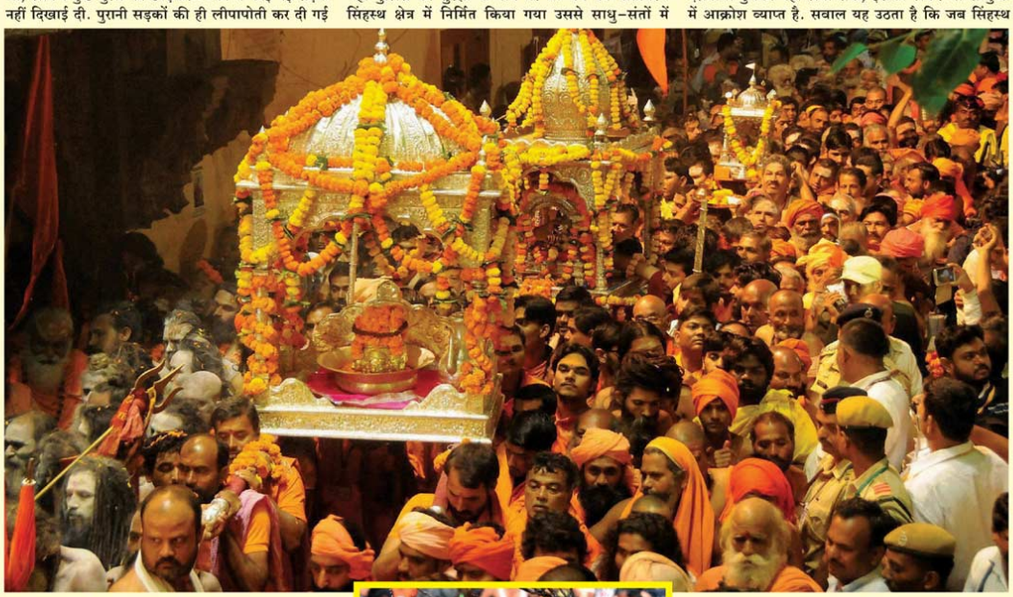

सिंहस्थ के कुम्भ मेले में चोरी-चकारी और गाड़ियों की तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से साधु-संत काफी नाराज़ हैं. साधुओं का गुस्सा इतने चरम पर पहुंच गया कि दत्त अखाड़ा क्षेत्र में उन्होंने चक्का जाम भी कर दिया और पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. साधुओं ने इस दौरान तलवार-भाले हवा में लहराए. जूना अखाड़े से जुड़े साधुओं के डेरे में शरारती तत्वों ने लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया. इसी दौरान एक साधु की कार पर गोली चलाई गई और प्रशासन इंकार करता रहा. सिंहस्थ के दौरान दत्त अखाड़ा स्थित गंगागिरि के आश्रम के संत तपस्वी गिरि पर एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया. घटना के बाद घायल संत को जिला अस्पताल लाया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें इन्दौर रेफर कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, भूखी माता मन्दिर के पास गुजरात के महेन्द्र गिरि का आश्रम है, वहां महेन्द्र गिरी के शिष्य तपस्वी गिरि पर अज्ञात आरोपी ने तलवार से वार कर दिया, पंडाल में तब चार-पांच सेवादार मौजूद थे, जबकि घटना के समय महेन्द्र गिरि पास के ही पंडाल में गए हुए थे, हमले के बाद तपस्वी को खून की उल्टी हुई, जब सेवादार वहां पहुंचे तो गिरि खून से लथपथ थे, गले में गंभीर चोट आ जाने की वजह से कुछ बोल नहीं सके, केवल इशारे में ही किसी मुंछ वाले का जिक्र उन्होंने किया. इस घटना से सवाल यह भी उठता है कि जब सिंहस्थ के अवसर पर उज्जैन में एक बड़ा अस्पताल तैयार किया गया और जिसको लेकर तमाम दावे किए गए तो जख्मी साधु को उपचार के लिए उज्जैन से इंदौर क्यों रैफर किया गया? सिंहस्थ के प्रचार को लेकर सरकार सबसे ज्यादा सक्रिय और सतर्क रही है, लेकिन सिंहस्थ की व्यवस्थाओं को लेकर एक समय ऐसा भी आया, जब पत्रकारों ने ही मीडिया सेंटर के बाहर धरना दे दिया. पहले तो जनसंपर्क विभाग से भोपाल के पत्रकार ही नाराज थे, क्योंकि सिंहस्थ के पास बनाने को लेकर कथित रूप से पक्षपात किया गया. इसके बाद उज्जैन में जो मीडिया सेंटर बनाया गया, वह किसके लिए था, यही समझ में नहीं आया. वहां मीडिया वालों को कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा था. सूचनाएं देने के लिए कोई अधिकारी हर समय उपस्थित नहीं रहता था. जो मीडियाकर्मी वहां पहुंचे, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तो पत्रकारों में गुस्सा बढ़ गया. अनेक पत्रकार मीडिया सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए. बाद में कुछ अधिकारियों ने समझा-बुझाकर उन्हें शांत किया. लेकिन अभी भी मीडिया के लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी नाराज़गी है. ■

हाईटेक सिंहस्थ का यह हाल!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल किस्म-किस्म के प्रतिमान स्थापित करने का काल रहा है. व्यापमं और डीमैट घोटाला इसी शासनकाल की देन हैं. भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का मामला हो या राज्य में अवैध कारोबारियों और अवैध उत्खनन करने वाले लोगों को संरक्षण देने का मामला, सबमें मध्य प्रदेश सरकार अग्रणी रही है. ठीक उसी तरह सिंहस्थ कुम्भ भी अराजक शासनिक-प्रशासनिक दुष्चक्र में फंस गया है. सिंहस्थ महाकुंभ मेला इस बार बिल्कुल नए कलेवर के साथ हाईटेक और ईको-फ्रेंडली व्यवस्था के रूप में प्रचारित होकर तो आया लेकिन वास्तविकता में वह कुछ और ही निकला. 22 अप्रैल को इसका शुभारंभ प्रथम शाही स्नान के साथ हुआ. पहले शाही स्नान में जितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही थी उससे बहुत कम संख्या में लोग आए और पहला शाही स्नान श्रद्धालुओं और धर्मार्थियों की दृष्टि से पूरी तरह असफल रहा. इसके पीछे क्या कारण हैं यह सरकार और मेला प्रबंधन जाने, लेकिन सोच का विषय यह है कि जिस सिंहस्थ की तैयारी के लिए करोड़ों रुपये प्रचार-प्रसार में फूंक दिए गए, करोड़ों रुपये के स्थाई और अस्थाई निर्माण कार्य कराए गए, नभ से लेकर थल तक सिंहस्थ का प्रचार इस तरह किया गया कि मानो कोई भव्य कॉर्पोरेट आयोजन हो रहा हो, लेकिन समय आने पर सब फिस्स हो गया. इस प्रचार के पीछे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रणनीतिकारों की सिंहस्थ के बहाने शिवराज सिंह को नरेंद्र मोदी के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की परिकल्पना काम कर रही थी. प्रचार में तो शिवराज सरकार सफल रही, लेकिन आस्थाओं और परम्पराओं के अनुरूप एक धार्मिक आयोजन के रूप में सिंहस्थ आम लोगों को नहीं खींच पाया. अब भीड़ जुटाने का अलग से जतन किया जा रहा है. आयोजन में सरकार द्वारा जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया गया और जिस तरह के निर्माण कार्यों और व्यवस्था का सरकारी व्यौरा आया, उसने सिंहस्थ के भ्रष्टाचार के महाकुम्भ की तरफ भी इशारा किया. सरकार ने साधु-संतों को भी खुश करने या अव्यवस्थाओं की अनदेखी करने के लिए उन्हें उनके ओहदे के मुताबिक दान-दक्षिणा पहले ही दे दी. स्वाभाविक है यह दक्षिणा भी करोड़ों में ही होगी. ■

-अवधेश पुरोहित

feedback@chauthiduniya.com

बिहार के बाद देश के कई राज्यों में शराबबंदी को लेकर ताल ठोक रहे सियासतदान

राजनीतिक मुद्दा बनने लगी शराबबंदी

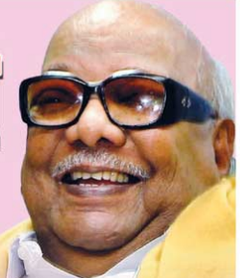

नवीन चौहान

जबसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है तबसे देश की राजनीति शराबबंदी से सराबोर हो गई है. शराबबंदी धीरे-धीरे सामाजिक से राजनीतिक मुद्दा बन गई है. नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से राज्य में शराबबंदी लागू करने का वादा किया था. जब उन्होंने शराबबंदी की बात कही तब कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक चोंचलेबाजी कहा था. कुछ ने तो उनकी इस घोषणा की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए थे. लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने एक अप्रैल से राज्य में शराबबंदी लागू कर दी, इसके बाद तो मानो पूरे देश में शराबबंदी का नशा चढ़ने लगा. देश के अलग-अलग हिस्सों में शराबबंदी की मांग होने लगी है. तमिलनाडु में भी यह चुनावी मुद्दा बन गया है.

शराबबंदी के मसले पर लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब विधानसभा चुनाव के दौर से गुजर रहे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कहा कि यदि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह राज्य में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करेंगी. उनकी इस घोषणा के बाद राज्य में सत्तारूढ़ एआईडीएमके और डीएमके के बीच रस्साकशी शुरू हो गई. डीएमके ने जयललिता पर उसके शराबबंदी के मुद्दे को चुराने का आरोप लगाया और उनके चरणबद्ध शराबबंदी के जवाब में पूर्ण शराबबंदी का वादा कर डाला. जयललिता ने कहा कि 1971 में डीएमके सरकार के शासनकाल में प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू हुई थी, इसलिए डीएमके को शराबबंदी के मसले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. गौरतलब है कि तमिलनाडु में 1937 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही पाबंदी लगा दी गई थी. आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को उस पाबंदी को बढ़ा दिया गया था. जयललिता अब चुनाव प्रचार के दौरान कह रही हैं कि शराब पर पाबंदी के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा. शुरुआत में शराब की दुकानों के खुलने के समय को कम किया जाएगा. इसके बाद उनकी संख्या में कमी की जाएगी. शराब छोड़ने वालों के लिए पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे. लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि तमिलनाडु सरकार को शराब की बिक्री से तकरीबन 21,800 करोड़ रुपये की आय होती है.

एक तरफ तो जयललिता शराबबंदी के खिलाफ भाषण दे रही हैं वहीं दूसरी तरफ बीते एक अप्रैल को शराबबंदी के लिए काम कर रहे संगठन मक्कल अधिकारम के छह लोगों को तिरुचिरापल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया गया. ऐसी ही एक घटना में पिछले साल अक्टूबर में जयललिता ने एक लोक गायक कोवन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था. कोवन अपने गानों में शराबबंदी का समर्थन करते हैं. जयललिता के इस निर्णय को लेकर उनकी बहुत आलोचना हुई थी और सवाल उठे थे कि एक लोक गायक जो शराबबंदी के खिलाफ गीत गाकर अभियान चलाता हो वह देशद्रोही कैसे हो गया? उसने लोगों को अपने गीतों से सरकार के खिलाफ उकसाया. शराबबंदी को लेकर ये जयललिता के दोहरे मापदंड हैं. लेकिन बिहार की शराबबंदी का असर तमिलनाडु में दिखना महत्वपूर्ण है. शराबबंदी के चुनावी मुद्दा बनने का सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि देश के हर हिस्से में लोग इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं. शराबबंदी के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, शराब का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, शराब की वजह से घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, शराबबंदी के कारण घटिया या कच्ची शराब का सेवन बढ़ता है जिसकी वजह से हर साल हजारों मौतें होती हैं, शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से सैक़ड़ों दुर्घटनाएं होती हैं और हज़ारों लोग इन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, वगैरह-वगैरह. वहीं शराबबंदी के विरोध में तर्क दिए जाते हैं कि खाने-पीने पर रोक नहीं होनी चाहिए. अब तक किसी भी राज्य, देश में शराबबंदी कारगर नहीं रही है. पाबंदी की वजह से तस्करी के जरिए शराब आती है और नकली शराब के आने का खतरा बढ़ जाता है. शराबबंदी की वजह से नशे के आदी लोग नशे के दूसरे विकल्पों की तलाश करते हैं जो शराब से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं. हालांकि देश में गांजा, अफीम, चरस और अन्य ड्रग्स पर प्रतिबंध है. लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को नशे की ये वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं. ऐसे में शराबबंदी का मुद्दा कितना प्रभावशाली होगा इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता.

शराबबंदी के मसले पर लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब विधानसभा चुनाव के दौर से गुजर रहे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कहा कि यदि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह राज्य में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करेंगी. उनकी इस घोषणा के बाद राज्य में सत्तारूढ़ एआईडीएमके और डीएमके के बीच रस्साकशी शुरू हो गई. डीएमके ने जयललिता पर उसके शराबबंदी के मुद्दे को चुराने का आरोप लगाया और उनके चरणबद्ध शराबबंदी के जवाब में पूर्ण शराबबंदी का वादा कर डाला.

साल 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब को देश का सबसे अधिक नशा प्रभावित राज्य माना जाता है. हाल ही में हुए पठानकोट आतंकवादी हमले का ड्रग्स की तस्करी का एंगल भी सामने आया था. पंजाब की राजनीति में नशा बहुत अहम मुद्दा है. पंजाब का अमीर व्यक्ति हो या गरीब, आम हो या खास. वहां का हर परिवार युवाओं की नशे की लत से परेशान है. नशे की आदत का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है. पंजाब भले ही देश के समृद्ध राज्यों में शुमार हो लेकिन वहां की युवा पीढ़ी नशे की लत की वजह से खोखली होती जा रही है. पंजाब चुनाव में नशाबंदी केंद्रीय मुद्दा होने जा रहा है. इसकी झलक मुक्तसर के माघी मेले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं. मुक्तसर रैली में उन्होंने पंजाब की सत्ताधारी बीजेपी और अकाली सरकार के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि दोनों ही पार्टियां पंजाब को नशे के दलदल से बाहर नहीं आने देना चाहती हैं. मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के करीबी रिश्तेदार विक्रम मजीठिया की ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हो चुकी है. ऐसे में पंजाब में बिहार की शराबबंदी का असर दिखने वाला है. हो सकता है कि पंजाब चुनावों में नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई दें. नीतीश कुमार पहले से ही भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं. फिलहाल और आने वाले वक्त में जिन राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं उनमें केवल पंजाब में एनडीए की सरकार है. इससे पहले दिल्ली और बिहार में हुए चुनावों में भाजपा को पटखनी दे चुके अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की जोड़ी भाजपा को एक बार फिर पटखनी देने के लिए एक साथ दिखाई दे सकती है. नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करके अरविंद केजरीवाल ने नए राजनीतिक संकेत दे दिए थे. अब उस समीकरण को फलीभूत करने का समय आ रहा है. पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार की हार को सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की विफलता से जोड़ा जाएगा, जिसका सीधा फायदा मिशन-2019 में विपक्षी दलों को होगा. हालांकि, पंजाब में नशे का मुद्दा आम आदमी पार्टी के प्रमुख एजेंडे में है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं है, यह बात दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं.

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग नाकाम हो चुका है. बिहार में 1977 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, लेकिन यह प्रभावी नहीं हुई थी. इसके बाद फिर स्थिति जस की तस हो गई थी. गुजरात में 1960 से शराबबंदी लागू है. गुजरात में शराब के उत्पादन, बिक्री और पीने पर पाबंदी है. पाबंदी के बावजूद वहां शराब उपलब्ध हो जाती है. नगालैंड में 1989 से शराब पर रोक है, अखबार में शराब के विज्ञापन पर भी रोक है, लेकिन वहां भी शराब उपलब्ध है. आंध्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कह कर शराबबंदी खत्म कर दी थी कि इसे पूरी तरह लागू कर पाना संभव नहीं है. हरियाणा में बंसीलाल सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयावह हुए थे. शराबबंदी के इक्कीस महीनों में ही इससे जुड़े किस्सों की भयावहता और उपहास ने अपनी तमाम हदें लांघ दी थीं. इतिहास गवाह है कि जब शराबबंदी खत्म करने की घोषणा की गई तो जनमानस इतना हर्षित हुआ था, जितना शायद शराबबंदी लागू होने पर भी नहीं हुआ था. एक लंबे समय बाद बंसीलाल ने भी यही बात दोहराई कि यह संभव नहीं. हालांकि उन्होंने कभी कहा था, मैं शराब पर पाबंदी हटाने के बजाय घास काट लूंगा. इसी साल जनवरी में ओड़ीशा में शराब के उपभोग और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को वहां की सरकार ने अवास्तविक बताया. ओड़ीशा के आबकारी मंत्री दामोदर राउत ने विधानसभा में कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू करना यथार्थवादी कदम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यदि राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा भी देता है तो शराब पीने वालों का उससे लगाव खत्म करना असंभव है. उन्होंने कहा कि शराब पर प्रतिबंध से शराब का अवैध व्यापार बढ़ेगा. अवैध शराब पीने से लोगों के मरने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय लोगों के बीच उत्तम शराब की बिक्री और वितरण को नियमित करना उचित कदम होगा. राउत ने यह बात भी साफ की कि राज्य सरकार की शराब की बिक्री से राजस्व अर्जित करने की मंशा भी नहीं है. गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर तक ओड़ीशा सरकार ने शराब की बिक्री से 1139.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है.

शराबबंदी का एक और सामाजिक पहलू यह भी है कि शराबबंदी का प्रभाव पर्यटन उद्योग पर भी पड़ता है, जिससे राज्य के हजारों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं. हालांकि शराबबंदी में फाइव स्टार होटलों को शराब परोसने की छूट होती है, लेकिन इन पांच सितारा होटलों में बहुत कम पर्यटक जाते हैं. शराबबंदी की वजह से बेरोज़गारी में बढ़ोत्तरी होती है. शराबबंदी का पहला असर डिस्टिलरीज के बंद होने के तौर पर सामने आता है. इससे कई लोगों का रोजगार छिन जाता है. इसके अलावा ठेकों, अहातों, होटलों, रेस्तराओं और परिवहन से भी कई लोगों को रोज़गार मिलता है. शराबबंदी के कारण इनका रोजगार छिन जाता है. तात्कालिक परिस्थितियों में उनके पास रोजगार का कोई विकल्प शेष नहीं बचता है जिससे उनके घर-परिवार पर कोई फर्क न पड़े. ऐसे बेरोज़गार कई बार गलत राह भी अपना लेते हैं. इन सबका असर राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अपराध पर भी पड़ता है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो शराबबंदी का निर्णय एकीकृत रूप से अच्छा है लेकिन इससे जुड़े अन्य आयामों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. इससे जुड़े लोगों के लिए रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए. इसके अलावा सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ज्यादा राशि खर्च करनी चाहिए ताकि लोग शराब छोड़ने की वजह से हताहत न हों. लेकिन शराबबंदी की वजह से राज्यों को जो वित्तीय नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकारें कैसे करेंगी? क्या इसके लिए वे करों में इजाफा करेंगी या अन्य कोई कदम उठाएंगी, यह देखना बेहद रोचक होगा. ■

navinonline2003@gmail.com

शराब पर निर्भर राज्यों की अर्थव्यवस्था

भारत में शराबबंदी एक ऐसी कसरत है, जिसे शुरू करने के बाद हर राज्य सरकार का दम फूलने लगता है. शराब का कारोबार पूरे देश में डेढ़ लाख करोड़ रुपये सालाना का आंकड़ा पार कर चुका है. एसोचैम के अनुमान के अनुसार शराब के उद्योग में सालाना 30 फीसदी की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है. यह एक ऐसा उद्योग है जो इसके कारोबारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों, नेताओं, सरकारी सुरक्षा कर्मियों और चंद ठेकेदारों को मालामाल कर देता है. शराब के व्यापार से देश में सबसे अधिक पैसा तमिलनाडु सरकार कमा रही है. तमिलनाडु सरकार को शराब पर टैक्स से एक साल में 21,800 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है. कोई भी सरकार इस कमाई को कैसे छोड़ सकती है. हालांकि साल 2014 में केरल में शराबबंदी लागू कर दी गई, जबकि वहां सरकार की कमाई का 20 फीसदी हिस्सा शराब से आ रहा था. इससे सरकार की माली हालत तो निश्चित तौर पर खराब हुई है. कर्नाटक सरकार तो खुद शराब के थोक कारोबार में शामिल है वहां भी सरकार की कुल आय का 20 प्रतिशत हिस्सा शराब की बिक्री से आता है. साल 2015 के अंत तक मध्य प्रदेश सरकार की शराब बिक्री से होने वाली आय लगभग 8 करोड़ रुपये हो गई. मोटे तौर पर पिछले बारह सालों में मध्य प्रदेश में शराब की खपत में चार गुना और शराब से होने वाली आय में दस गुना की बढ़ोत्तरी हुई है. राजस्थान सरकार की आबकारी नीति-2015-16 में शराब से सरकार को 6,130 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है. वहीं साल 2016-17 में सरकार ने शराब से सात हजार करोड़ से भी ज्यादा आमदनी का लक्ष्य रखा है. सरकार की कमाई का आलम यह है कि शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आने वाले आवेदनों की फीस से ही पिछले साल छह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो गई थी. बंगाल में शराब की बिक्री के मद में राजस्व आय 1477.64 करोड़ रुपये है जो कि देश के दूसरे राज्यों के मुक़ाबले बेहद कम है. शराब पूरी तरह राज्यों का विषय है इसलिए इस पर अलग-अलग राज्य सरकारों की मनमर्जी चलती है. ■

नीतीश ने पार्टी की बागडोर संभाली, देश की कमान थामने की ओर बढ़ाया क़दम

मछली की आंख पर सधा है निशाना

फोटो-प्रभात पाण्डेय

सरोज सिंह

पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के हजारों पदाधिकारियों और नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने शरद यादव के हाथों से जदयू की कमान अपने हाथों में ले ली. मोटे तौर पर इसे महज एक औपचारिकता कहा गया लेकिन अपने भाषण में नीतीश कुमार ने जिन बातों का उल्लेख किया उससे साफ हो गया कि उनकी राजनीतिक लाइन में कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है और वह क्या और कैसे चाहते हैं, इसे उनके विरोधी और सहयोगी दोनों समझ लें. आगे शरद यादव की क्या भूमिका होगी इसे भी तय कर दिया गया और देश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों को यह संदेश दे दिया गया कि अब समय आ गया है कि जदयू को पूरे देश में मजबूत किया जाए और इसमें सभी की भूमिका अहम है. लगे हाथ शराबबंदी और संघमुक्त भारत का हथियार भी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लोगों को थमा दिया. कहा जाए तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू ने एक अध्याय का समापन किया और एक नए अध्याय का श्रीगणेश कर दिया. पार्टी ने अपने नायक और लक्ष्य को तय कर लिया है.

पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में नीतीश कुमार ने बहुत सारे भ्रम दूर करने के प्रयास किए. नीतीश कुमार ने कहा कि जो राजनीतिक पंडित यह समझ रहे हैं कि पीएम पद के लिए मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं तो वे गलत दिशा में अपना दिमाग लगा रहे हैं. देश का अगला पीएम कौन होगा यह वक्त और देश की जनता तय कर देगी. आप और हम दावा करने वाले कौन होते हैं. वैसे भी जो पीएम बनने का दावा करते हैं वे कभी पीएम नहीं बन पाते. नीतीश कुमार ने बातों को और साफ करते हुए कहा कि जब मैं संघमुक्त भारत और भाजपा की सोच का विरोध करने वाले दलों और नेताओं की एकजुटता की बात करता हूं तो मेरी मंशा केवल और केवल यह होती है कि 2019 के संग्राम में नरेंद्र मोदी की वापसी न होने पाए. मेरा पक्का मानना है कि अगर हम भाजपा विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाने में सफल रहे तो नरेंद्र मोदी की विदाई तय है. लेकिन जब मैं ऐसी बातों की पहल करता हूं तो मेरे जेहन में यह बात नहीं होती है कि मुझे ही सब लोग नेता मान लें. पहले सब लोग साथ आएं और भाजपा और संघ से देश के सामने जो खतरा पैदा हो गया है उसका मिलकर मुक़ाबला करें. कौन नेता होगा इसे बाद में देख लिया जाएगा. नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, सभी को त्याग करना होगा तब कोई तस्वीर बनेगी. बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन बनाया तो मैंने और लालू जी ने त्याग किया. अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग कभी भी भाजपा को नहीं रोक पाते. इस रणनीतिक सफलता को हम लोग पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं. अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि इस दिशा में मैं अपना प्रयास जारी रखूं.

> **नीतीश कुमार यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस अभियान का चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर सकता, चाहे समर्थक हों या विरोधी. दूसरी बात यह है कि इसी तरह के कुछ कार्यक्रमों को लेकर विपक्षी एकता के लिए माहौल बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार इसी पृष्ठभूमि में यूपी और झारखंड में बड़े आयोजन कर रहे हैं. साफ है कि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि उनको भी पता है कि एक छोटी सी चूक उनके पूरे अभियान को रसातल में पहुंचा देगी.**

नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह साफ कर दिया कि वह बिना किसी पद के लालच के एकता का प्रयास कर रहे हैं. गौरतलब है कि जैसे ही नीतीश कुमार ने संघमुक्त भारत का नारा दिया वैसे ही यह चर्चा गर्म हो गई कि 2019 में वे खुद को नरेंद्र मोदी के समानान्तर रखना चाहते हैं. लगे हाथों लालू प्रसाद और तारिक अनवर का भी समर्थन नीतीश कुमार को मिल गया. बहस तेज़ हो गई कि नीतीश ने पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी तेज़ कर दी और जल्द ही नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की राजनीतिक जंग का यह देश गवाह बनेगा. जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अभी से ही इस तरह की राजनीतिक लड़ाई के खतरे को पहचान लिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे और भाजपा विरोधी एकता बनाने में दिक्कत आएगी. यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने तो कहना भी शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए मुलायम से बेहतर चेहरा और कोई नहीं हो सकता. नीतीश कुमार को लगा कि अगर दूसरे नेताओं का भी विरोध शुरू हो गया तो उनकी मुहिम शुरू होने से पहले ही मर जाएगी. इसलिए उन्होंने दो टूक कहा, मैं पीएम की दौड़ में नहीं हूं और केवल विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी रणनीति से हमें सफलता मिल सकती है, जिसे बिहार में हमने साबित करके दिखा दिया है. इस मुद्दे पर सफाई देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वह शराबबंदी को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पूरे देश में छेड़ना चाहते हैं. बिहार के लोगों ने जिस तरह से इस अभियान को हाथों हाथ लिया है उससे साफ है कि देश भर में इसे सफलता मिलेगी.

नीतीश कुमार यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस अभियान का चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर सकता, चाहे समर्थक हों या विरोधी. दूसरी बात यह है कि इसी तरह के कुछ कार्यक्रमों को लेकर विपक्षी एकता के लिए माहौल बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार इसी पृष्ठभूमि में यूपी और झारखंड में बड़े आयोजन कर रहे हैं. साफ है कि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि उनको भी पता है कि एक छोटी सी चूक उनके पूरे अभियान को रसातल में पहुंचा देगी. जहां तक बिहार में विपक्षी पार्टियों का सवाल है तो वे सभी अभी इंतजार करो और देखो की रणनीति पर काम कर रही हैं. इन पार्टियों की एकमात्र उम्मीद फिलहाल लालू प्रसाद ही हैं. विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि लालू और नीतीश का साथ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है. शराबबंदी का सारा श्रेय नीतीश कुमार को मिल रहा है. वोट बैंक के हिसाब से इससे राजद को कहीं कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा है. उल्टे इसमें राजद को राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ है, क्योंकि शराब के धंधे में ज्यादातर यादव बिरादरी के लोग ही हैं. भाजपा और उसके सहयोगी दलों को लगता है कि लालू प्रसाद मौके की तलाश में हैं. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि भाजपाई ख्याली पुलाव पकाते रहें, कहीं कुछ नहीं होगा. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं. दोनों नेताओं की बस यही इच्छा है कि गरीबों का भला हो और बिहार में तेज़ी से विकास हो. भाजपा के लोग सपने देखते रहें. उनको पता होना चाहिए कि वे 2019 में दिल्ली की सत्ता से भी बेदखल हो जाएंगे. नीरज कुमार का दावा है कि सूबे की सरकार पूरे पांच साल मजबूती से चलेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है. साफ है कि नीतीश कुमार का मिशन-2019 चालू है और इरादा भी साफ है. जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक लाइन तय की है उसी पर वह सारे देश में घूमेंगे और विपक्षी एकता का माहौल बनाएंगे. पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद इसमें तेजी आने की उम्मीद है.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड सरकार पर नाराज मूल निवासी, विपक्ष ने तेज़ किया आंदोलन

बाहरियों पर मेहरबानी से घिर रही भाजपा

प्रशांत शरण

झारखंड में स्थानीयता को लेकर वोटों की राजनीति तेज़ हो गई है. भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों एवं मूलवासियों का मोह भंग होता देख मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाहरियों को लुभाने के लिए ऐसी स्थानीय नीति बनाई, जिससे बाहरियों को कोई नुकसान न हो. एक तरह से मुख्यमंत्री दास बाहरियों पर कुछ ज्यादा मेहरबान हैं. 15 साल बाद घोषित स्थानीय नीति में 30 वर्षों से झारखंड में रहन वाले लोगों को स्थानीय माना गया है, पर बाहरी को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि जिसने कक्षा एक से 10वीं तक की पढ़ाई झारखंड में की हो, उसे भी स्थानीय माना जाएगा. भाजपा ने बाहरी लोगों के पक्ष में स्थानीय नीति लाकर लगभग 40 प्रतिशत मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी. राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से लगभग आधे पर हार-जीत में इन मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है.

भाजपा ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित सभी विपक्षी दलों ने इसे आदिवासी-मूलवासी विरोधी फैसला बताते हुए इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस फैसले के विरोध में 14 मई को झारखंड बंद बुलाया है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन चलाया जाएगा. वहीं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी भी इस मुद्दे को भुनाने में लग गए हैं. उन्होंने इसे आदिवासी मूलवासी विरोधी बताते हुए पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि खान से कोयले का उठान भी नहीं करने दिया जाएगा.

वैसे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री बाहरी पर मेहरबान हैं. लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री स्वयं बाहरी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इसलिए बाहरियों के साथ इनकी सहानुभूति कुछ ज्यादा ही है. मुख्यमंत्री दास ने जब सत्ता संभाली तो उन्हें झारखंड कैडर के आईएएस पर विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने बिहार के एक स्वजातीय आईएएस को आयात कर उन्हें अपना प्रधान सचिव बनाया. झारखंड में भाजपा बहुमत में रहने के बावजूद हमेशा सरकार गिरने के भय से सशंकित रहती है. मुख्यमंत्री रघुवर दास को हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि भाजपा का ही एक गुट, जिसका नेतृत्व एक स्थानीय आदिवासी नेता कर रहे हैं, कहीं उनकी सरकार को पटखनी न दे दे. अगर ऐसा हुआ तो रघुवर दास अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए किसी से हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे. अगर इसमें वे सफल नहीं हुए तो विधानसभा भंग कर चुनाव में जाना चाहेंगे. भविष्य की चुनावी रणनीति को देखते हुए ही इस तरह की स्थानीय नीति लाई गई है. इसका लाभ भाजपा उठा सकती है, क्योंकि यहां क्षेत्रीय दलों सहित कांग्रेस भी आदिवासी व मूलवासी की ही राजनीति करती रही है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहते हैं कि अभी तक की सभी सरकारें इस पर राजनीति ही करती रही हैं. वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा इसे मुद्दा बनाए रखकर आदिवासी एवं मूलवासियों को छलने का काम किया है. झारखंडवासियों को भाजपा ने एक तोहफा दिया है. दास ने कहा कि झारखंड के लोगों की यह बहुप्रतीक्षित मांग थी. उम्मीद है कि राज्य के विकास के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी. प्रदेश के इतिहास में यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा.

इधर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा है कि स्थानीय नीति के मसले पर सरकार ने झामुमो के सुझाव को दरकिनार कर दिया. सरकार प्रदेश की जनता को बांटने का काम कर रही है. नीति में कई ऐसी बातें हैं जिनसे आपस में ही मनमुटाव होगा. इस नीति से किसी का हित नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता तय होनी चाहिए थी. झामुमो की यह मांग थी और इससे ही यहां के आदिवासियों का हित सधने वाला था, लेकिन घोषित नीति से आदिवासियों का हक मारा जाएगा.

दरअसल आदिवासी व मूलवासी 1932 के सर्वे को आधार मानते हुए स्थानीय नीति की मांग कर रहे थे. 2002 में बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल नीति बनाई और 20 अप्रैल 2002 को मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद 8 अगस्त व 19 अगस्त को इसे कुछ संशोधित करते हुए संकल्प पत्र जारी कर इसमें सर्वे को आधार माना गया. कहा गया कि उसी को स्थानीय माना जाएगा जिसके अपने पूर्वज या पूर्वज के नाम पर ज़मीन या मकान हो. उसका सर्वे में रिकॉर्ड दर्ज हो. तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय व्यक्ति की बहाली की बात भी कही गई थी. इस नीति के लागू होने के बाद झारखंड में हिंसा का दौर शुरू हो गया. बाहरी-भीतरी एक-दूसरे के दुश्मन बन गए और हिंसा-प्रतिहिंसा का दौर आरंभ हो गया. बाबूलाल मरांडी ने इस नीति को लाकर झारखंड को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया था. स्थिति बिगड़ती देख झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के इस आदेश को 27 नवंबर 2002 को निरस्त कर दिया. तब से यह मामला विचाराधीन था. मरांडी सरकार गिरने के बाद से अब तक किसी भी सरकार ने काबिज कोई भी सरकार ने इसमें हाथ डालने का साहस नहीं किया. सभी दलों को यह पता था कि स्थानीय नीति के लागू होने से एक पक्ष का आक्रोश झेलना ही होगा.

ऐसे में, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस नीति को लाकर बाहरियों को एक प्रकार से तोहफा ही दे दिया है. नीति में 30 साल से झारखंड में रहने वाले को स्थानीय माना गया है. इसमें चालाकी से एक शब्द ऐसा जोड़ दिया गया है जिससे पूरा लाभ मिले. नीति में स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा एक से 10 तक स्थानीय स्कूल में पढ़े लोगों को भी स्थानीय माना जाएगा. चाहे उसके पास अपना मकान या ज़मीन हो या न हो. इससे बाहरी लोग भी नौकरी पाने के हकदार हो जाएंगे. वैसे यह भी कहा गया है कि शिड्यूल एरिया में 10 साल तक तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर जिले के स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी. राज्य के 13 आदिवासीबहुल क्षेत्र शिड्यूल एरिया में आते हैं. 10 साल बाद इन जिलों में बाहरी लोगों की नियुक्ति की राह प्रशस्त हो जाएगी. बहरहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इस स्थानीय नीति का क्या असर पड़ता है. वैसे, इस नीति से रघुवर दास ने बाहरियों का दिल जीतने का काम किया है. बाहरियों के मन में भय समाया हुआ था, बच्चों के भविष्य को लेकर वे चिंतित थे, सरकार के कदम से उनका भय खत्म हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

ये सब माने जाएंगे झारखंडी

- झारखंड की भौगोलिक सीमा में रहनेवाले वैसे सभी लोग, जिनका स्वयं या पूर्वजों का नाम गत सर्वे व खतियान में दर्ज हो. वैसे मूल निवासी जो भूमिहीन हैं. उनके संबंध में भी उनकी प्रचलित भाषा, संस्कृति व परंपरा के आधार पर ग्राम सभा की ओर से पहचान किए जाने पर वे स्थानीय कहलाएंगे.
- झारखंड के वैसे निवासी जो व्यापार को लेकर विगत 30 वर्षों या उससे अधिक समय से झारखंड में रह रहे हैं. चल-अचल संपति अर्जित की हो तो वे उनकी पत्नी या पति और उनकी संतानें झारखंडी मानी जाएंगी.
- झारखंड सरकार की ओर से संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/निगमों आदि के नियुक्त व कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी और उनकी पत्नी या पति और उनकी संतानें झारखंडी होंगी.
- झारखंड में कार्यरत भारत सरकार के पदाधिकारी व कर्मचारी और उनकी पत्नी या पति और उनकी संतानें झारखंडी होंगी.
- झारखंड में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियवुत व्यक्ति या उनकी पत्नी या पति और उनकी संतानें झारखंडी मानी जाएंगी.
- जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो या जिन्होंने मैट्रिक या समकक्ष स्तर की शिक्षा प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थान से पाई हो, उन्हें झारखंडी माना जाएगा.

शीर्ष अफसर के आदेश की भी यूपी में ऐसी-तैसी, भ्रष्टाचार की जांच ठेंगे पर

आरोपी ने धमकाया तो क्लीन चिट दे दी

मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग में अराजकता का यह हाल

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार में भारी अराजकता है. कोई किसी की नहीं सुनता. विभाग का शीर्ष अफसर कुछ आदेश करता है तो उसके ही मातहत अफसर कुछ और तानाबाना बुन देते हैं. करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ठंडे बस्ते में इसलिए चली जाती है क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोपी जांच करने वाले अधिकारी को खुलेआम धमकाता है और जांच अधिकारी डर के मारे बिना जांच किए ही क्लीन चिट जारी कर देता है. ऐसी अंधेरगर्दी की कुछ विचित्र बानगियां देखिए.

संजय अग्रवाल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं. संजय अग्रवाल उस विभाग के प्रमुख हैं, जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं. ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव होने के नाते संजय अग्रवाल बिजली महकमे के आठों निगमों के चेयरमैन भी हैं. अब समाजवादी पार्टी की सरकार में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता में संजय अग्रवाल जैसे शीर्ष अधिकारियों की सुनता कौन है! प्रमुख सचिव ने भ्रष्टाचार के दो गंभीर मामलों में उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया. यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक प्रमोद गोपाल राव खंडालकर को इस मामले की जांच करने को कहा गया. इसमें एक मामला जालौन जिले के कालपी और कोंच में 139 किलोवाट के दो विद्युत उपकेंद्रों और झांसी के दुनारा में 220 किलोवाट के एक विद्युत उपकेंद्र की स्थापना में करोड़ों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित था. इसमें यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में झांसी व आगरा में तैनात तत्कालीन अधिशासी अभियंता आरके सिंह मुख्य आरोपी हैं. भ्रष्टाचार के आरोपी आरके सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते सिंह की महकमे में खूब हनक है. दूसरा प्रकरण यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र बुनकर के भ्रष्टाचार के तीन दर्जन मामलों की जांच से सम्बन्धित हैं.

कालपी, कोंच और दुनारा में विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के क्रम में भीषण भ्रष्टाचार किए जाने की शासन को शिकायत मिली थी. विभागीय अराजकता का हाल यह पाया गया कि अधिशासी अभियंता आरके सिंह ने विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण की डिजाइन खुद ही तैयार कर ली और उसे शीर्ष अधिकारियों से पास कराए बगैर लागू भी कर दिया. जबकि बाद में उस डिजाइन में गंभीर तकनीकी त्रुटियां पाई गईं. उसके एक ही उदाहरण से आपको भयावह स्थिति का अंदाजा मिल जाएगा. आरके सिंह द्वारा बनाई गई डिजाइन पर कालपी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए बने पाइल फाउंडेशन (नींव निर्माण) की गहराई सात मीटर पाई गई जबकि कोंच के विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए पाइल फाउंडेशन (नींव निर्माण) की गहराई महज साढ़े तीन मीटर पाई गई. ऐसी अराजक अनियमितताओं के कई उदाहरण सामने आए और ऐसे अनापशनाप फैसलों पर भुगतान भी जारी होता रहा. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल के आदेश पर 18 नवम्बर 2014 को जांच शुरू हुई. यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक प्रमोद गोपाल राव खंडालकर ने जांच के क्रम में पाइल फाउंडेशन की गहराई की सटीक तकनीकि पड़ताल के लिए दिल्ली के विशेषज्ञ मनोज वर्मन को दो अप्रैल 2016 को बुक भी कर लिया. लेकिन नींव निर्माण की गहराई की जांच आखिरकार नहीं ही हो पाई. इस बीच ऐसा कुछ हो गया कि 12 अप्रैल 2016 को आरोपी आरके सिंह का पक्ष लेकर बिना जांच किए ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई. ऊर्जा महकमे के अधिकारी कहते मिलेंगे कि जांच अधिकारी खंडालकर को खुलेआम धमकियां दी गईं जिससे जांच रुक गई और जबरन क्लीन चिट देनी पड़ी. अब उन्हीं विभूति को ऊर्जा महकमे की किसी शाखा में निदेशक बनाने की भी तैयारी चल रही है.

ऐसा ही हश्र अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र बुनकर के भ्रष्टाचार के 36 मामलों की जांच का भी हुआ. जल विद्युत निगम और विद्युत उत्पादन निगम के साझे चीफ इंजीनियर एसके गोयल को बुनकर के भ्रष्टाचार का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना था, लेकिन उन्होंने इस निर्देश का पालन नहीं किया. गोयल से इस बारे में कोई पूछताछ भी नहीं की गई और खंडालकर ने बुनकर के भ्रष्टाचार की जांच को भी खड्डे में डाल दिया. बुनकर वही हैं जो विद्युत उत्पादन केंद्र माताटीला (ललितपुर) में आठ लाख 40 हजार पेड़ लगाने के घोटाले में नाम कमा चुके हैं. लाखों पेड़ कागज पर ही लगा दिए गए और सारे पेड़ कागज पर ही सूख भी गए. घोटाले की जांच भी सूख ही गई.

लब्बोलुबाब यह है कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा महकमा भ्रष्टाचार का केंद्र है. ऊर्जा महकमे के व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल कहते हैं कि अरबों रुपये के घोटालों की जांच की जब ऐसी-तैसी कर दी जाती है तो करोड़ों रुपये के घोटालों की औकात ही क्या है. अनपरा-उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन के विद्युत टावरों की पेंटिंग में हुए 50 अरब रुपये के घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश के बावजूद उस पर ग्रहण लगा दिया गया. अनपरा बिजलीघर से उत्पादित होने वाली बिजली को उन्नाव पारेषण उपकेन्द्र तक पहुंचाने के लिए बनाए गए टावरों की पाइलिंग और पेंटिंग में अरबों का घोटाला किया गया था. जायसवाल कहते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में घोटाले चरम पर हैं और बिजली की चोरी भी बेपनाह हो रही है, लेकिन राज्य सरकार इसे रोकने में अक्षम साबित हो रही है, क्योंकि सरकार से जुड़े नेता और नौकरशाह घोटालों में शामिल हैं. घोटालों के कारण ही प्रदेश की बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है.

घोटालों में जब सरकार ही शामिल हो!

घोटालों में जब सरकार ही शामिल हो तो कोई क्या कर लेगा? सरकार चाहे मायावती की रही हो या उसके बाद अखिलेश यादव की, किसी को घोटाला रोकने की नहीं बल्कि घोटालेबाजों को फायदा पहुंचाकर अपना हित साधने में अधिक रुचि रही है. तभी तो अखिलेश सरकार ने ऐसी कंपनी को लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका दे दिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था. चौथी दुनिया ने बीते दिनों यह खुलासा किया था कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं के ठेके लेने वाली कंपनी ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड के दो निदेशक उत्तर प्रदेश में खनन के गोरखधंधे से जुड़े हैं. कंपनी के दो निदेशकों में से एक बुंदेलखंड में खनन माफियाराज चलाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ा है, तो दूसरा समाजवादी पार्टी का नेता है और सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है. इन ताकतवर लोगों की कंपनी को ठेका पहले दे दिया गया, कंपनी बाद में अस्तित्व में आई. ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार सिंह और सीरज व्वज सिंह बांदा-बुंदेलखंड के खनन माफिया हैं. बाबू सिंह कुशवाहा का खनन साम्राज्य यही लोग चलाते हैं. सत्ता चाहे बसपा की हो या सपा की, चलती इन्हीं लोगों की है. बाबू सिंह कुशवाहा के खास सीरज व्वज सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सपा के टिकट पर वह बांदा से 2007 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. इस खबर का खुलासा होने के बावजूद सपा सरकार की खाल पर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई. ■

घोटालों का अंधेरा

यूपी पावर कॉरपोरेशन व इससे जुड़े दूसरे निगमों में बीते वर्षों में खरबों रुपये के बड़े-बड़े घोटाले हुए. घोटालों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआई से जांच कराने की मांग हुई, पर कुछ नहीं हुआ. अखिलेश सरकार के आने के पहले मायावती सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पांच हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. उसके पहले मुलायम सिंह सरकार के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1,600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. विद्युत नियामक आयोग की शह पर जेपी समूह समेत निजी बिजली घरानों को लाभ पहुंचाने में 30 हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया. इसी तरह राज्य जल विद्युत निगम में 750 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा तेलंगाना की वैरिगेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी को ठेका देकर हजारों करोड़ का घोटाला किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के खोदरी में जल विद्युत गृह बनवाने और उसका मालिकाना हक छोड़ने में कम से कम छह हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. लेकिन इनमें से किसी भी मामले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अगर निष्पक्ष जांच हुई होती तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर का घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ होता. जिसमें नेता, नौकरशाह, इंजीनियर, जज, सरकारी वकील एवं सीबीआई के अधिकारी सब लिप्त पाए जाते. घोटाले की जांच कराने के बजाय अदालत घोटाला उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल के खिलाफ़ ही अदालत की अवमानना का मामला चला रही है. जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला दे रखा है कि पांच हज़ार करोड़ के घोटाले की जांच के बाद ही अवमानना मामले पर सुनवाई की जाएगी. लेकिन, उस आदेश को ताक पर रखकर कार्यवाही चलाई जा रही है. घोटाला और उसकी लीपापोती करने में वे सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं जो प्रदेश की सत्ता में रही हैं. इसमें बहुजन समाज पार्टी सरकार और समाजवादी पार्टी सरकार की बराबर की मिलीभगत है. बसपा और सपा, दोनों ही जब-जब सत्ता में आती हैं, एक-दूसरे के घोटाले दबाने का काम करती हैं. विरोध-प्रतिरोध सब दिखावा है. बसपा सरकार के समय 30 हज़ार करोड़ रुपये का बिजली घोटाला हुआ था. उक्त घोटाले के दस्तावेजी प्रमाण लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा को दिए गए थे. लोकायुक्त ने उसे संज्ञान में भी लिया, लेकिन सत्ता के प्रभाव में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने पांच निजी पावर ट्रेडिंग कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया था. पावर कॉरपोरेशन ने उक्त कंपनियों से महंगी दर पर पांच हज़ार करोड़ यूनिट बिजली खरीदने का समझौता किया था. उस करार की शर्त थी कि सस्ती बिजली मिलने पर भी पावर कॉरपोरेशन कहीं और से बिजली नहीं खरीदेगा. इस खरीद से उत्तर प्रदेश को भीषण नुक़सान हुआ. इस तरह की विचित्र खरीद सपा सरकार में भी जारी है. बसपा सरकार से पहले सपा के शासनकाल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1,600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. उस समय भी केवल जांच ही चली, नतीजा कुछ नहीं निकला. सत्ता पर काबिज होने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती सरकार 25 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई है. लेकिन, उन्होंने इस घाटे की वजह जानने या उसकी औपचारिक जांच कराने की ज़रूरत नहीं समझी. यहां तक कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी को हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त होना पड़ा, फिर भी सरकार ने घोटाले को लेकर कोई क़ानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई. इसी तरह उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में भी 750 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, लेकिन उसमें लिप्त तत्कालीन सीएमडी आईएएस आलोक टंडन समेत अन्य अधिकारियों एवं अभियंताओं का कुछ नहीं बिगड़ा. सपा के मौजूदा शासनकाल में बिजली के बिलों में फर्जीवाड़ा करके हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का मामला भी सामने आया. घोटाले दर घोटाले जारी हैं. नेता दलीय सीमाएं लांघकर कमा रहे हैं और कमवा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दलितों को अपनी ओर लाने के लिए भाजपा कर रही सारे उपक्रम

बुद्धम् शरणम् गच्छामि

एसआर दारापुरी

दलितों को रिझाने के लिए भाजपा एक ओर डॉ. अम्बेडकर को अपनाने में लगी है तो अब वह भगवान बुद्ध की शरण में भी जाने का दिखावा कर रही है. इस सम्बन्ध में भाजपा ने हाल ही में सारनाथ से एक धम्म चक्र यात्रा निकाली, जिसे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई थी. इसमें एयर कंडीशंड बसें और इन्नोवा जैसी कारें लगाई गई हैं. इस यात्रा के मुखिया राज्यसभा के पूर्व सदस्य भंते डी. धम्मवीरियो हैं जो पूर्व में लालू प्रसाद यादव के साथ थे परन्तु अब सत्ताधारी पार्टी के साथ आ गए हैं. इस यात्रा में इनके साथ 70-80 भंते और भी हैं. यह यात्रा चार चरणों में उत्तर प्रदेश के लगभग 70 केंद्रों पर जाएगी और हर जगह पर दो दिन रुकेगी. इस यात्रा के मुख्य सूत्रधार मायावती के पूर्व नजदीकी रहे सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा हैं जो अब भाजपा में हैं.

वैसे तो भाजपा ने इसका असली राजनीतिक मकसद छुपाने के लिए इसे धम्म चक्र यात्रा का नाम दिया है परन्तु इसका असली काम उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच मोदी के अम्बेडकर और बौद्ध धर्म सम्बन्धी विचारों का प्रचार-प्रसार करना है. दरअसल यह भाजपा का दलित वोटरों में अपनी पैठ बनाने का ज़ोरदार प्रयास है. इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस यात्रा की मॉनीटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे की जा रही है. इस यात्रा में लगाई गई गाड़ियों पर मोदी के देसी तथा विदेशी बौद्ध स्थलों के दर्शन सम्बन्धी चित्र लगाए गए हैं. यात्रा के दौरान रुकने वाले प्रत्येक केंद्र को एक-एक टीवी सेट दान दिया जाएगा और वहां पर एक घंटे की सीडी

दिखाई जाएगी जिसमें मोदी के बौद्ध धर्म और अम्बेडकर सम्बन्धी विचारों का वीडियो दिखाया जाएगा. यह यात्रा 14 अक्टूबर को लखनऊ में समाप्त होगी.

इस यात्रा के बारे में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने अभियान के संयोजकों के साथ आठ बैठकें की थीं और यात्रा की मोदी ब्रांडिंग को उचित ठहराया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही संसद में डॉ. अम्बेडकर पर चर्चा का सुझाव दिया था और अम्बेडकर के नाम पर एक सिक्का भी जारी किया गया था. लिहाजा, जनता को यह बताना ज़रूरी है कि मोदी जी डॉ. अम्बेडकर का कितना सम्मान करते हैं. वैसे भाजपा के बुद्ध प्रेम का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि काफी वर्ष पहले जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लखनऊ के अम्बेडकर महासभा प्रांगण में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की थी कि बामियान (अफगानिस्तान) में तालिबान द्वारा ध्वस्त की गई बुद्ध प्रतिमा से भी ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन वहां पर आज तक एक पत्थर तक नहीं लगा. अब राजनाथ सिंह ने सारनाथ में पुनः घोषणा की है कि कुशीनगर में भी वैसी ही मूर्ति लगाई जाएगी.

लोगों का कहना है कि यदि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए ही सही बुद्ध का इस्तेमाल करना चाहती है तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य की पाली भाषा को अधिक से अधिक विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था करे और सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में पाली साहित्य के विषय को पुनर्स्थापित करे, जैसे स्मृति ईरानी आईआईटी संस्थानों में संस्कृत पढ़ाने की वकालत कर रही हैं. दूसरे, पूरे देश में बिखरी हुई बौद्ध धरोहर की देखभाल के लिए मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की तरह बौद्ध-धरोहर संरक्षण बोर्ड बनाने की मांग को स्वीकार करे. राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि भाजपा ने डॉ. अम्बेडकर के नाम पर दलित वोटरों को आकर्षित करने का फार्मूला दलित नेताओं मायावती, रामविलास पासवान, उदित राज, अठावले और प्रकाश अम्बेडकर आदि से सीखा है. इन नेताओं ने डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाओं और आदर्शों को नज़रअंदाज़ करके उसका इस्तेमाल केवल दलित वोट बैंक खींचने के लिए ही किया है. अब भाजपा, कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टियां भी वही कर रही हैं. दलित नेताओं ने अगर डॉ अम्बेडकर की शिक्षाओं और आदर्शों को ईमानदारी से अपनाया होता तो आज डॉ. अम्बेडकर केवल वोट बटोरने वाले पोस्टर ब्वॉय बन कर नहीं रह जाते. इन सभी नेताओं ने अब तक अम्बेडकर के नाम पर व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति ही की है और डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा को दफनाया है. ■ *(लेखक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं)*

feedback@chauthiduniya.com

कमल मोरारका

सरकार वित्तीय मामलों में समझदारी दिखाए

आशा की जा रही है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण प्रोडक्टिव होगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार इस सत्र में बैंकरप्सी (दिवालिया) बिल को लाने का प्रयास कर रही है, इसके साथ ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल को भी सदन से पास कराने की कोशिश सरकार करेगी. लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम अक्सर नई परिस्थितियां पैदा कर देता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. जब तक कांग्रेस सहयोग नहीं करेगी तब तक भाजपा के लिए राज्यसभा में बिल पास करवाना मुश्किल होगा या फिर जब तक वह कांग्रेस के अलावा अन्य दलों का समर्थन हासिल नहीं कर लेगी तब तक कोई भी बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो सकेगा. भाजपा को राज्यसभा में जीएसटी बिल को पास कराने में जरूर दिक्कत पेश आएगी लेकिन बैंकरप्सी सहित अन्य बिलों पर वह अन्य विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने में सफल हो सकती है.

मुख्य मुद्दा यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, उन्होंने अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे का मामला उठाया है, यह मामला कुछ दिनों पहले ही उजागर हुआ था और उस पर मीडिया में बहस भी हुई थी. अब इसमें नया बदलाव यह है कि इटली की एक अदालत ने इस मामले में फैसला दिया है कि इस वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में धांधली हुई है. अदालत ने अपने फैसले में कुछ लोगों के नाम लिए हैं जो हमें नहीं मालूम. 1986 में बोफोर्स सौदे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. सबसे पहले एक स्वीडिश रेडियो ने इस सौदे के बारे में खबर प्रसारित की थी. इसके बाद पता चला था कि उस डील में परदे की पीछे बहुत सारी सौदेबाजी हुई थी. आर्थिक अपराध और उसकी जांच का अपना अलग तरीका होता है. यह कहना कि इटली की अदालत ने ऐसा कहा है यह कहकर मामले को आसान करना है. भारतीय जांच और अदालत में सुनवाई का अलग तरीका है. बेशक सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करके आप इसका राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं और शायद यही काम सुब्रमण्यम स्वामी करना चाहते हैं.

उसी तरह से पनामा लीक के काग़जात हैं जिनमें बिजनेस और फिल्म जगत के जाने-माने लोगों के नाम सामने आए हैं. ये लोग हक़ीकत में बहुत दूर तक गए हैं क्योंकि पनामा एक ऐसी जगह है जहां किसी को जानकारी दिए बगैर कंपनी स्थापित की जा सकती है. इन दस्तावेजों से केवल कंपनी और उससे जुड़े लोगों के नाम जाहिर हुए हैं. उनमें कितना पैसा लगा है, उनका बैंक खाता कहां है, वहां पैसा किस तरह ले जाया गया, इसकी जांच काफी लंबे समय तक चलेगी. लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने के इस दौर में यह एक खेल की तरह है. जहां तक सरकार का सवाल है, उसे फिर से अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि क्या उसकी दूसरे देशों से पैसा वापस लाने में दिलचस्पी है. पहले तो इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि यह मामला जांच के लायक है भी या नहीं. मीडिया में जितनी बड़ी राशि की बात की जा रही है, यदि वाकई में भारतीयों का इतना धन विदेशों में है तो यह देश के हित में होगा कि वह पैसा वापस आए. मॉरीशस और दूसरे चैनलों से कुछ धन भारत में अवश्य आया होगा. क़ानूनी तौर पर या डरा-धमकाकर इस धन को वापस लाना संभव नहीं है. अगर आप वास्तव में इस पैसे को वापस लाना चाहते हैं तो आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें लोग खुद ही अपने पैसे वापस ले आएं. हर बिजनेसमैन यह जानता है कि यदि यहां उसे फायदा होगा तो वह अपने पैसे जरूर वापस लाएगा. ऐसे में आपको उन्हें प्रोत्साहन देना होगा जो कि बेशक एक बहस का विषय है कि ऐसा करके कहीं गलत लोगों को तो प्रोत्साहित तो नहीं किया जा रहा है?

उसी तरह एनपीए का मामला है. एनपीए का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. यानी कंपनियां बैंकों का ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं. इसका मतलब यह नहीं होता है कि पैसा डूब गया. बैंकों को इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि क्या उन्हें उन कंपनियों का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेना चाहिए या जो प्रमोटर्स हैं उन्हें उनके पैसे वापस दे दिए जाएं. विजय माल्या के मामले में बैंक यह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके विमान लीज़ पर थे, जिसमें बैंक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ जैसा बर्ताव किया जा रहा है वह ठीक नहीं है. अगर आप अपने ही लोगों के लिए इस तरह की अनिश्चितता का माहौल बनाएंगे, तो आप एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के आने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जबकि डॉ माल्या एक सांसद भी हैं. इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को पूरे माहौल की समीक्षा करनी चाहिए कि उनसे पैसे वापस लेने का सबसे बेहतर क्या विकल्प हो सकता है? मौजूदा परिस्थिति में विकल्प पिक एंड चूज (आपको जो अच्छा लग रहा है उसे चुनना) का है जिसे पश्चिम के लोग पसंद नहीं करते हैं, वे रूल ऑफ लॉ को पसंद करते हैं जो सबके ऊपर लागू होता है.

समाचार पत्रों में छपी खबरों के मुताबिक डॉ माल्या के ऊपर बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ है, लेकिन और भी लोग हैं जिन पर तीस हजार करोड़ रुपये बैंकों के बकाया हैं. आप ऊपर से शुरू करिए या नीचे से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहां हम अपनी पसंद के मुताबिक काम कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है यह सरकार ही बेहतर तरीके से जानती है. डॉ माल्या निश्चित रूप से सरकार के पसंदीदा लोगों की सूची से बाहर हो गए होंगे, इसलिए वह जाल में फंस गए. बिलकुल उसी तरह जिस तरह सहारा के सुब्रत रॉय के साथ हुआ जो कि एक अजीबो-गरीब मामला है. उन्हें यूपीए सरकार ने जेल में डाला लेकिन एनडीए सरकार ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वह सजायाफ्ता नहीं हैं, वह हमारी हिरासत में हैं. मुझे नहीं लगता है कि ये तरीके सही हैं. ऐसे में जब वामपंथी और मुझ जैसे समाजवादी यह समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर सही विकल्प है तो वे ठीक हैं, क्योंकि आपने उद्योग जगत को इतना बड़ा होने का मौका ही क्यों दिया? आपने इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का पैसा कर्ज के रूप में दिया लेकिन अब आपको मालूम नहीं है कि पैसे की उगाही कैसे की जाए. यह समझदारी का काम नहीं है. मैं यहां यह जरूर कहूंगा कि यूपीए और पी चिदंबरम ने कुछ मानकों का पालन जरूर किया, ऐसे मामलों में उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई. लेकिन यदि यह सरकार सोचती है कि वह कार्रवाई करके, डर फैलाकर या धमकाकर कि यदि आपने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. इससे कुछ हासिल नहीं होगा. भारत में हर किसी को मालूम है कि आयकर विभाग लोगों को वर्षों से डराता-धमकाता रहा है. इसका नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं. व्यवस्था तंत्र इस वजह से लगातार कमजोर होता गया और अब इस व्यवस्था तंत्र के आधार पर व्यापारी इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लेंगे. यह ऐसा मामला है जिसका कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें वित्त मंत्री, दूसरे संबंधित मंत्री और ऐसे लोग जिनके पास आर्थिक मामलों का अनुभव हो, जैसे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन आदि शामिल हों. इस बैठक में यह सवाल उठना चाहिए कि चूंकि हमने उदारीकरण, वित्तीय घाटा आदि के लिए अमेरिकी प्रणाली को अपनाया है तो अमेरिका ऐसी स्थिति का सामना किस तरह करता, इसकी मंत्रणा कर आपको भी वही तरीके अपनाना चाहिए.

2008 में अमेरिकी बैंक धराशाई हो गए थे. अमेरिकी सरकार ने उन्हें डूबने से बचाने के लिए अपना पैसा लगाया. यह सही है या गलत, यह दूसरी बात है लेकिन यही एक व्यवहारिक विकल्प है. सरकार को उन बैंकों की मीटिंग बुलानी चाहिए जिनका पैसा लगा हुआ है. बैंकर्स बहुत बुद्धिमान होते हैं. वह हर चीज से वाकिफ होते हैं कि पैसा कैसे वापस आएगा. वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 बैंकों को यह अधिकार देता है कि वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के संपत्ति अधिग्रहित कर सकते हैं. आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बेशक आप इसे उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि पैसा वापस लेने के लिए कर्जदारों के पास कोई संपत्ति ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपको उस पैसे को भूलना होगा. आप कानूनी तौर पर किसी को परेशान कर सकते हैं उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं जिल्लत के बारे में नहीं. वित्त मंत्री जितनी जल्दी इस मामले को सुलझा लें उतना ही बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाचार पत्रों में छपी खबरों के मुताबिक डॉ माल्या के ऊपर बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ है, लेकिन और भी लोग हैं जिन पर तीस हजार करोड़ रुपये बैंकों के बकाया हैं. आप ऊपर से शुरू करिए या नीचे से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहां हम अपनी पसंद के मुताबिक काम कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है यह सरकार ही बेहतर तरीके से जानती है. डॉ माल्या निश्चित रूप से सरकार के पसंदीदा लोगों की सूची से बाहर हो गए होंगे, इसलिए वह जाल में फंस गए, बिलकुल उसी तरह जिस तरह सहारा के सुब्रत रॉय के साथ हुआ जो कि एक अजीबो-गरीब मामला है. उन्हें यूपीए सरकार ने जेल में डाला लेकिन एनडीए सरकार ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वह सजायाफ्ता नहीं हैं, वह हमारी हिरासत में हैं. मुझे नहीं लगता है कि ये तरीके सही हैं.

पाठकों की दुनिया

सूखे की चपेट में देश

कवर स्टोरी-देश में पानी का भीषण संकट, सूखता भविष्य (25 अप्रैल-01 मई, 2016) ने काफी प्रभावित किया. देश के 12 राज्यों के लगभग 35 फ़ीसद ज़िले भयंकर सूखे की चपेट में हैं. लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया है. विडंबना यह कि मंत्री पद पर बैठा शख्स यह कहने से गुरेज नहीं करता कि क्या सूखा हमारे हाथ में है? जब भगवान की मर्जी होगी, तब बारिश होगी. लानत है, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर!

-राहुल चौहान, *भोपाल, मध्य प्रदेश*

* कवर स्टोरी-देश में पानी का भीषण संकट, सूखता भविष्य (25 अप्रैल-01 मई) ने झकझोर दिया. अगर हमें एक दिन पीने का पानी न मिले, तो हमारी हालत खराब हो जाती है, वहीं देश की एक बड़ी आबादी रोज इस समस्या से दो-चार हो रही है. सूखे की न तो राज्य सरकारों को चिंता है और न केंद्र सरकार को. केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का यह बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है कि क्या सूखा हमारे हाथ में है?

-विकास शर्मा, *पालम गांव, नई दिल्ली.*

* देश के कई राज्यों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है. नदियां, नहरें, तालाब एवं कुएं सूखे की मार झेल रहे हैं. लेकिन, सरकार और विपक्षी दल सिर्फ़ एक-दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं. जनता की चिंता किसी को नहीं है. राजनीतिक दलों को सिर्फ़ सत्ता पाने-हथियाने से मतलब रह गया है. सरकार और विपक्ष को मिलकर यह विचार करना चाहिए कि सूखे से कैसे निपटा जाए, लेकिन संसद में इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती.

-सुरेश यादव, *गोपालगंज, बिहार.*

सरकार चिंतित नहीं

जब तोप मुक़ाबिल हो-प्रधानमंत्री जी, अभी भी चेत जाने का वक्त है (25 अप्रैल-01 मई, 2016) के तहत संतोष भारतीय ने सही कहा कि आने वाले दिन या महीने देश के लोगों की जान पर आने वाले संकट के दिन होंगे. देश में सूखे के चलते हालात खराब हैं. लातूर में ट्रेन से पानी भेजा रहा है, लेकिन वह सिर्फ़ शहरी इलाकों के लोगों को मिल पा रहा है, ग्रामीण इलाकों में नहीं. ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं. लातूर में पानी ढोते-ढोते एक बच्चे की जान चली गई. बुंदेलखंड के लोगों की बात पढ़कर हैरानी हुई कि अगर इस बार बारिश न हुई, तो इलाके से गुज़रने वाली ट्रेनें लूटी जाएंगी. जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वह उसकी समस्याओं का निवारण करेगी, लेकिन जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगती, तब तक सरकार कुंभकर्णी नींद सोती रहती है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सूखे की समस्या को लेकर चिंतित हैं, लेकिन देश की सरकार को कोई चिंता नहीं है.

-विनोद यादव, *मुंगेर, बिहार.*

जनता के बारे में भी सोचो

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. उम्मीद करिए कि एक बेहतर मानसून आए शीर्षक तले प्रकाशित अपने आलेख में कमल मोरारका ने सही कहा कि देश में जल संकट बना हुआ है और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे से बुरी तरह प्रभावित है. महाराष्ट्र में आईपीएल से लाखों लीटर पानी की बर्बादी होती, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसके आयोजन पर रोक लगा दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में सूखे का जिक्र किया और लोगों से पानी बचाने की अपील की है.

-राजेश कुमार, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

विधानसभा चुनाव के नतीजे

आलेख-असम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं (25 अप्रैल-01 मई) पढ़ा. मेघनाद देसाई ने बहुत बेबाकी से पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की चर्चा की है. वास्तव में बीता साल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए अच्छा नहीं था. भाजपा को पहले दिल्ली और फिर बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ा. जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनमें भाजपा का दबदबा कभी नहीं रहा, लेकिन इस बार उसकी निगाहें असम पर टिकी हैं, जहां वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है. तमिलनाडु में राष्ट्रीय दलों का प्रभाव कभी नहीं रहा. अभी तक जो चुनावी सर्वे सामने आए हैं, उनमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बहुमत मिलने की बात कही गई है. इस बार अगर किसी को सबसे अधिक नुक़सान हो सकता है, तो वह है कांग्रेस, जो केरल और असम की सत्ता गंवा सकती है. असम में भाजपा और केरल में वाम मोर्चे की सरकार बनने के आसार हैं.

-अमित तिवारी, *सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश.*

जन-जन का अख़बार

चौथी दुनिया देश का एकमात्र ऐसा अख़बार है, जो किसानों की समस्याएं प्रमुखता से उठाता रहा है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर कम ध्यान दे रहे हैं. राज्य के आम जनजीवन से जुड़ी रिपोर्ट्स अधिक से अधिक छापें और चौथी दुनिया को उसके पुराने तेवर में वापस लाएं. पाठकों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं. जनसूचना अधिकार पर आपका प्रयास सराहनीय है.

-मेराज अहमद अंसारी, *बहराइच, उत्तर प्रदेश.*

रियायती प्रीमियम पर फसल बीमा

सूखे और बाढ़ की मार देश के किसानों को लगभग हर साल झेलनी पड़ती है. धान की फसल ऊंचे इलाकों में कम बारिश और तराई इलाकों में बाढ़ के चलते नष्ट हो जाती है. पिछले साल ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल तबाह कर दी थी. राज्य सरकार ने जो राहत राशि दी, वह भी पर्याप्त नहीं थी. किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है, जो मानसून पर निर्भर है. इसलिए सरकार रियायती प्रीमियम पर फसल बीमा योजना लागू करे, जिससे फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को आत्महत्या का रास्ता न चुनना पड़े.

-राज किशोर प्रहरी, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सरकार सूखे को राष्ट्रीय समस्या घोषित कर निदान करे

अभी-अभी जब मैं संपादकीय लिखने बैठा हूं तो खबर आई कि पंजाब में चार किसानों ने आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या की खबरें इतनी आम हो गई हैं कि उनकी चिंता न टेलीविजन को है, न अखबारों को है और न संसद को है. हमारी संसद में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप-प्रत्यारोप करती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता, बस वक्त निकल जाता है और ऐसा लगता है कि संसद चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, एक घटिया टेलीविजन सीरियल का पर्याय बन गई है.

मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 900 किसानों ने आत्महत्या की. महाराष्ट्र से, खासकर मराठवाड़ा से, मेरे पास अकसर यानी हर छठवें-सातवें दिन एक फोटोग्राफ कोई भेज देता है जिसमें एक किसान फंदा लगाकर लटकता हुआ दिखाई देता है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओड़ीशा जैसे राज्य उत्तर भारत के लिए कोई महत्व ही नहीं रखते. यहां पर चाहे सूखा हो, न हो, किसान आत्महत्या करे, किसान तड़पकर मर रहा हो, कोई आंदोलन हो रहा हो, उत्तर भारत में इसे कोई स्थान नहीं मिलता. और संसद है कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त है.

क्या मानें, संसद के पास इतना भी समय नहीं है कि वह सरकार से पूछे और सरकार के पास इतनी शर्म नहीं है कि वह देश को बताए कि उसने सूखे का सामना करने के लिए कोई उपाय किए भी हैं या नहीं. और उन उपायों में उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों का सहयोग चाहिए या नहीं. क्या सरकार को उन छोटे या बड़े क्षेत्र के लोगों को (जहां सूखा नहीं पड़ा है) यह नहीं बताना चाहिए कि उन क्षेत्रों के लोगों की मदद करना उनका भी फर्ज है जहां भयानक सूखा पड़ा है, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई की बात तो बहुत दूर की है.

पीने का पानी कैसे पहुंचाया जाए? फौरी तौर पर सरकार ने रेल से पानी पहुंचाना शुरू किया और उसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है. अपने किए हुए कर्तव्य पालन को हम अपनी उपलब्धि मानने लगें तो समझ जाना चाहिए कि सरकारें जब सारे कामों से फुर्सत पा लेती हैं और जनता के लिए कुछ करती हैं तो यह उनकी उपलब्धि होती है. शायद यही सच भी है कि उन्हें लोगों के ज़िंदा रहने के लिए कुछ करने का वक्त तो मिला.

जब हमने पता किया कि लंबे समय से चले आ रहे सूखे के पीछे कारण क्या है, तो वही सार्वभौम उत्तर मिला-भ्रष्टाचार. एक बड़े तालाब को खोदने का पैसा सैंक्शन हुआ लेकिन उसमें राजनेता, ठेकेदार, अधिकारियों ने मिलकर तीन फीट का गड्ढा खोद लिया और उसे तीन हजार फीट का गड्ढा बताकर उसका सारा पैसा खा लिया. यही अफसोस हर तरह के काम में है और इस भ्रष्टाचार की कहीं कोई सुनवाई नहीं है. भले ही लोग बिना पानी मिले तड़पकर, शरीर में पानी न होने की बीमारी से मर जाएं या खेती में लगातार हुए घाटे की वजह से आत्महत्या कर लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. शायद सरकारें यह संदेश देने में सफल रही हैं कि जनता की तकलीफों से और खासकर जीवन की तकलीफों से और उन तकलीफों से जिनका रिश्ता जीवन और मरण से तात्कालिक तौर पर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. पर अब तो संसद भी यही संदेश दे रही है.

हमें अन्न के लिए लूट के दृश्य शायद थोड़े दिनों बाद देखने को मिलेंगे लेकिन पीने के पानी के सवाल पर एक-दूसरे की गर्दन काटने वाले दृश्य बहुत जल्दी ही

क्या मानें, संसद के पास इतना भी समय नहीं है कि वह सरकार से पूछे और सरकार के पास इतनी शर्म नहीं है कि वह देश को बताए कि उसने सूखे का सामना करने के लिए कोई उपाय किए भी हैं या नहीं. और उन उपायों में उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों का सहयोग चाहिए या नहीं. क्या सरकार को उन छोटे या बड़े क्षेत्र के लोगों को (जहां सूखा नहीं पड़ा है) यह नहीं बताना चाहिए कि उन क्षेत्रों के लोगों की मदद करना उनका भी फर्ज है जहां भयानक सूखा पड़ा है, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई की बात तो बहुत दूर की है.

देखने को मिलेंगे. जहां पर पानी को सशस्त्र सिपाहियों की देखरेख में पहुंचाना पड़े उस देश में सरकार किसी समस्या का समाधान करने में कितनी सक्षम है या कितनी कल्पनाशील है, इसे आसानी से समझा जा सकता है.

दरसअसल भारत सरकार को बिना राजनीति का अ-ब-स-द सोचे पूरे देश को एक क्षेत्र मानकर, विज्ञान का सहारा लेकर जहां-जहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी की कमी है उसके हल के लिए देश के लोगों की मदद लेनी चाहिए और अपनी तरफ से वित्तीय सहायता देनी चाहिए. और अगर उसे लगता है कि देश के लोगों के पास दिमाग नहीं है तो विश्व के उन देशों की मदद लेनी चाहिए जिन्होंने इसी तरह की स्थिति पर विजय पाई हो. और ऐसे देश हैं. आज तकलीफ इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति भी यह मान बैठा था कि वैचारिक मतभेद भले ही एक तरफ हों लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री प्राथमिकताओं की सूची में इस देश की बहुसंख्या के सामने आने वाली तकलीफों (जिनमें सिंचाई और पीने का पानी, खेती की उपज और किसान को कम से कम लागत मिले) और समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे. पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. प्रधानमंत्री जी आपसे फिर मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में लाइए, वरना आप इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे जिसके समय इस देश में पानी और अन्न को लेकर लोगों ने एक दूसरे का सिर फोड़ना शुरू कर दिया. आप निश्चित ही इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाने जाएं, यह हमारी भी हार्दिक इच्छा है, पर इसके लिए अपने महत्वपूर्ण वक्त, अपनी पूरी सरकार और विशेषज्ञों के साथ तत्काल विचार-विमर्श करें और इन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या मानकर, जो कि हैं, इनका तत्काल निदान सोचें. यह अनुरोध आपसे बार-बार है. ■

editor@chauthiduniya.com

कश्मीर पर विश्वास दिखाना चाहिए

मेघनाद देसाई

कनाडा ने 102 साल पहले कोमागाटा मारू (जहाज़) को अपने देश से वापस कर दिया था. जिसके लिए कनाडा सरकार ने कनाडा और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले सिखों से माफी मांगी है. ब्रिटिश शासन से बचने के लिए कुछ बहादुर सिखों ने, जापानी जहाज (कोमागाटा मारू) पर सवार होकर, कनाडा में दाख़िल होने की कोशिश की थी. लेकिन, उन्हें वापस लौटा दिया गया और जब वे भारत लौटे तो उनपर गोलियां चलाई गई थीं. सिख भारत की एक अद्‌भुत कौम है. उनके लिए किसी ने न तो अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात की और न ही उन्होंने जाटों या पाटीदारों की तरह आरक्षण की मांग की.

1980 के दशक से लेकर 1990 के दशक के आधे भाग तक पंजाब जल रहा था. सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल पर जून 1984 में हमला हुआ था. उसके चार महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी. उसके बाद जो हुआ वह सामूहिक हत्या थी या पंजाब में दमन की कार्रवाई. सिखों को आतंकवादी कहकर निशाना बनाया गया. आज तक न तो भारत सरकार ने और न ही कांग्रेस पार्टी ने इस ज़्यादती के लिए सिखों से माफ़ी मांगी है. यह कांग्रेस की असंवेदनशीलता ही थी कि उसने 1984 में हुई हत्याओं के लिए एक सिख प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन फिर भी सिख कौम उल्लेखनीय रूप से ज़िंदादिल और भारत के प्रति वफादार बनी रही. सिख दुनिया में जहां भी गए, उन्होंने वहां की तरक्की में अपना योगदान दिया.

भारतीय लोग भारत के अंदर कई राष्ट्र होने के विचार से ही असहज महसूस करने लगते हैं.

शेष भारत को यह स्वीकार करने की जरूरत है कि कश्मीर का मामला अलग है. भारत के राजनेता जो भी कहें, 1948 में कश्मीर के एक्सेशन के बाद पूर्ण एकीकरण नहीं हो पाया था. भारत का हिस्सा रहते हुए कश्मीरियों का एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में सम्मान किया जाना चाहिए. क्या भारत का कोई दूसरा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री (जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था) को बिना मुकदमे के उसके घर में वर्षों नजरबंद रखा गया हो. फिर भी शेख अब्दुल्ला (कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री) का भारत में विश्वास बरक़रार रहा. भारत को इसके बदले में कश्मीर के प्रति अपना विश्वास दिखाना चाहिए.

यहां विविधता को (देशभक्ति की कमी के हवाले के बिना) स्वीकार करने में एक गहरी असुरक्षा महसूस की जाती है. यूनाइटेड किंगडम ने पिछले 50 वर्षों से यह स्वीकार करना शुरू किया कि वह एक राष्ट्र के बजाए कई राष्ट्रों का संग्रह है. स्कॉट्स (स्कॉटलैंड के लोग) हर उस टीम का समर्थन करते हैं जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फुटबॉल मैच खेलती है. यूनाइटेड किंगडम के प्रति उन्हें अपनी निष्ठा पर कोई शक भी नहीं होता. जब नॉमन टेबिट ने भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों को क्रिकेट मैचों में इंग्लैंड का समर्थन करने के लिए चेताया तो उन्हें हंसी का पात्र बनना पड़ा. इंग्लैंड में टेबिट के बयान को नस्लभेदी करार देकर खारिज कर दिया गया था. यूनाइटेड किंगडम में भारतीय 'राष्ट्र' अगर चाहे तो भारतीय टीमों को समर्थन कर सकता है.

भारत में भारत के अंदर मौजूद सभी राष्ट्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है. नगा लगभग 70 वर्षों से भारत में अपनी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं. या जैसा कि भाजपा अभी कश्मीर में देख रही है कि वहां कश्मीरियों में अलगाव की मजबूत भावना है. हर एक को ज़बरदस्ती भारत माता की जय बुलवा कर देश के प्रति वफादार बनाना ठीक नहीं है. अगर भारत की हार के बाद कश्मीरी युवक खुश होते हैं तो उनकी भावना को हमें समझाना चाहिए और उन्हें समायोजित करने की कोशिश करनी चाहिए.

भले ही यह कहा जाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर को लेकर समस्याएं रही हैं. ऐसा तमिलनाडु और गुजरात के लिए नहीं कहा जा सकता है. जब भारतीय प्रधानमंत्रियों का कश्मीर का दौरा होता है तो वहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी जाती हैं. भारत के किसी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं होता. यूपीए सरकार ने कश्मीर के लिए वार्ताकारों की एक टीम नियुक्त की थी, हालांकि वार्ताकारों की बातों को सरकार ने नज़रअंदाज़ कर दिया था. लेकिन, कर्नाटक या असम के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति हास्यास्पद होगी.

शेष भारत को यह स्वीकार करने की जरूरत है कि कश्मीर का मामला अलग है. भारत के राजनेता जो भी कहें, 1948 में कश्मीर के एक्सेशन के बाद पूर्ण एकीकरण नहीं हो पाया था. भारत का हिस्सा रहते हुए कश्मीरियों का एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में सम्मान किया जाना चाहिए. क्या भारत का कोई दूसरा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री (जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था) को बिना मुकदमे के उसके घर में वर्षों नजरबंद रखा गया हो. फिर भी शेख अब्दुल्ला (कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री) का भारत में विश्वास बरक़रार रहा. भारत को इसके बदले में कश्मीर के प्रति अपना विश्वास दिखाना चाहिए. फिलहाल कश्मीर में एक युवा महिला मुख्यमंत्री बनी हैं. यह भारत के लिए एक मौक़ा है. नरेन्द्र मोदी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोक्ष-ज्ञान भूमि

बदलेगी बोधगया की तस्वीर

चौथी दुनिया ब्यूरो

स्मार्ट सिटी के रूप में भले ही गया का चयन नहीं किया गया है लेकिन हृदय व प्रसाद योजना के तहत इसकी तस्वीर बदलने का प्रयास किया गया है. इस योजना के तहत गया-बोधगया को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्तर का स्वरूप प्रदान किया गया है. मोक्ष और ज्ञान भूमि गया-बोधगया अनादि काल से दुनिया के लोगों के लिए आस्था व श्रद्धा का केन्द्र रहा है. हिन्दू और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए गया-बोधगया वैसे ही श्रद्धा का केन्द्र है जैसे इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए मक्का है. गया में पितरों के लिए पिंडदान करने या गया श्राद्ध करने से इनके संततियों को धन-धान्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है. यही कारण है कि प्राचीन काल से गया में पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिन्दू धर्मावलंबी आते रहे हैं. 15 दिन के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में तो देश-दुनिया के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में हिन्दू धर्मावलम्बी गया आकर पिंडदान करते हैं.

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दौरान सारे पितर गया क्षेत्र में आकर अपनी संततियों से पिंडदान की अपेक्षा करते हैं. गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी का देवघाट पिंडदान का केन्द्र होता है. यही कारण है कि भारत सरकार ने गया शहर को हृदय और प्रसाद योजना के तहत चयन कर इसके विकास के लिए वृहद योजना तैयार की है. काम शुरू भी हो चुका है. कुछ काम तो 30 अप्रैल 2016 तक पूरा भी हो जाना है. इसी प्रकार तथागत की तपोभूमि बोधगया का भी चयन हृदय योजना के तहत किया गया है. आज से 2600 वर्ष पूर्व निरंजना नदी के तट पर स्थित बोधगया प्राचीन नाम उरूवेला में एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. तब से बोधगया दुनिया के बौद्ध धर्मालंबियों के लिए आस्था का केन्द्र बना है. केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से प्रसाद योजना के तहत वर्ष 2013-2014 में साढ़े चार करोड़ की राशि आवंटित की गई है. इस राशि से विष्णु मंदिर परिसर में काम किया जा रहा है. इसके साथ ही हृदय योजना के तहत विष्णुपद मंदिर परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों को 34 करोड़ की राशि से विकसित किया जाएगा. गया के आसपास स्थित अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जाएगा. पवित्र फल्गु नदी के विभिन्न घाटों का भी सौंदर्यीकरण इन दोनों योजनाओं के तहत किया जाएगा. फल्गु किनारे टुरिस्ट स्पॉट भी बनाया जाएगा. इसी प्रकार बोधगया का चयन भी प्रसाद योजना के तहत किया गया है.

बोधगया को और बेहतर रूप से विकसित करने के लिए योजना तैयार की गई है. बोधगया को हरित शहर के रूप में विकसित करने की योजना है. केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से बोधगया उत्सव के आयोजन का भी प्रस्ताव है. साथ ही निरंजना नदी के रीवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण 10 करोड़ रूपये से किया जाना है. इस योजना के तहत डहेरिया

महावस्तु ग्रंथ में बुद्ध ने निरंजना के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहा है-वहां मैंने एक रमणीय, प्रसन्नताकारी भूमि में एक नदी को बहते देखा, जिसका घाट श्वेत और रमणीय था. चीनी यात्रा ह्वेनसंग ने भी निरंजना की रमणीयता का उल्लेख किया है. बौद्ध साहित्य ललितविस्तर और महावस्तु में इस नदी के जल को निर्मल, शुद्ध, नीला व शीतल बताया गया है.

बिगहा से सूरजपूरा तक निरंजना नदी के पश्चिमी तट के सुदृढ़ीकरण के अलावा घाटों का निर्माण होगा. इसके अलावा रोशनी की व्यवस्था कुछ इस तरह की जाएगी, जिससे पूरा तट मनमोहक लगे. बैठने के लिए पार्क में बेंच के अलावा कुटी की भी व्यवस्था होगी. यह तट योजना के पूरा होने के बाद पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विकसित होगा. शौचालय, यूरिनल व जलपानगृह भी बनेगा. हालांकि नदी में पानी रखने के लिए सूबे की सरकार ने भी 4 करोड़ से चेक डैम का प्रस्ताव तैयार किया है. यह सूरजपूरा के निकट बोधगया नगर पंचायत की सीमा पर होगा. महावस्तु ग्रंथ में बुद्ध ने निरंजना के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहा है-वहां मैंने एक रमणीय, प्रसन्नताकारी भूमि में एक नदी को बहते देखा, जिसका घाट श्वेत और रमणीय था. चीनी यात्रा ह्वेनसंग ने भी निरंजना की रमणीयता का उल्लेख किया है. बौद्ध साहित्य ललितविस्तर और महावस्तु में इस नदी का जल, निर्मल, शुद्ध, नीला व शीतल बताया गया है. स्नान के लिए घाट बने थे व नीचे उतरने के लिए क्रमबद्ध सीढ़ियां थी. महाबोधिवंश में इसके तट पर शालवन की बात कही गई है. इस प्रकार गया तथा बोधगया को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की योजना बनाई गई है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक यहां आ सकें. ■

feedback@chauthiduniya.com

काकोलत जलप्रपात

उपेक्षा का दंश झेलता बिहार का कश्मीर

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

बिहार के नवादा जिले में स्थित काकोलत जलप्रपात को आज तक पूर्ण पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया जा सका है. गर्मी के दिनों में भी दूर से ही ठंड का एहसास कराने वाली काकोलत जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहा जाता है. गर्मी के दिनों में आस-पास के जिले ही नहीं बल्कि झारखण्ड से भी बड़ी संख्या में लोग काकोलत जलप्रपात का आनन्द लेने पहुंचते हैं. प्रति वर्ष 14 अप्रैल को लगने वाले बिसुआ मेले को भी बिहार सरकार बहुत अधिक महत्व नहीं दे पाती है. जिसके कारण अद्भुत और कौतुहल का विषय माना जाने वाला काकोलत जलप्रपात राज्य में भी अपनी खास जगह नहीं बना पा रहा है. कुछ स्थानीय लोगों के प्रयास से इस जलप्रपात की महत्ता को प्रचारित-प्रसारित करने का काम किया जा रहा है. लेकिन यह प्रयास सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण बहुत सार्थक नहीं हो पा रहा है. नवादा जिले से 35 किलोमीटर दूर गोविंदपुर प्रखंड में स्थित है, काकोलत जलप्रपात. यह एक ऐसा जलप्रपात है, जो सुन्दरता और प्राकृतिक सौन्दर्य के लिहाज से देश के किसी भी जलप्रपात से कम नहीं है. लेकिन सरकार तथा संबंधित विभाग द्वारा इस जलप्रपात की खूबसूरती में चार-चांद लगाने के बदले इसके अस्तित्व को ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है. बिहार में कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात को विकास के इस दौर में सबसे ऊपर होना चाहिए था. लेकिन बिहार सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में इसका स्थान कहीं नहीं है. काकोलत जलप्रपात को विकसित कर दिया जाए तो यहां विदेशी सैलानियों की भीड़ लगी रहेगी, जिससे सरकार के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी व्यावसायिक लाभ होगा.

काकोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीहुद्दीन बताते हैं कि यह जलप्रपात प्राचीनकाल से प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है. प्रति वर्ष 14 अप्रैल को यहां लगने वाले पांच दिवसीय सतुआनी मेला पर आस-पास के लोगों का बड़ा जमावड़ा लगता है. लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से इसके विकास के लिए सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकार चाहे तो काकोलत जलप्रपात के रास्ते यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराके बेरोजगारी दूर कर सकती है. झारखण्ड से अलग होने के बाद शेष बिहार में काकोलत अकेला ऐसा जलप्रपात है, जिसका पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है. बिहार सरकार इस ऐतिहासिक जलप्रपात की महत्ता को समझे या नहीं लेकिन भारत सरकार के डाक एवं तार विभाग ने इस जलप्रपात की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए काकोलत जलप्रपात पर पांच रुपये मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया है. इसका लोकार्पण भी डाक तार विभाग ने 2003 में काकोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीहुद्दीन से पटना में कराया था. 1995 से पहले काकोलत जलप्रपात के तालाब में स्नान करने के दौरान दर्जनों लोगों की जान चली गई थी. लेकिन गया के तत्कालीन प्रमंडलीय वन पदाधिकारी वाईके सिंह चौहान के अथक प्रयास से काकोलत जलप्रपात को बहुत ही सुन्दर रूप भी दिया गया. उन्होंने विशेषज्ञों की राय लेकर जलप्रपात के पानी को लोहे के बने पाइप के सहारे मोड़ कर तालाब के गड्ढे को पूरी तरह भरकर एक आकर्षक तालाब का रूप दिया, जो आजतक बरकार है.

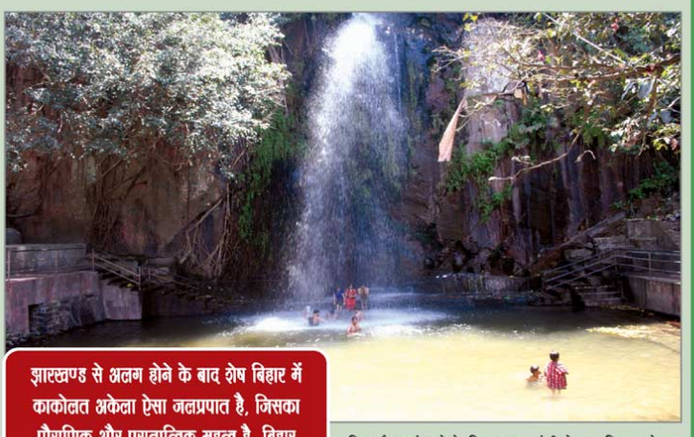

झारखण्ड से अलग होने के बाद शेष बिहार में काकोलत अकेला ऐसा जलप्रपात है, जिसका पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है. बिहार सरकार इस ऐतिहासिक जलप्रपात की महत्ता को समझे या नहीं लेकिन भारत सरकार के डाक एवं तार विभाग ने इस जलप्रपात की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए काकोलत पर पांच रुपये मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया है.

अब काकोलत जलप्रपात के तालाब में डूबने से किसी की मौत नहीं होती है. हालांकि चौहान के इस प्रयास में नवादा के तत्कालीन जिला पदाधिकारी रामवृक्ष महतो और काकोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीहुद्दीन का सहयोग मिला. जिला पदाधिकारी ने 50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी तो डीएफओ ने वन विभाग के तमाम नियमों में शिथिलता बरतते हुए काकोलत जलप्रपात को एक अच्छे पर्यटन स्थल का रूप दे दिया. यहां वन विभाग की ओर से आकर्षक गेस्ट हाउस और दुकानों का निर्माण भी कराया. कुछ वर्षों तक तो यहां सबकुछ अच्छा चला. लेकिन इन पदाधिकारियों का स्थानांतरण होते ही काकोलत जलप्रपात पुन: उपेक्षित हो गया. हालांकि काकोलत विकास परिषद की ओर से 1997 में प्रति वर्ष लगने वाले बिसुआ मेला को काकोलत महोत्सव का नाम देकर एक बड़ा आयोजन कराया. जिसकी शुरुआत गया के प्रसिद्ध माउंटेन मैन दशरथ मांझी के हाथों कराया था.

इस महोत्सव के माध्यम से मगध की सांस्कृतिक विरासत को बचाने तथा यहां की प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास किया जाता है. लेकिन अफसोस है कि सुशासन में भी काकोलत जलप्रपात की उपेक्षा की गई. यह जलप्रपात नवादा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर पूर्व दक्षिण गोविंदपुर प्रखंडम में स्थित है. यहां जाने के लिए नवादा रांची रोड पर स्थित फतेहपुर मोड़ से जर्जर सड़क के सहारे जाना पड़ता है. अभी हाल में फतेहपुर मोड़ से काकोलत जाने वाली सड़क में काम लगा है. सात पर्वत श्रृंखलाओं से प्रवाहित काकोलत जलप्रपात और इसकी प्राकृतिक छटा बहुत सारे कौतुहल को जन्म देती है. धार्मिक मान्यता है कि पाषाणकाल में दुर्गा सप्तशती के रचयिता ऋषि मारकण्डेय का काकोलत में निवास था. धार्मिक मान्यता यह भी है कि काकोलत जलप्रपात में वैशाखी के अवसर पर स्नान करने मात्र से सांपयोनि में जन्म लेने से प्राणी मुक्त हो जाती है. इस जलप्रपात की खोज अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस बुकानन ने 1811 में की थी. फ्रांसिस बुकानन ने इस जलप्रपात को देखा और कहा कि जलप्रपात का नीचे का तालाब काफी गहरा है. इसकी गहराई को भरने के उद्देश्य से एक अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर यहां स्नान करने वाले लोगों को पहले तालाब में एक पत्थर फेंकने का नियम बनाया था. क्योंकि इस तालाब में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है. लेकिन 1995 में इस तालाब को भर दिया गया और आकर्षक बना दिया गया. लेकिन सरकार की सार्थक दृष्टि नहीं पड़ने के कारण यह जलप्रपात आज भी उपेक्षित है. यह जलप्रपात किसी दूसरे राज्य में होता तो पर्यटन का मुख्य केन्द्र होने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के आय का भी बड़ा साधन होता. लेकिन न जाने किस कारणवश इस अद्भुत जलप्रपात की उपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है. पर्यटन विभाग चाहे तो वन विभाग से मिलकर काकोलत जलप्रपात को सचमुच में कश्मीर बनाया जा सकता है. ■

VCSM®
विश्व कम्प्यूटर साक्षरता मिशन
A program initiated by Sanjeeo Technological System (P.) Ltd.
ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified
VCSM की फ्रेंचाइजी बनिए और अपने साथ-साथ हजारों के कैरियर बनायें।
विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें : जूही अलका 9386551901

काम बिहार में, आराम बंगाल में

सीमांचल के शराबियों ने खोजा नया ठिकाना

नीरज सिंह

बिहार में एक अप्रैल से शराबबंदी कर नीतीश कुमार जहां अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं वहीं भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उनके द्वारा की शराबबंदी को पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं. विरोधियों का कहना है कि पहले नीतीश ने घर-घर शराब परोस कर सबको पीने की लत लगा दी अब शराबबंदी करके आधी आबादी महिलाओं के हमदर्द बनने में जुटे हुए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर इसे राजनीतिक हथियार बनाकर प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना पालने लगे हैं. लेकिन इसके साइड इफेक्ट अभी से मिलने चालू हो गये हैं.

मालूम हो कि वर्ष 2014 में बिहार सरकार को शराब मद से कुल 3500 करोड़ रुपये, कुल राजस्व का 15 प्रतिशत प्राप्त हुआ था. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के अनुसार भारत में सबसे अधिक शराब की खपत में बिहार चौथे स्थान पर था. शराब से बिहार सरकार को प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ की आय होती थी. पूर्व में 1977 में कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में शराब पर प्रतिबंध लगा था. आर्थिक राजनीतिक कारणों से कर्पूरी ठाकुर को फैसला वापस लेना पड़ा. 1996 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने शराब बंदी को लागू किया परिणाम यह निकला कि हरियाणा के सारे शराबियों का जमावड़ा राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की सीमा पर रात भर लगने लगा. शराबी शराब पीने रात में राजस्थान पंजाब जाने लगे और सबेरे होने पर घर लौटते थे. शराब बंदी के कारण 1998 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बंसी लाल की हरियाणा विकास पार्टी की करारी हार हुई.

बिहार में शराब बंदी से सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार के शराबियों का जमावड़ा बंगाल एवं नेपाल की सीमा पर लगने लगा है जिससे यहां शराब की बिक्री में दोगुने से अधिक का इजाफा हुआ है. बंगाल सरकार को बिहार में शराबबंदी का भरपूर राजस्व का लाभ मिलने लगा है. बंगाल सरकार विगत एक माह के अंदर राजस्व बढ़ाने को लेकर सीमांचल की सीमा से सटे बंगाल के छोटे-छोटे कस्बों में धी दुकानें एवं बियर-बार लगभग एक दर्जन नये लाइसेन्स निर्गत किये हैं. इससे बंगाल के उत्पाद राजस्व मे काफी उछाल आया है.

बंगाल का हरिश्चंद्रपुर, टुनीदिघी, करणदिघी कटिहार के बारसोई अनुमंडल की सीमा से लगता है, बंगाल का दालकोला और सूर्यापुर पूर्णिया के बायसी अनुमंडल से सटा है. किशनगंज से बंगाल का कानकी रामपुर पांजीपाड़ा सटा है. किशनगंज के पोठिया से इस्लामपुर कालागच्छ एवं सोनापुर सटा है. वही ठाकुरगंज से विधान नगर, बागडोगरा, सिलीगुड़ी और गलगलिया सटा है. ये सारे कस्बे राष्ट्रीय उच्चपथ 31 एवं 327 पर स्थित हैं. यहां पर बिहार के शराबियों का जमघट लगने लगा है. शाम ढ़लते ही यहां के बियर बार से लेकर लाइन होटलों में बहार छा जाती है. इस्लामपुर स्थित ब्लू डायमंड बियर बार में कुछ शराबियों से बिहार में शराब बंदी को लेकर बात की गई तो अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर वे तपाक से बोल पड़े. एक पारो थी जो देवदास को हमेशा शराब छोड़ने के लिए कहती रही, मगर एक देवदास की शराब नहीं छुड़वा सकी. अब एक नीतीश कुमार हैं जो एक झटके पूरे बिहार वासियों का शराब छुड़वा देना चाहते हैं. अब हमारा रात्रि विश्राम भी बंगाल में होने लगा है. बंगाल में घर भी बना रहे हैं. काम करेंगे बिहार में, आराम करेंगे बंगाल में. बिहार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी रोक लग रही है. उल्टे सवाल दागते हुए पूछा कि बिहार में लॉटरी पर प्रतिबंध है फिर भी वहां लॉटरी बिक रही है. बंगाल में न तो लॉटरी पर प्रतिबंध है न तो शराब पर. आज बंगाल दोनों तरह के राजस्व से मालामाल हो रहा है, जबकि बिहार दोनों राजस्व से वंचित है ऐसे में जब राज्य को राजस्व ही नहीं प्राप्त होगी तो विकास खाक होगा. वहीं ठाकुरगंज, दिघलबैंक, टेढ़ागाछ, कुरसाकांटा, सिकटी, पलासी, जोगबनी, फारबिसगंज के शराबी जब शाम में नेपाल में प्रवेश करते हैं तो दूसरे दिन प्रातः ही घर लौटते हैं. हाल यह है कि शराब के लिए सीमांचल के शराबियों ने ठिकाना खोज लिया है. ऐसा नहीं है कि सरकार सतर्क नहीं है. लगातार छापेमारी हो रही है और शराब जब्त भी हो रही हैं. लेकिन अगर पड़ोसी राज्य मदद नहीं करेंगे तो इसका असर बिहार पर पड़ना तय है. हालांकि सूबे का पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है.

बिहार सरकार ने राज्य से लगी नेपाल एवं बंगाल के सीमा पर अवैध शराब के प्रवेश को रोकने लिए कुल 39 चेक पोस्ट बनाए हैं. जहां सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है लेकिन नित्य शराब तस्करी के नये मामले प्रकाश में आ रहे हैं. मद्य निषेध अभियान के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर किशनगंज के फारिंग गोला चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक पिकप वैन डब्लू बी 73सी 6656 से 150 पेटी बीयर बरामद हुई. चालक के अनुसार यह माल सिलीगुड़ी से मालदा जा रहा था. 21 अप्रैल को राज बस डब्लू बी 73-2370 से 38 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ. इस गाड़ी से गलगलिया चेक पोस्ट दो तस्कर को भी पकड़ा गया राज बस सिलिगुड़ी से मुजफ्फरपुर जा रही थी. गलगलिया में नेपाली युवक मिलन लिम्बू से सिक्किम निर्मित दो बोतल विदेशी शराब एवं एक बोतल बीयर पकड़ी गई. 20 अप्रैल को जोगबनी बॉर्डर पर चार युवकों को नेपाली शराब के साथ पकड़ा गया. पूर्णिया के दलकोला चेक पोस्ट पर 24 अप्रैल को एक एंबुलेन्स से 25 लीटर विदेशी शराब की पेटियां जब्त की गई. एंबुलेन्स चालक सुरेश नाथ का कहना था कि शराब लेकर वह आंध्रप्रदेश जा रहा था. साथ ही उसका कहना था कि लाश लेकर वह सिक्किम गया था लेकिन रास्ता भटक गया. विगत दिनों बंगाल-बिहार सीमा पर हटवार (किशनगंज) गुमा बियर बार पर बिहार-बंगाल पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब जब्त की गई. उल्लेखनीय है कि बंगाल के उत्पाद विभाग द्वारा गुप्ता बियर बार को एक नई शराब दुकान का लाइसेन्स हाल ही में निर्गत किया गया था. पूर्णिया के कुछ शराबियों का कहना कि 200 रुपये अधिक देने से पूर्णिया में शराब उपलब्ध हो जा रही है, जो गिट्टी लदे ट्रकों के माध्यम से पूर्णिया पहुंचती है. पूर्णिया प्रमंडल के डीआईजी उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने 14 मार्च की बैठक में कहा कि नेपाल, बांग्लादेश-पश्चिम बंगाल की सीमा राज्य से लगने के कारण शराब की खेप पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस विभाग ने हर जरूरी कदम उठाए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीमांचल के शराबियों के नए ठिकानों पर बिहार पुलिस कैसे और क्या कार्रवाई करती है? ■

> इस्लामपुर स्थित ब्लू डायमंड बियर बार में कुछ शराबियों से बिहार में शराब बंदी को लेकर बात की गई तो अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर वे तपाक से बोल पड़े. उन्होंने कहा कि एक पारो थी जो देवदास को हमेशा शराब छोड़ने के लिए कहती रही, मगर शराब नहीं छुड़वा सकी. अब एक नीतीश कुमार हैं जो एक झटके पूरे बिहार वासियों का शराब छुड़वा देना चाहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ., साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते समय लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मित विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिश्न में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डड ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ., साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूँ, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कप पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- मोरिक होमियो टेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -बिजापुर 9341610592 गुलबर्ग:9343834519

भयंकर गर्मी और लू से बचें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ नरेश कुमार यादव मधेपुरा के ग्वालपारा के जेनरल फिजिशियन से बातचीत के अंश यहां प्रस्तुत हैं। बिहार के साथ साथ देश के कई हिस्से में गर्मी का पारा सामान्य से अधिक चल रहा है इसके कारणों और उपचार पर उन्होंने बातचीत की- लू और ताप घात क्या है ? - इस गर्मी के प्रकोप मे लू से कोई प्रभावित हो सकता है परन्तू बच्चे, गर्भवती महिलायें धूप मे व दोपहर मे कार्यरत श्रमिक, यात्री, खिलाड़ी व ठण्डी जगवायु मे रहने वाले व्यक्ति (ए.सी. मे रहने वाला व्यक्ति) सबसे अधिक प्रभावित होते है। लक्षण:- शरीर मे लवण एव पानी अपर्याप्त होने पर अचानक ठंढ से गर्म वातावरण मे आने से यह लक्षण दिखते हैं- 1. सिर का भारीपन एवं सिरदर्द। 2.अधिक प्यास लगना एवं शरीर मे भारीपन के साथ थकावट। 3. जी मचलना, सिर चकराना व शरीर का तापमान बढना। 4.शरीर का तापमान अत्यधिक (105 फॉरेनहाईट या अधिक) हो जाना व पसीना आना बन्द होना, मुंह का लाल हो जाना व त्वचा का सूखा होना। 5. अत्यधिक प्यास का लगना बेहोशी जैसी स्थिति का होना बेहोश हो जाना। 6. प्राथमिक उपचार या समुचित उपचार के अभाव मे मृत्यु भी संम्भव है। इसलिए डॉक्टर से परामर्श लेते रहें **बचाव / उपाय-** 1) प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक गर्मी से बचाने हेतु छायादार ठंढे स्थान पर रहने का प्रयास करें। 2) तेज धूप मे निकलना आवश्यक हो तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा मे ठंढे जल का सेवन करके बाहर निकले अर्थात खाली पेट न निकलें और पानी साथ में हमेशा लेकर चलें। 3)थोड़े अन्तराल के पश्चात ठंढे पानी,शीतल पेय, छाछ , ताजा फलो का रस का सेवन करते रहें। 4) तेज धुप मे सूती फुल बांह के कपड़े, सिर पर कपड़ा रखकर चलें हो सके तो इन दिनों चश्में का प्रयोग बिना शौक के भी करना चाहिए। बाहर निकलने पर छाते का उपयोग करें। 5) प्रभावित रोगी को तुरन्त छायादार ठंढे स्थानो पर लिटा दे। 6) रोगी की त्वचा को गीले कपड़े से स्पन्ज करते रहें तथा रोगी के कपडो को ढीला कर दे। 7). रोगी होश मे हो तो उसे ठन्डा पेय पदार्थ देवे। 8) रोगी को तत्काल नजदीक के चिकित्सा संस्थान मे उपचार हेतु लेकर जायें एवं डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। ■ भारती

DR.NARESH KUMAR YADAV
(MBBS) GWALPARA(MADHEPURA)

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

वर्ल्ड बैंक और सरकार प्रायोजित धंधा है बांध निर्माण

पर्वत पर पहाड़ जैसा अन्याय

अरुण तिवारी

उत्तराखंड राज्य में सैकड़ों बांध बनाए जा रहे हैं. काफी बनाए जा चुके हैं. इन बांधों के निर्माण से पहले कुछ सपने हर बांध से प्रभावित होने वाली जनता को दिखाए जाते हैं. जैसे बांध निर्माण से बिजली उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्धी हो जाएंगे, लोगों का बेहतर पुनर्वास किया जाएगा आदि-आदि. अब इसका वास्तविक पक्ष या कहिए स्याह पक्ष देखना हो तो एक बार टिहरी बांध की ओर नज़र जरूर दौड़ानी चाहिए. टिहरी बांध के विस्थापितों का दर्द लगभग उत्तराखंड के प्रत्येक बांध विस्थापित की कहानी है. इसी तरह का एक बांध बन रहा है विष्णुकगॉड पीपलकोटि बांध.

पीपलकोटि बांध के निर्माण की सुगबुगाहट होने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था. साल 2004 में ही इसके निर्माण से होने वाले खतरों के मद्देनजर कई खत सरकार को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए. लेकिन इसके बावजूद बांध बनाने की कागजी कार्रवाई चलती रही. बांध के विस्थापितों की आवाज उठाने वाले एनजीओ माटू जनसंगठन के प्रमुख विमल भाई कहते हैं कि पीपलकोटि बांध को लेकर पहली जनसुनवाई साल 2006 में रखी गई. उस जनसुनवाई में हमने बांध निर्माण का विरोध किया था. उस सुनवाई के दौरान विश्व बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे. हमने इस बात का भी विरोध किया कि यहां जनसुनवाई के दौरान विश्व बैंक के अधिकारी क्यों मौजूद हैं? विमल भाई कहते हैं कि पीपलकोटि तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है. उत्तराखंड में बांध बनाने का धंधा चल रहा है, जिसमें विश्व बैंक के अधिकारी और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है. वे जेपी कंपनी पर सीधे उंगली उठाते हुए कहते हैं कि इस धंधे में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाकर यही कंपनी आम लोगों को लूट रही है. वे टिहरी बांध को उत्तराखंड राज्य की संस्कृति पर एक धब्बा बताते हैं.

माटू जनसंगठन के प्रमुख विमल भाई कहते हैं कि पीपलकोटि तो सिर्फ एक प्रोजक्ट है, उत्तराखंड में तो बांध बनाने का धंधा चल रहा है. इस धंधे में विश्व बैंक के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है. वे कहते हैं कि टिहरी बांध उत्तराखंड की संस्कृति पर एक धब्बा है. उनका मानना है कि बांध निर्माण की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई. अविरल बहती नदियों पर बांध बनाकर आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है.

बांध विस्थापितों की आवाज बुलंद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विमल भाई

पीपलकोटि बांध की दूसरी जनसुनवाई 2007 में हुई और इसी साल 22 अगस्त को इसे इन्वायरनमेंटल क्लियरेंस मिल गई. अब इसे फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यवकता थी. 2008 में वह भी दे दी गई. लेकिन इसके बाद मामला अदालत में होने की वजह से बांध निर्माण का काम लटका रहा. 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य में चल रहे सभी बांधों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी. राज्य सरकार ने चालाकी दिखाते हुए इस प्रोजेक्ट की बैक डेट में क्लियरेंस दे दी. उसके बाद यहां उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद काम चालू हो गया. बांध निर्माता कंपनी टीएचडीसी ने फिर वही सब काम शुरू कर दिए जो वह पहले भी अपने कई प्रोजेक्ट के दौरान करती आई है. बांध निर्माण के दौरान पूरा मलबा नदी में डाला जा रहा है. इसमें बहुत संशय नहीं है कि यह भविष्य में फिर एक भयावह बाढ़ को आमंत्रित करे. ज्यादा समय नहीं बीता जब उत्तराखंड एक ऐसी त्रासदी से गुजर चुका है और अभी उसके घाव भरे नहीं है.

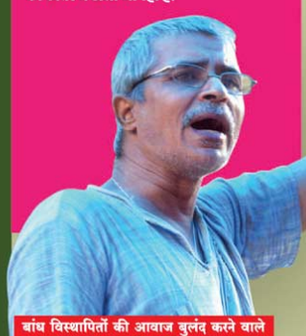

कंपनियों द्वारा आम जनता को दिए जाने वाले लालच के बारे में भी विमल भाई बताते हैं. कहते हैं कि कंपनियों को जिन इलाकों में बांध निर्माण का काम करना होता है, वहां के लोगों को वे लालच देना शुरू कर देती हैं. लोगों में पैसे बांटे जाते हैं. पुनर्वास का प्रलोभन दिया जाता है. गांव के प्रधान या किसी एक रसूखदार आदमी तक कंपनी के अधिकारी पहुंच बनाते हैं जो लोगों को अपने लालच के जाल में फांस सकें. वे कहते हैं कि जब पैसा बंट रहा होता है तो ऐसे समय में हमारे लिए लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है. हमारे खिलाफ वहां की आम जनता को भी भड़काया जाता है कि विरोध करने वाले लोग विदेशी धन से संचालित हो रहे हैं और विकास कार्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं. आम जनता इन लोगों के लालच में आ जाती है और फिर बाद में त्रासदी भुगतती है. कंपनियां सीएसआर का पैसा भी डकार जाती हैं.

बांध की सच्चाई बयान करने वाले एक सर्वे ने साल 2001 में कहा था कि बांध निर्माण से सिंचाई की एक इंच जमीन भी नहीं बढ़ी है. मतलब पहले से ही मौजूद जिन संसाधनों के आधार पर खेती की जा रही थी और जितना उत्पादन हो रहा था, उसमें कोई बढ़ोतरी बांध निर्माण से नहीं हुई. हालांकि इस मामले में टीएचडीसी कंपनी के अधिकारी यही कहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है. लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके सारे दावे काफुर हो जाते हैं.

विमल भाई कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि बांध निर्माण की प्रक्रिया से यहां के लोग जूझ रहे हैं. वे पूछते हैं कि आप ही बताइए कौन सा ऐसा बांध है जहां से पूर्व में निर्धारित की गई बिजली क्षमता का पूरा उत्पादन हो पा रहा है. कंपनी के अधिकारी बांध निर्माण से पहले बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य दिखाते हैं वह बांध निर्माण के बाद शायद ही पूरा हो पाता है. इसका मतलब यह है कि जिस विकास के खोखले वायदे के साथ आप नदियों को अविरल बहने से रोककर प्राकृतिक त्रासदियों को बुलावा देते हैं, उस विकास के वायदे के हर चरण पर सरकार असफल साबित होती है. इतिहास इसका गवाह है. आप इस संदर्भ में उत्तराखंड के टिहरी बांध के मामले को शुरुआत से देखिए. इस बांध की वजह से यहां के लोगों के जीवन में जो तबाही आई है, उसकी भरपाई शायद ही हो पाए.

कई रिपोर्ट ऐसी भी आई कि विश्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट को फंड करने से मना कर दिया. तो फिर आखिर कैसे ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए. इस पर विमल जवाब देते हैं कि देखिए विश्व बैंक के भारत में जो अधिकारी हैं, उन्हें भी अपनी दुकान चलानी है. उनका यहां सरकारी अधिकारियों और कंपनियों से गठजोड़ होता है. यह एक पूरा सिस्टम है जो साथ मिलकर उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद करने का प्रण ले चुका है. मान लीजिए कि हमने यहां से खत लिखकर विश्व बैंक के मेन ऑफिस को सूचित भी कर दिया तो यहां मौजूद उसके अधिकारी वहां पर पूरे मामले को रफा-दफा करने के लिए जोर लगाते हैं. बांध निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो सरकारी अधिकारी निरीक्षण करने जाते हैं वे भी सही रिपोर्ट नहीं लगाते. अगर वे यह रिपोर्ट लगा दें कि यहां बांध का मलबा नदियों में डाला जा रहा है तो इनका इन्वायरनमेंटल क्लियरेंस तुरंत ही रद्द हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी इस गठजोड़ का हिस्सा हैं. एक योजना की शुरुआत में ही यह तय हो जाता है कि पुनर्वास के दौरान लगभग कितने पैसे का खर्च बैठेगा. शुरुआती पुनर्वास दिखावे के लिए तेजी से किया जाता है लेकिन फिर बाद में उसकी बंदरबांट शुरू हो जाती है. आप ये सोचिए कि आखिर इन सब के बीच नुकसान किसका होता है. कमाल की बात तो यह है कि जब आम जनता इसके खिलाफ आंदोलन करती है तो उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं. अभी पीपलकोटि बांध का विरोध करने पर सौ से अधिक ग्रामीणों पर मुकदमे लाद दिए गए हैं. सरकार कहती है ये देशविरोधी लोग हैं और विकास कार्य नहीं होने देना चाहते. आप बताइए यह विकास किसके लिए हो रहा है? क्या इन बांधों के आस-पास की जनता देश की नागरिक नहीं है? क्या इस देश का विकास उनकी बर्बादी की शर्त पर ही होगा?

दरअसल, पीपलकोटि बांध एक बानगी है उत्तराखंड में बांध के नाम पर चल रहे गोरखधंधे की. इस गोरखधंधे में विश्व बैंक, सरकार और स्वदेशी कंपनियों के अलावा कई ऐसे एनजीओ भी शामिल हैं जो बांध विकास कार्य की पहली शर्त बताते हैं. इनका काम लोगों तक सही बात पहुंचाना है लेकिन ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर अपना पेट भरने का धंधा करते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें बिजली और सिंचाई जैसी जरूरतों के लिए बांधों की आवश्याकता है. लेकिन बांध निर्माण के दौरान होने वाले घपले सिर्फ बदनीयत दिखाते हैं. दरअसल इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो लोगों को लूट कर भागने की फिराक में रहती हैं, अगर यही काम जनता के प्रतिनिधियों ने भी करना शुरू कर दिया तो समझिए बेड़ा गर्क होने में ज्यादा समय नहीं है. यह याद रखना होगा कि उत्तराखंड ने बाढ़ की बड़ी त्रासदी देखी है. अगर यूं ही हीलाहवाली में बांधों का निर्माण कार्य चलता रहा तो जल्द ही एक और केदारनाथ जैसी त्रासदी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

पर्वत प्रदेश को भी मार रहा सूखा बैताल

कहीं लुप्त न हो जाए नैनी का ताल

राजकुमार शर्मा

हिमालयी राज्य उत्तराखंड भी इस बार बुरी तरह सूखे की चपेट में आ चुका है. गर्मी की शुरुआत होते ही हिमालय की सदा प्रवाहमान रहने वाली नदियां एवं निर्मल झीलें अभी से हांफती नजर आने लगी हैं. मौसम की बेरुखी का असर अब उत्तराखंड और नैनी झील पर भी दिखने लगा है. नैनीताल की मशहूर नैनी झील का जलस्तर तेजी से घट रहा है और झील का जलस्तर गिरकर अप्रैल माह में ही साढ़े सात फीट से भी नीचे चला गया. जानकारों का कहना है कि 82 वर्षों में ऐसी स्थिति पहली बार आई है. अगर मौसम का यही मिजाज रहा, तो पेयजल का संकट गहरा सकता है जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है. झील का जलस्तर कम होना प्रशासन के साथ ही पर्यटन व्यवसायियों और सैलानियों को भी चिंतित कर रहा है.

नैनी झील नैनीताल के लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है. यहां के लोगों की पहचान है. झील की सेहत और खूबसूरती से नैनीताल की खूबसूरती है, क्योंकि पयर्टन ही यहां का मुख्य रोजगार है. इस झील से नैनीताल के साथ-साथ आसपास के इलाकों के लोगों को भी पीने का पानी और रोजगार मिलता है. 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर भारत सरकार ने नैनीताल की झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए लगभग 48 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना मंजूर की थी. इस योजना के तहत लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से झील में एयरेशन(सफाई) के अलावा और कोई काम नहीं हुआ. पिछले लगभग 18 सालों से नैनी झील की सालाना नाप-जोख तक नहीं हो पाई है.

नैनी झील के संरक्षण के लिए कराड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं. पयर्टन के कारण सलाना अरबों रुपये का कारोबार होता है. लेकिन आज तक नैनी झील के संरक्षण के लिए बनी योजनाओं पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है. सरोवर नगरी में पयर्टन का मौसम शुरू होते ही माल रोड हो या फिर इससे लगे होटल हर जगह पयर्टकों की चहलकदमी दिखाई देने लगी है. लेकिन पयर्टन के व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के चेहरे से रौनक गायब है जो पहले पयर्टन की शुरुआत होने के समय नजर आती थी. बीते वर्षों तक अप्रैल के महीने में नैनी झील लबालब भरी रहती थी. कहीं जाकर मई और जून के महीने में झील का जल स्तर कम होता था. झील में हमेशा इतना पानी रहता था कि यहां आने वाले सैलानी अपने आप ही झील को ओर आकर्षित हो जाते थे. लेकिन इस बार का नजारा बिल्कुल उलट है.

एनजीटी ने भूजल दोहन करने वालों का ब्यौरा मांगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिना अनुमति के रोजाना लाखों लीटर भूजल का दोहन करने वाले स्लॉटर हाउस और मीट एक्सपोर्ट युनिटों पर अब निगाहें टेढ़ी कर दी है. एनजीटी ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्लॉटर हाउसों और मीट एक्सपोर्ट यूनिटों का ब्यौरा मांगा है. ब्योरे में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी से भूजल दोहन की अनुमति की एनओसी और दूसरे प्रमाण पत्र भी मांगे गए हैं. इस केस में मीट, चर्बी की दुर्गंध और भूजल प्रदूषण की बेहद गंभीर समस्या भी शामिल है. ■

नैनी झील के संरक्षण के लिए कराड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं. पयर्टन के कारण सालाना अरबों रुपये का कारोबार होता है. लेकिन आज तक नैनी झील के संरक्षण के लिए बनी योजनाओं पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है. सरोवर नगरी में पयर्टन का मौसम शुरू होते ही माल रोड हो या फिर इससे लगे होटल हर जगह पयर्टकों की चहलकदमी दिखाई देने लगी है. लेकिन पयर्टन के व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के चेहरे से रौनक गायब है जो पहले पयर्टन की शुरुआत होने के समय नजर आती थी.

अप्रैल महीने के शुरुआत में ही झील का जलस्तर कम होने लगा था. वर्तमान में झील का पानी अपने प्राकृतिक स्वरूप से सात फीट से भी नीच जा चुका है, जिसकी वजह से तल्लीताल दर्शन घर पार्क, फांसी गधेरे, माल रोड में स्थित पुस्तकालय, तल्लीताल में झील नियंत्रण कक्ष, मल्लीताल में बोट स्टैंड और नैना देवी मंदिर के समीप डेल्टा बन गए हैं. उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के झील नियंत्रण कक्ष के मुताबिक नैनी झील जब अपने प्राकृतिक स्वरूप में होती है, तब झील में अधिकतम 12 फुट पानी रहता है, जबकि नियंत्रण कक्ष द्वारा 11 अप्रैल को जब जलस्तर की जांच की गई, तो नैनी झील में सामान्य जल स्तर से माइनस तीन फुट(-3) ही पानी रह गया था. जिसकी वजह से नैनी झील अपने वास्तविक स्वरूप को खो चुकी है. ऐसे में जहां एक ओर झील सैलानियों के मन को नहीं भा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर पयर्टन व्यवसाय पर पड़ने की आशंका की वजह से पयर्टन व्यवसायी खासे परेशान हैं.

पयर्टन व्यवसायिओं का कहना है कि जलस्तर कम होने की वजह से व्यवसाय खासा प्रभावित होगा. सैलानी यहां रुकने की जगह आसपास के क्षेत्रों में रुकना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि पयर्टक झील को इस रूप में देखकर निराश होंगे. सबसे ज्यादा चिंता की वजह यह है कि नैनी झील से पानी न छोड़े जाने के बावजूद भी जलस्तर लगातार घटता जा रहा है. झील का जल आखिर सूख क्यों रहा है? सूखती झील की वजह से लोगों की चिंताएं उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है. लेकिन वहीं दूसरी ओर भीमताल, नौकुचियाताल और सातताल की झीलें लबालब हैं. ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि नैनी झील का पानी इतनी से तेजी कहां जा रहा है? नैनीताल के लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों को इस बात की जांच करानी चाहिए कि जब पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर झील का पानी कहां जा रहा है? पेयजल संकट को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा नैनी झील की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन यह भी कार्य धीमी गति से चल रहा है, इसे लेकर भी पयर्टन व्यवसायी चिंतित हैं. नैनी झील को बचाने के लिए समय रहते ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है. अगर नैनी झील की अनदेखी की गई, तो आने वाले दिनों में नैनी झील का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पानी को तरस रहे बुंदेलखंड में पानी की तरह बह रहा है पैसा

सट्टा लगा रहा है बट्टा

इसरार पठान

विकास को परिभाषित करने के लिए आज हम जिस आधुनिक तकनीक का हवाला देते हैं, उसी आधुनिकता को आधार बनाकर अपराधी गिरोह समाज को सट्टे की सौगात परोस रहे हैं. टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल के सहारे खेले जाने वाले इस खेल का वैसे तो समूचा देश ही शिकार है, पर बुंदेलखंड में इसकी जड़ें कुछ ज्यादा ही गहराई तक धंस चुकी हैं. बीते दिनों झांसी में हुआ गैंगवार, उसमें हुई एक सट्टा माफिया की मौत और इस हत्या में शामिल आरोपियों की अबु सलेम तक पहुंच होने जैसा खुलासा इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त है कि सूबे का सर्वाधिक पिछड़ा यह क्षेत्र अब सटोरियों की चंगुल में है. सट्टा कारोबार से जुड़े लोग यहां की मुफलिसी को कैश करा रहे हैं और तंगहाली के शिकार लोगों को रातों-रात लखपति बनाने का सब्ज़बाग दिखाकर उन्हें कंगाल कर रहे हैं.

इसमें कोई दो राय नहीं कि तरक्की में आधुनिक तकनीक का अहम रोल है, लेकिन आपराधिक तत्वों ने सोशल मीडिया जैसी तकनीक का सहारा लेकर जुए और सट्टे को नई पहचान दे दी है. इसके आकर्षण में फंसकर लोग अपना सब कुछ गंवा रहे हैं. जुए के गर्भ से पैदा हुए सट्टा कारोबार ने जिस तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं, वह चौंकाने वाला है. दुबई और मुम्बई से चला यह सट्टा कारोबार कब और कैसे बुंदेलखंड में जड़ें जमा गया, किसी को नहीं पता, लेकिन आज बुंदेलखंड में सट्टा कारोबार की एक बड़ी मंडी बन गई है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता. झांसी जैसे शहर से लेकर चित्रकूट के बीहड़ों तक इस खेल का बोलबाला है. यह खेल यहां किस पैमाने पर खेला और खिलाया जाता है, इसका खुलासा तब हुआ जब बीते छह अप्रैल को बुंदेलखंड का सट्टा किंग ठाकुर सुंदर मारा गया. देर रात झांसी शहर के थाना प्रेमनगर के अंतर्गत धुबियाना मुहल्ले में हुए घटनाक्रम को शुरुआती जांच में आपसी रंजिश बता रही पुलिस तब भौंचक्की रह गई जब इस गैंगवार के पीछे सट्टा कारोबार अहम वजह निकली. स्थानीय पुलिस के उस समय तो होश ही उड़ गए जब पकड़े गए हत्यारोपियों में से एक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के दाहिने हाथ कहे जाने वाले और सट्टा के जन्मदाता अबु सलेम से खुद की नजदीकी का खुलासा किया. बताते हैं कि अबु सलेम का यह करीबी तौफीक अहमद उर्फ आशिक उर्फ मराठा वर्ष 2006 से 2011 तक मुम्बई में उसकी कारिंदगी कर चुका है. मौजूदा समय में झांसी के सिलबटगंज में रह रहा मराठा मुम्बई से आने के बाद यहां के एक सट्टा माफिया जीशान खान के साथ जुड़ गया. वही जीशान खान जो इस शहर के सट्टा किंग कहे जाने वाले ठाकुर सुंदर सिंह को पटखनी देकर खुद झांसी में इस कारोबार पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहता था और उसने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर अपना लक्ष्य साध ही लिया.

बड़े बड़े लगा रहे हैं दांव

सट्टा ऐसा खेल है जिसमें खेलने वाले खिलाड़ियों के जीतने की संभावनाओं का प्रतिशत बेहद कम होता है. बूकी और उनके एजेंट पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों की तुलना में नए लोगों को अधिक तरजीह देते हैं. नए खिलाड़ी अनुमान पर खेलते हैं जबकि पुरानों की पैनी नजर इस खेल के आंकड़ों पर होती है. सट्टे का शौक केवल बिगड़ैल युवकों का नहीं बल्कि नेता, सरकारी बाबू, व्यापारी और राजपत्रित अधिकारियों तक का है जो इस खेल में बड़े-बड़े दांव लगा रहे हैं. बुंदेलखंड में करीब दो हजार से अधिक बूकी और पांच हजार से भी ज्यादा उनके एजेंट सक्रिय हैं जो लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं. बूकियों का ही अनुमान है कि बुंदेलखंड में ही प्रतिमाह दो से तीन करोड़ के बीच का सट्टा कारोबार होता है.

झांसी में घटी यह घटना नजीर है इस बात की कि बुंदेलखंड में सट्टा कारोबार किस पैमाने पर अपने पैर पसार चुका है और इस हत्याकांड में सत्ताधारी दल के प्रदेश सचिव उमाशंकर यादव के भाई किशन यादव की नामजदगी और अब तक उसका पकड़ा नहीं जाना साबित करता है कि इसमें सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण और स्वीकृति शामिल है. लिहाजा, इस धंधे को पुलिस की शह भी स्वाभाविक है. पुलिस को इस खेल की आमदनी से एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है. सट्टे के इस अवैध खेल का दायरा झांसी तक ही सीमित नहीं है. ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और महोबा जनपदों में भी यह खेल बड़े पैमाने पर खेला और खिलाया जा रहा है. आज बुंदेलखंड के हर शहर और कस्बे में ढेरों सट्टा बूकी मौजूद हैं. महोबा जनपद में तो कुछ बूकी बाकायदा ऑफिस खोलकर अपने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं. इस खेल की समझ रखने वाले लोगों की मानें तो सटोरिये मौसम पर, गाड़ियों के आवागमन टाईम पर, रास्ते पर चलते लोगों की एक्टीविटीज़ पर और क्रिकेट पर जब जहां जो मौका मिला उसपर दांव लगाने से नहीं चूकते. हालांकि क्रिकेट इनकी पहली पसंद है. सट्टा बूकी बताते हैं कि एशिया कप और टी-20 में अकेले बुंदेलखंड से लगभग सौ करोड़ का सट्टा कारोबार हो चुका है. वर्तमान में चल रहे आईपीएल में भी इतना ही होने की उम्मीद है. हालांकि उनके द्वारा बताया जाने वाला यह आंकड़ा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो है नहीं, फिर भी इससे धंधे के फैलाव का अंदाजा तो मिल ही जाता है. जिस बुंदेलखंड में तंगहाली और भुखमरी अपने चरम पर हो, वहां इस प्रकार के खेल को बढ़ावा दिया जाना क्या सही है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक बड़ा सन्नाटा है. आम जनता में और इस खेल की बलिवेदी में चढ़कर तबाह हो रहे युवकों के अभिभावकों में बेचैनी देखी जा सकती है. लेकिन स्वार्थी नेता और खुदगर्ज पुलिस के चेहरे पर शर्म का कोई भाव नहीं दिखता. यही वजह है कि बुंदेलखंड में सट्टे का कारोबार अब गैंगवार की शक्ल अख्तियार करने लगा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेहनतकश फाकाकशी में करोड़पति हो गए शोहदे

हाड़तोड़ मेहनत और इमानदारी से काम करने वालों की तुलना में जब शोहदों को आप लग्जरी कारों में देखें तो समझ लें कि वे सट्टा के धंधे से जुड़े हैं. सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों की बुंदेलखंड में यही पहचान है. महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन और झांसी में वातानुकूलित और लग्जरी कारों पर घूमते ऐसे न जाने कितने लोग आसानी से देखे जा सकते हैं जो कल तक दाने-दाने को मोहताज़ थे, पर आज शानदार इमारतों के मालिक बन चुके हैं. हैरत इस बात की नहीं कि ये रातों-रात पूंजीपति कैसे हो गए, बल्कि विचार करने योग्य बात यह है कि आम जनता और साधारण व्यापारियों को नियम तथा कानून का पाठ पढ़ाने वाले प्रशासनिक अधिकारी ऐसे धंधेबाजों पर निगाह क्यों नहीं रखते. बुंदेलखंड के शहर और कस्बों में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो इस प्रशासनिक मिलीभगत की खुलेआम तस्दीक करते हैं

बिहार में पूर्ण शराबबंदी से बेचैन पियक्कड़ों के लिए यूपी बनी मधु-नाला

बॉर्डर पर पीजिये छक कर साथ ले जाइये ढंक कर

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार में पूर्ण शराबबंदी से बेचैन बिहारी पियक्कड़ों के लिए यूपी की सीमा मधुशाला के बजाय मधु-नाला बन गई है. बिहार से लोग आते हैं, बॉर्डर पर छक कर पीते हैं और साथ में ढेर सारी शराब छुपा कर ले भी जाते हैं. उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी हो, लेकिन शराब के शौकीनों ने इसका तोड़ ढूंढ़ निकाला है. इसके लिए उन्हें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं काफी मुफीद लग रही हैं जहां आकर वे अपना गला भी तर कर रहे हैं और अपने साथ स्टॉक भी ले जा रहे हैं. कभी यह हाल था कि बिहार निर्मित पाउच वाली शराब से यूपी के शराब कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा था. अब वह बिल्कुल उल्टा हो गया है. अब बिहार में लागू शराबबंदी से उत्तर प्रदेश के शराब कारोबार में इजाफा होने लगा है. उत्तर प्रदेश के बिहार से लगने वाले सीमाई क्षेत्रों में यूपी की शराब की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है. शराब की तस्करी बेतहाशा बढ़ गई है.

बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही बिहार में शराब पर रोक लगाने की बात कही थी और चुनाव सम्पन्न होने के बाद पुनः सत्ता में आने पर एक अप्रैल 2016 से बिहार में शराब पर पूर्ण पाबंदी का ऐलान कर दिया. महिलाओं ने खास तौर पर इस फैसले का जोरदार स्वागत किया. शराबबंदी से सरकारी राजस्व को भले ही नुकसान पहुंचा, लेकिन लोगों का जीवन बचाने की राह आसान हो गई. लेकिन पियक्कड़ों ने इसकी भी काट निकाल ली. अब वे यूपी के बॉर्डर का रुख करने लगे हैं. बिहार के पियक्कड़ों के लिए बिहार से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर वगैरह शराब पाने का बेहतर जरिया बन रहे हैं. बिहारी पियक्कड़ों की भीड़ यूपी की ओर आती देख यूपी के शराब ठेकेदारों, आबकारी और पुलिस अधिकारियों की तो चांदी हो गई है. यूपी के आबकारी विभाग के ही अफसर बताते हैं कि पेटियां भर-भर कर शराब सड़क मार्ग या सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण रास्तों से बिहार जा रही हैं. गाजीपुर जिले का गहमर, देवल, सायर भदौरा जैसा इलाका शराब के इस अवैध कारोबार का अड्डा बन गया है. गाजीपुर के ही भांवरकोल और करीमुद्दीनपुर में भी शराब की खपत काफी बढ़ गई और शराब की तस्करी भी खूब हो रही है. चंदौली जिले के इलिया, बरहुआं, कुशहां, महंजी जिगना, सैयदराजा, चिरईगांव, मानिकपुर, नौबतपुर आदि इलाकों से भी कर्मनाशा नदी को पार कर शराब की तस्करी की जा रही है. बलिया जिले के भरौली, नरही, गोलंबर इलाके शराब कारोबार से गुलजार हैं, जहां से गंगा नदी के पार बिहार में शराब पहुंचाई जा रही है. सोनभद्र जिले से लगने वाले बिहार की सीमा वाले क्षेत्र में भी शराब का धंधा करने वालों की लॉटरी खुल गई है. बिहार के शराब माफिया यूपी के लाइसेंसी शराब के ठेकेदारों और दुकानदारों से साठगांठ कर लग्जरी वाहनों से शराब की तस्करी करा रहे हैं. यूपी की शराब को महंगे दामों पर बिहार में बेचा जा रहा है. बिहार और यूपी को जोड़ने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी यूपी की शराब की बिहार में तस्करी का जरिया बन रही हैं. बिहार की तरफ से पियक्कड़ों की टोलियां यूपी आती हैं और अपने बैगों-अटैचियों में भर कर शराब ले जाती हैं. बिहार के बक्सर के रास्ते पियक्कड़ों की टोलियों को गाजीपुर के भरौरा, गहमर, दिलदारनगर, जमानियां आदि स्टेशनों पर उतरते आराम से देखा जा सकता है. वे यूपी आकर शराब पीते हैं और साथ में ले जाते हैं. रघुनाथपुर, चौसा, डुमरांव, बरूना, टुड़ीगंज कारीसाथ, बिहिया, बनाही आदि स्टेशनों से उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले कुछ खास किस्म के लोगों को स्थानीय लोग बहुत आराम से पहचान रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी सरकार को फायदा ही फायदा

बिहार में शराबबंदी से पियक्कड़ों में बेचैनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और शराब के कारोबारी बड़े चैन में हैं. वे खूब मुनाफा कमा रहे हैं. यूपी सरकार ने शराब बिक्री से अर्जित होने वाले राजस्व का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया है. पिछले वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 127 करोड़ था, लेकिन इस वर्ष (2016-17)राजस्व लक्ष्य बढ़ा कर 140 करोड़ कर दिया गया है. यूपी के सीमाई जिलों में बीयर और देसी-विदेशी शराब विक्रय के जो लक्ष्य रखे जाते थे उसे पूरा करने में पहले जद्दोजहद करनी पड़ती थी, अब वह बात नहीं रही, अब तो माल ही कम पड़ने लगा है. अब तो शराब कारोबारी भी प्रसन्न हैं और अधिकारी भी खुश हैं.

कहानियों का नया बाज़ार

अनंत विजय

सनी लियोनी और साहित्य. सुनकर कुछ अजीब लगता है, क्योंकि एक एडल्ट फिल्मों की नायिका जो इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो लगातार चार साल तक गूगल में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत रही हों, उनका साहित्य से क्या लेना देना. परन्तु सनी लियोनी अब कहानीकार के तौर पर सामने आई हैं. पिछले दिनों भारतीय प्रकाशन जगत में एक नए डिजीटल पब्लिशिंग हाउस ने दस्तक दी है, नाम है जगरनॉट. उसने इसकी शुरुआत सनी लियोनी की कहानियों से की है. जगरनॉट के मोबाइल एप्प पर अगले दस दिनों तक हर रोज रात दस बजे सनी लियोनी की एक नई कहानी अपलोड की जाएगी. सनी लियोनी के कहानी संग्रह का नाम स्वीट ड्रीम्स है और इसको उनकी छवि के हिसाब से ही प्रकाशक ने प्रचारित भी किया है. दरअसल, खबरों के मुताबिक प्रकाशन संस्थान ने सनी लियोनी को अपने लांच के लिए साइन किया था और उसकी तारीख को ध्यान में रखकर कहानी संग्रह तैयार करवाया गया था. सनी लियोनी की कहानियों में प्यार होगा, रोमांस होगा और डिजायर भी होगा. इसके अलावा जगरनॉट के लेखकों में विलियम डेलरिंपल, श्वेतलाना एलेक्सविच, अरुंधति रॉय, पोल स्टार प्रशांत किशोर और हुसैन हक्कानी जैसे बड़े नाम शामिल किए गए हैं. अभी इस डिजीटल प्रकाशन गृह की शुरुआत करीब सौ टाइटल के साथ की गई है और इसकी भविष्य की योजना में और भी किताबें हैं. सौ में से करीब पचास किताबें उन्होंने खुद तैयार की हैं और बाकी पचास अन्य प्रकाशकों के साथ साझा समझौते के तहत जारी की गई हैं. जगरनॉट की योजना के मुताबिक वो पहले ईफॉर्मेट में किताबें प्रकाशित करेंगे और फिर पाठकों के रेस्पांस के हिसाब से उसको किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे. भारतीय प्रकाशन जगत के लिए यह ठीक उल्टी प्रक्रिया है. यहां तो पहले कोई भी कृति किताब के रूप में प्रकाशित होती है फिर बाद में उसका डिजीटल संस्करण जारी किया जाता है या ज्यादा से ज्यादा दोनों एक साथ ही जारी किए जाते हैं.

जगरनॉट का दावा है कि वो भारत की पहली एप्प आधारित डिजीटल प्रकाशन गृह है जो पाठकों को इतनी कम कीमत पर किताबें उपलब्ध करवा रही है. इस महात्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पाठकों के लिए पंद्रह रुपये रोज या फिर 299 रुपये महीने की सदस्यता पर किताबें उपलब्ध की जाएंगी. अगर पाठक सदस्यता नहीं लेना चाहे तो 99 रुपये में किताबें उपलब्ध हैं जिसे डाउनलोड किया जा सकता है. दरअसल, यह कहा जा सकता है कि प्रकाशन की दुनिया का ये स्टार्टअप है जिसने मोबाइल यूजर के लिए उसकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उस फॉर्मेट में किताबों को पेश करने की योजना बनाई है. इस प्रकाशन गृह के पीछे पेंग्विन प्रकाशन की पूर्व एडिटर इन चीफ चिकी सरकार और उनकी सहयोगी दुर्गा रघुनाथ हैं. अब तक इस स्टार्टअप में करीब पंद्रह करोड़ का निवेश हो चुका है. निवेशकों में नंदन नीलेकणी, फैब इंडिया के विलियम बिसिल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के भारत प्रमुख नीरज अग्रवाल प्रमुख हैं. जगरनॉट का मानना है कि मोबाइल एप्प का जो इकोसिस्टम है वो पारंपरिक प्रकाशन से कम खर्चे पर चलता है. कम खर्चे की बात इस वजह से होती है कि ईबुक्स को एक बार तैयार करवाने में खर्च होता है बाकी तो उसके बाद जितने भी डाउनलोड होते हैं वो मुनाफा ही होता है. किताबों की तरह यहां नहीं है कि जितनी भी प्रति बिकेगी सबकी कुछ न कुछ लागत होगी. संभव है चिकी सरकार का अलग गणित हो, लेकिन मोबाइल एप्प आधारित सभी कारोबार का इकोसिस्टम बेहद खर्चीला माना जाता है. स्टार्टअप बिजनेस के लिए किसी भी तरह का मोबाइल एप्प बनवाना बहुत आसान और सस्ता है, लेकिन उस मोबाइल एप्प को डाउनलोड करवाना और फिर उसको रिटेन करवाना बहुत ही मुश्किल है. गूगल और फेसबुक भी छह सौ रुपये में एक ग्राहक बेचते हैं लेकिन उसको रिटेन करवाने का कोई फॉर्मूला उनके पास भी नहीं है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि एक मोबाइल एप्प को डाउनलोड करवाने का खर्च लगभग पांच सौ रुपये आता है और उसको ग्राहक अपने मोबाइल में कब तक रखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. भारत में मोबाइल के ग्राहकों की विशाल संख्या को देखते हुए वेंचर कैपिटलिस्टों को और स्टार्टअप को यहां एक बड़ा बाजार नजर आता है. वे भूल जाते हैं कि ज्यादातर स्मार्टफोन में मेमोरी बहुत कम होती है और ग्राहक अपने मोबाइल में खरीदारी के एप्प को ज्यादा से ज्यादा दो की संख्या में रखते हैं, नए डाउनलोड करते हैं तो पुराने हटा देते हैं. ये पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन की संख्या पर भी निर्भर करता है. जगरनॉट ने तो मोबाइल वैलेट कंपनी पेटीएम के साथ भी करार किया है. इस करार के मुताबिक कोई भी ग्राहक जिसके पास पेटीएम का एप्प है वो उसके जरिए भी जगरनॉट के एप्प तक पहुंच सकता है. जगरनॉट को पेटीएम के मोबाइल ग्राहकों की संख्या पर भी भरोसा है कि उनके जरिए किताबों की बिक्री हो सकेगी. यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मोबाइल वैलेट के लोग कितना पैसा किताबों के लिए निकालते हैं. दरअसल, हमारे देश में हाल के दिनों में ग्रॉसरी से लेकर सब्जी तक के स्टार्टअप खुलते जा रहे हैं और उसी रफ्तार से बंद भी हो रहे हैं. मोबाइल एप्प पर आधारित इस तरह की ज्यादातर कंपनियां घाटे में चल रही हैं. घाटे में चल रही इन कंपनियों के लिए वेंचर कैपटलिस्ट की पूंजी प्राणवायु का काम तो करती है. लेकिन ये दीर्घकालीन हल नहीं देते हैं, क्योंकि वेंचर कैपटलिस्ट पहली बार तो इक्विटी से अपना घाटा पूरा करते हैं और फिर कंपनी की वैल्यूएशन के आधार पर उसको मौका मिलते ही बेच देते हैं. किसी भी कारोबार को शुरू करने और उसकी सफलता के लिए माना जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में औरों से बेहतर जानकारी हो, आपको अपने ग्राहकों के स्वभाव और उनकी खरीदारी के पैटर्न का बेहतर अंदाजा हो और कारोबार को सफल करने का ख्वाब हो. लेकिन स्टार्टअप में एक और चीज जोड़ी जानी चाहिए कि कारोबारी को इस बात का भी इल्म हो कि उसके ट्रांजेक्शन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं. चिकी सरकार को अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर ज्ञान है और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को खरीदारी के पैटर्न का अंदाज है. विजय शर्मा भी जगरनॉट के सलाहकार हैं तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये स्टार्टअप सफल होगा. साहित्य जगत के लिए भी इसका सफल होना बेहतर होगा.

दिसंबर 2015 तक भारत में मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले तीस करोड़ छह लाख ग्राहक थे और इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक यह 21 फीसदी की दर से बढ़कर जून 2016 तक 37 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा. मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल के विस्तार को देखते हुए जगरनॉट का बिजनेस मॉडल बेहतर कर सकता है बशर्ते कि इसका खूब प्रचार प्रसार हो. जगरनॉट का मानना है कि जिस तरह से मोबाइल का विस्तार हो रहा है उससे यह संख्या और भी बढ़ सकती है. जगरनॉट जून में हिंदी की किताबें भी ईफॉर्मेट में पेश कर रही है. हिंदी के प्रकाशक वाणी प्रकाशन की कॉपीराइट की निदेशक अदिति माहेश्वरी जगरनॉट का स्वागत करती हैं और कहती हैं कि यह भारतीय भाषाओं के लिए अच्छी बात है. नए-नए फॉर्मेट में किताबें आ रही हैं और साथ ही पूंजी निवेश भी हो रहा है. पर मुझे लगता है कि पाठकों को मोबाइल के एप्प तक पढ़ने के लिए लाना बहुत मुश्किल काम है. इस तरह का काम काफी सालों से डेलीहंट नाम की कंपनी करती आ रही हैं जो बेहद कम मूल्य पर भारतीय भाषाओं की पुस्तकें बेच रही हैं. उनके बिजनेस मॉडल का पता नहीं है कि वो मुनाफे में है या नहीं. प्रकाशन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत में किताबों को लेकर जो प्यार और अपनापन पाठकों के दिलो दिमाग तक छाया हुआ है वह अहसास उनको वर्चुअल बुक्स से नहीं मिलता है यही वजह है कि भारत में अब तक ईबुक्स का बहुत बड़ा बाजार नहीं बन पाया है. इस साल जनवरी में दिल्ली में हुए विश्व पुस्तक मेले में पाठकों की उमड़ती भीड़ ने भी साबित किया है कि पुस्तकों के प्रति पाठकों का प्यार कम नहीं हुआ है. अब पुस्तक प्रेमियों के समाज को सनी लियोनी जैसी सेलिब्रिटी द्वारा ईफॉर्मेट में ले जाना दिलचस्प होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

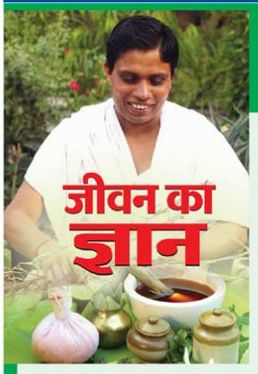

अश्वगन्धा

पिछले अंक से आगे

हृदय रोग :

❖ **हृदय शूल–** 2 ग्राम अश्वगन्धा मूल चूर्ण को जल के साथ सेवन करने से वातज-शूल में लाभ होता है.

❖ अश्वगन्धा चूर्ण में बहेड़े के चूर्ण को समान मात्रा में मिलाकर 2-4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ लेने से उदरकृमियों का शमन होता है.

उदर रोग :

❖ **उदर कृमि–** अश्वगन्धा चूर्ण में समान भाग गिलोय का चूर्ण मिलाकर 5-10 ग्राम मधु के साथ नियमित सेवन करने से उदरकृमियों का शमन होता है.

❖ **बद्धकोष्ठ–** 2 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण को गर्म जल के साथ सेवन करने से बद्धकोष्ठता मिटती है.

प्रजनन-संस्थान रोगः

❖ 20 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण, एक लीटर जल तथा 250 मिली गोदुग्ध, तीनों को मंद अग्नि पर पकाकर, जब दूध मात्र शेष रह जाए, तब इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिलाकर मासिक धर्म के शुद्धिस्नान के तीन दिन बाद, तीन दिन तक सेवन करने से यह गर्भधारण में सहायक होता है.

❖ अश्वगन्धा चूर्ण को गाय के घी में मिलाकर मासिक-धर्म स्नान के पश्चात् प्रतिदिन गाय के दूध के साथ या ताजे जल से 4-6 ग्राम की मात्रा में एक माह तक निरंतर सेवन करने से यह गर्भधारण में सहायक होता है.

❖ **गर्भस्तम्भनार्थ–** बार-बार गर्भपात होने पर अश्वगन्धा और सफेद कटेरी की जड़ इन दोनों के 10-10 मिली स्वरस को प्रथम मास से पांच मास तक सेवन करने से अकाल में गर्भपात नहीं होता है.

❖ **प्रदर–** 2-4 ग्राम अश्वगन्धा मूल चूर्ण में मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से प्रदर में लाभ होता है.

❖ अश्वगन्धा, तिल, उड़द, गुड़ तथा घृत को समान मात्रा में लेकर लड्डू बनाकर खिलाने से प्रदर में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग :

❖ **गठियावात–** अश्वगन्धा के पंचांग को कूटकर, छानकर, 2-4 ग्राम तक सेवन करने से गठियावात का शमन होता है या गठिया में अश्वगन्धा के 30 ग्राम ताजा पत्तों को, 250 मिली पानी में उबालकर, जब पानी आधा रह जाए, तो छानकर पी लें. एक सप्ताह पीने से ही गठिया रोगी बिल्कुल अच्छा हो जाता है तथा इसका लेप भी बहुत लाभदाय है.

❖ 2 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण को, सुबह शाम गर्म दूध या पानी के साथ खाने से गठिया के रोग में विशेष लाभ होता है.

❖ **कटिशूल–** 2-5 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण को गोघृत या शक्कर के साथ चाटने से कटिशूल और निद्रानाश में लाभ होता है.

❖ **संधिवात–** तीन ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण में तीन ग्राम घी तथा एक ग्राम शक्कर मिलाकर सुबह शाम खाने से संधिवात का शमन होता है.

❖ अश्वगन्धा की 15 ग्राम कोंपले या कोमल पत्र लेकर 200 मिली जल में उबालें, जब पत्ते गल जाएं या नरम हो जाएं, तो छानकर गर्म-गर्म 15-20 मिली मात्रा में 2-4 दिन तक सुबह और शाम पीने से कफजन्य कास तथा संधिवात का शमन होता है.

❖ अश्वगन्धा के मूल के क्वाथ और कल्क में चौगुना मात्रा में घी मिलाकर पकाकर सेवन करने से वात-व्याधि का शमन होता है.

त्वचा रोग :

❖ **विसर्प–** अश्वगन्धा मूल को पीसकर, गुनगुना करके लेप करने से विसर्प में लाभ होता है.

❖ **शस्त्रक्षत–** क्षत होने पर या चोट लगने पर अश्वगन्धा के चूर्ण में गुड़ या घी मिलाकर दूध का सेवन करना हितकर है.

❖ **त्वचा रोग–** अश्वगन्धा के पत्र कल्क का लेप त्वचागत कृमि, मधुमेह-जन्य व्रण, फिरंग जन्य व्रण, शोथ तथा अन्य व्रणों का शीघ्र निवारण करता है. पत्र-क्वाथ से प्रक्षालन तथा स्वेदन करना भी लाभप्रद है.

❖ **रक्तविकार–** अश्वगन्धा चूर्ण में समभाग चोपचीनी चूर्ण अथवा चिरायता चूर्ण मिलाकर 3-5 ग्राम की मात्रा में सुह और शाम सेवन करने से रक्तज विकारों में लाभ होता है.

सर्वशरीर रोगः

❖ **दौर्बल्य–** 2-4 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण को एक वर्ष तक यथाविधि सेवन करने से शरीर रोग रहित हो जाता है.

❖ 10-10 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण, तिल व घी को लेकर और तीन ग्राम मधु मिलाकर नित्य शरद ऋतु में 1-2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से शरीर पुष्ट हो जाता है.

❖ 6 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण में समान भाग मिश्री और मधु मिलाकर इसमें 10 ग्राम गाय का घी मिलाएं, इस मिश्रण को 2-4 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम शीतकाल में 4 मास तक सेवन करने से शरीर का पोषण होता है.

❖ 3 ग्राम अश्वगन्धा मूल चूर्ण को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ताजे दूध से, वात प्रकृति वाला शुद्ध तिल से और कफ प्रकृति का व्यक्ति गर्म जल के साथ एक वर्ष तक सेवन करे, तो निर्बलता दूर होकर सब व्याधियों का नाश होता है.

❖ 20 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण, तिल 40 ग्राम और उड़द 169 ग्राम, इन तीनों को महीन पीसकर इसके बड़े बनाकर ताजे-ताजे एक मास तक सेवन करने से दौर्बल्य का शमन होता है.

❖ अश्वगन्धा चूर्ण और चिरायता बराबर-बराबर लेकर खरल करके रखें. इस चूर्ण को 2-4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से दौर्बल्य का शमन होता है.

❖ **ज्वर–** 2 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण तथा 1 ग्राम गिलोय सत्, दोनों को मिलाकर प्रतिदिन शाम को गुनगुने पानी के साथ खाने से जीर्ण वातज्वर का शमन होता है.

❖ **सर्वरोग–** 250 मिग्रा गिलोय सत् को 2 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण के साथ मिलाकर शहद के साथ सेवन करने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं.

अहितकर : उष्ण प्रकृति वालों के लिए.
निवारण : गोंद, कतीरा एवं घी.
प्रयोज्यांग : पत्र, मूल, फल एवं बीज.
मात्रा : मूल चूर्ण 2-4 ग्राम. क्वाथ 10-30 मिली अथवा चिकित्सक के परामर्शानुसार. ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

आदमी अपने संस्कार के अनुसार सुख या दुःख को ढूंढ़ता है

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

शत्रुता का प्रतिकार

जीवन में कुछ लोगों के बहुत से मित्र होते हैं और अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके मित्र कम और न चाहते हुए भी अनेक शत्रु होते हैं. शत्रुता से त्राण पाने के लिए वे छटपटाते रहते हैं और बाह्य सहायता की उम्मीद रखते हैं. इस सम्बन्ध में आपकी क्या धारणा है?

हमारे मित्र, हमारे शत्रु- सब हमारे कर्मफल के परिणाम हैं. जैसे अपना बच्चा कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, मधुर स्वभाव का हो या उद्दंड-है तो हमारा ही. वैसे ही जीवन में चाहे मित्र हों, चाहे शत्रु, सब कुछ साथ ही झेलना है. मित्रता से हम स्वयं आनंदित होते हैं और शत्रुता के प्रतिकार के लिए दूसरे से अपेक्षा करते हैं. किसी और से सहायता क्यों मांगें- अपने कर्मफल से मुक्ति के लिए?

प्रार्थना का महत्व

यदि जीवन में सब कुछ पूर्व नियति के अनुसार ही हो रहा है, तो हमारी प्रार्थना आदि का क्या लाभ है?

ईश्वर तो सदैव भक्तों के कल्याण के कार्य में संलग्न हैं. वह सर्वशक्तिमान हैं. उनकी शक्ति असीमित है. वे प्रकृति के नियमों के भीतर और उनके बाहर भी कार्य करने में सक्षम हैं. भक्त की भाव-दशा एवं अवस्था को देखते हुए वह प्राकृतिक नियमों में भी परिवर्तन लाकर भक्त की सहायता कर सकते हैं.

प्रतिक्रिया या सहनशीलता?

जीवन में अक्सर हमारे मन को प्रतिशोध की भावना घेरे रहती है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं. हमें लगता है कि दूसरे हम पर ज्यादती कर रहें हैं. ऐसी स्थिति में अनाचार को सहन करना अच्छा है या दूसरे को ठीक करना?

हम किसी को ठीक करने वाले कौन होते हैं? सहन करना निश्चित रूप से श्रेयस्कर है. शत्रुता के जिस भाव से ग्रस्त होकर हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं, उससे क्रिया-प्रतिक्रिया का जो क्रम शुरू होता है, वह जीवन को संघर्षमय बना देता है. हम यह तर्क करते हैं कि सहन करने में भी पीड़ा है, किन्तु यह भूल जाते हैं कि बदला लेने में उससे भी ज्यादा कष्ट है. सहन करने का दुःख, क्रिया-प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न संघर्ष एवं दुःख की तुलना में निश्चित रूप से कम है. खुद ही विचार करके देखना होगा कि आप सहन करके कम दुःख चाहते हैं या प्रतिक्रिया करके अधिक दुःख भोगने के पक्षपाती हैं.

भौतिकता की चाहत और दुःख

सब कुछ होकर भी संसार में आज आदमी इतना दुखी और परेशान क्यों हैं?

सब कुछ अगर हर व्यक्ति के पास होता, तो वह दुःखी क्यों होता? इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके पास सब कुछ हो. वास्तव में जिसको हम अपने संकुचित दृष्टिकोण से सब कुछ समझते हैं, वह मूल्यहीन है, अर्थहीन है और हमारे जीवन के स्वकाल तक सीमित है. आदमी तभी दुखी होता है जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, चाहे वह भौतिक हों या अध्यात्म-संबंधी हों. पर इन दोनों स्थितियों में दुखी होना एक प्रकार का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग या ईश्वर-अनुभूति की चाहत रख रहा हो और उस दिशा में प्रयास कर रहा हो, वह भौतिक चीजों की कमी से कभी दुखी न होगा और जो भौतिकवाद से अपनी चाहत को पूरा करना चाहता हो, वह चाहे कितनी भी भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर ले, उसे आध्यात्मिक जीवन की सरलता, निःशंकता और आनंद का अनुभव न होगा. आदमी अपने संस्कार के अनुसार सुख या दुःख को ढूंढ़ता है, जब से यह मानव-सभ्यता बनी है, तभी से यही चला आ रहा है. वस्तुतः आदमी की सुख-दुःख की परिभाषा उसके अपने अनुसार है और अपनी अनुभूति के अनुरूप है. हां, यदि कोई चाहे कि उसे दुःख से निकलने के लिए सही मार्ग मिल जाए, तो उसे सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा. ■

> वस्तुतः आदमी की सुख-दुःख की परिभाषा उसके अपने अनुसार है और अपनी अनुभूति के अनुरूप है. हां, यदि कोई चाहे कि उसे दुःख से निकलने के लिए सही मार्ग मिल जाए, तो उसे सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आईपीएल का विवादों से नाता

देश में सूखा बीसीसीआई पैसों का भूखा

तरुण फोर

हाल ही में खबर आई कि आईपीएल के अगले सीजन का आयोजन भारत के बाहर हो सकता है. बीसीसीआई के महासचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईपीएल की संचालन परिषद इस बात पर विचार विमर्श करने वाली है कि आईपीएल के दसवें सीजन का आयोजन विदेश में किया जाए या नहीं. उनके यह कहते ही अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया. साल 2009 और 2014 में देश में लोकसभा चुनाव की वजह से सरकारें मैच के दौरान खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं थीं. इसलिए आईपीएल का आयोजन 2009 में दक्षिण अफ्रीका में और 2014 में 15 दिनों के लिए यूएई में किया गया. लेकिन इस बार आईपीएल के विदेश जाने का कारण दूसरा है. आईपीएल के मौजूदा सीजन में महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल मैचों का आयोजन महाराष्ट्र से बाहर करने का आदेश दिया. इससे आईपीएल के निर्धारित कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल करना पड़ा. देश के अन्य भागों में भी सूखे की वजह से स्थिति खराब हो रही है. देश का बड़ा इलाका सूखे की चपेट में है. महाराष्ट्र से मैचों को जयपुर स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने दखल दिया और कहा कि राजस्थान भी सूखे से जूझ रहा है ऐसे में वहां मैचों को क्यों स्थानांतरित किया गया.

> “अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईपीएल की संचालन परिषद इस बात पर विचार विमर्श करने वाली है कि आईपीएल के दसवें सीजन का आयोजन विदेश में किया जाए या नहीं. उनके यह कहते ही अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया.”

ऐसे में बीसीसीआई को बेहद जटिल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. यदि बार-बार मैचों को उसे अदालत के आदेश पर स्थानांतरित करना पड़ा तो उसके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी. क्योंकि नए वेन्यू का चुनाव करना और वहां तैयारियों को अंतिम रूप देना भी आसान काम नहीं है, ऐसे में यदि उस जगह भी अदालत ने मैचों के आयोजन पर दखल देकर रोक लगाई तो उसके पास और कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा. बीसीसीआई किसी तरह इस सीजन को समाप्त करना चाह रही है और आग लगने से पहले कुआं खोदने की कोशिश कर रही है. बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को लगता है कि यदि इस साल भी बारिश नहीं होगी तो आईपीएल का अगले सीजन का आयोजन वह भारत में नहीं कर पाएगी. इससे उसे बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसे में वह अगले सीजन का आयोजन देश के बाहर करने की योजना बना रही है, जिससे अगले सीजन उसे सूखा और उसके बाद की स्थिति से दो चार न होना पड़े.

विदेशी धरती पर आईपीएल के आयोजन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है. साल 2009 में आईपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था. तब मैचों के आयोजन के स्तर पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आयोजन के बाद आईपीएल के तत्कालीन कमिश्नर ललित मोदी के ऊपर वित्तीय धांधली के आरोप लगे. उसके बाद उन्हें आईपीएल कमिश्नर के पद से हटा दिया गया. वह उसके बाद लंदन चले गए और भारत वापस नहीं लौटे. 2009 में ही आईपीएल में फिक्सिंग होने की संभावना जताई गई थी. लेकिन देश के बाहर आयोजन होने की वजह से कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिल सके. विदेश में आयोजन से फ्रेंचाइजी को टिकटों की बिक्री से होने वाला फायदा भी नहीं मिल सका. क्योंकि घरेलू मैदान पर उन्हें मैचों के आयोजन से आमदनी हो जाती थी. इस तरह के कई अन्य मसले थे. आईपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के सामने आने के बाद साल 2014 में यूएई में 15 दिनों के लिए आईपीएल मैचों का आयोजन हुआ. भारत ने 1999 के मैच फिक्सिंग की जांच के बाद शारजाह और यूएई में कोई भी मैच नहीं खेला था, क्योंकि वहां क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहीम से जुड़े होने की बात सामने आई थी. इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि यदि वहां आईपीएल का आयोजन होगा तो मैच फिक्सिंग हो सकती है. हालांकि स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच उस समय चल रही थी इसलिए आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने फूंक-फूंक कर कदम रखे. चुनावों के बाद आईपीएल वापस भारत लौट आया.

लेकिन अब जब आईपीएल को विदेश ले जाने की बात हो रही है, तब फिक्सिंग के आरोप में खिलाड़ियों, टीमों (चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स) और उनके मालिकों पर पाबंदी लग चुकी है. अगला सीजन मौजूदा आईपीएल सेटअप का अंतिम सीजन होगा. इसके बाद खिलाड़ियों और टीमों की नए सिरे से नीलामी होगी. ऐसे में टीम के मालिकों के पास पैसे कमाने का अंतिम मौका है. हो सकता है अगली बार वे टीम खरीदने में कामयाब हों या न हों. ऐसे में यदि भारत में अगले सीजन के आयोजन पर तलवार लटकी रहेगी तो टीम के मालिकों की नींद भी हराम रहेगी. उन्हें सूखा और देश की परेशानियों से ज्यादा अपना नुकसान नज़र आ रहा है. ऐसे में बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के ऊपर उनका भी दबाव होगा कि अगले सीजन के आयोजन में किसी भी तरह की बाधा न आए. इसलिए भी बीसीसीआई को विदेश में आईपीएल के आयोजन का निर्णय लेना पड़ सकता है.

बीसीसीआई को विदेश जाना ही एकमात्र समाधान के रूप में दिखाई पड़ रहा है. लेकिन वह चाहे तो अगले सीजन के लिए ऐसे वेन्यू का चुनाव कर सकती है जहां पानी की समस्या न हो. उसके पास अभी वक्त है बारिश होगी या नहीं इस बात का पता तो किसी भी सूरत में जुलाई-अगस्त तक चल जाएगा. यदि जिन राज्यों में बेहतर बारिश हुई हो उनका चयन वेन्यू के रूप में किया जाएगा तो किसी को भी समस्या नहीं होगी और बीसीसीआई की साख भी बच जाएगी और देश का पैसा भी देश में रह जाएगा. जिससे सूखा प्रभावित राज्यों की मदद भी खेल के माध्यम से हो सकेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

मैरीकॉम रिंग से पहुंची राज्यसभा

मैरीकॉम के साथ कामयाबी का एक नया अध्याय जुड़ गया है. लेकिन उनके सपनों का सफ़र जारी है. मैरीकॉम ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी.

मणिपुर की ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज़ एमएसी मैरीकॉम को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है. मैरीकॉम पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है. साथ ही भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और भाजपा नेता नवजोत सिंह सिद्धू को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है. मैरीकॉम के साथ कामयाबी का एक नया अध्याय जुड़ गया है. लेकिन उनके सपनों का सफर अभी जारी है. मैरीकॉम ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी. मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और आने वाली क्वालीफाइंग प्रतियोगिता पर फोकस कर रही थी. इसमें कोई शक नहीं कि लंदन ओलंपिक की पदक विजेता मैरीकॉम के लिए उनकी सबसे बड़ी चुनौती बाकी है. मैरीकॉम के लिए रियो ओलंपिक आखिरी ओलंपिक खेल हो सकता है. मई में अस्ताना (कज़ाकिस्तान) में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के जरिए मैरीकॉम रियो का टिकट हासिल करना चाहती हैं और इसके लिए उनके पास समय बहुत कम है. ओलंपिक के लिए मैरीकॉम कड़ी मेहनत कर रही हैं. उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रियो का टिकट हासिल हो जाएगा और वह अपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना पूरा कर लेंगी. मैरीकॉम कहती हैं कि वो अपनी कमज़ोरियों पर खास तौर पर काम कर रही हैं. उन्हें उम्मीद है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सलमान को गुडविल अम्बैसेडर बनाने पर भड़के खिलाड़ी

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का विवादों से गहरा नाता है. लेकिन इस बार विवाद उनकी किसी फिल्म को लेकर नहीं हुआ, बल्कि अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक में उनको भारतीय दल का गुडविल अम्बैसेडर बनाए जाने की वजह से हुआ है. पहले रेसलर (पहलवान) योगेश्वर दत्त नाराज हुए तो अब महान स्प्रिंटर (धावक) मिल्खा सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं. जबकि आईओए और अन्य एथलीटों ने इस फैसले का समर्थन किया है.

लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर ने ट्वीट किया कि अम्बैसेडर का क्या काम होता है कोई मुझे बता सकता है क्या? क्यों पागल बना रहे हो देश की जनता को. हरियाणा के इस पहलवान ने सलमान के लिए कहा कि कहीं भी जाकर

अपनी फिल्म का प्रमोशन करें, इस देश में अधिकार है, लेकिन ओलंपिक फिल्म प्रमोशन की जगह नहीं है.

योगेश्वर दत्त ने बिना सलमान का नाम लिए कहा कि पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह जैसे बड़े स्पोर्टस स्टार हैं, जिन्होंने कठिन समय में देश के लिए मेहनत की है, लेकिन खेल के क्षेत्र में इस अम्बैसेडर ने क्या किया?

वहीं मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सलमान खान के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन आईओए का फैसला गलत है और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए. ऐसा पहली बार है जब मैं देख रहा हूं कि ओलंपिक के लिए किसी बॉलीवुड अभिनेता को गुडविल अम्बैसेडर बनाया गया हो. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी बॉलीवुड ने किसी खिलाड़ी को अपने बड़े कार्यक्रम के लिए अम्बैसेडर बनाया है?

आईओए के उपाध्यक्ष तरलोचन सिंह ने कहा कि जब जानी-मानी हस्तियां लोगों से मदद करने की अपील करती हैं तो साधारण-सी बात है कि हमें और प्रचार मिलता है, जो खेल के लिए अच्छा है. युवाओं में प्रवृत्ति है कि वे इस तरह की फिल्मी हस्तियों से प्रेरणा लेते हैं. ■

रईस की लैला बनकर खुश हैं सनी

शाहरुख़ के साथ काम करना एक बेहतरीन अनुभव है. ऐसे अवसर के लिए मैं हर दिन दुआ मांगती थी. इतने बड़े स्टार के साथ काम करना सपने से कम नहीं था. काश ऐसा मौका दोबारा मिले.

जिस्म-2 से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने वाली सनी लियोनी का शाहरुख़ खान के साथ काम करने का सपना सच हो गया है. सनी लियोनी शाहरुख़ खान की आने वाली फ़िल्म रईस के गाने लैला ओ लैला में नज़र आएंगी. उन्होंने कहा कि शाहरुख़ खान के साथ काम करना बहुत ही गज़ब का था. ऐसे अवसर के लिए मैं हर दिन दुआ मांगती थी. इतने बड़े स्टार के साथ काम करना सपने से कम नहीं था. काश ऐसा मौका दोबारा मिले.

जहां बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियां अपना रुख हॉलीवुड की तरफ कर रही हैं, वहीं सनी लियोनी की चाहत फ़िलहाल सिर्फ़ बॉलीवुड है. हालांकि सनी ये भी मानती हैं, उन्हें पहले लगता था कि बॉलीवुड में काम करना आसान होगा, पर अब उन्हें समझ में आ गया है कि इस इंडस्ट्री में बने रहना आसान नहीं है.■

राय लक्ष्मी जूली-2 से करेंगी बॉलीवुड में एंट्री

2004 में आई फिल्म जूली में नेहा धूपिया बोल्ड अवतार में नज़र आई थीं और अब इसके सीक्वल में राय लक्ष्मी अपनी बोल्डनेस से दर्शकों को दीवाना बनाने आ रही हैं. वैसे राय लक्ष्मी साउथ में काफी पॉपुलर हैं और कई हिट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.

फिल्म जूली-2 का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है जो काफी बोल्ड है. इससे पहले फिल्म के दो पोस्टर रिलीज़ हो चुके हैं, जो काफी ग्लैमरस हैं. हालांकि इस बार नेहा धूपिया की जगह साउथ की एक्ट्रेस राय लक्ष्मी अपनी बोल्डनेस से बड़े पर्दे पर आग लगाती नज़र आएंगी. साउथ की एक्ट्रेस राय लक्ष्मी जूली-2 के जरिए बॉलीवुड में एंट्री मारने की तैयारी कर रही हैं. 2004 में आई फिल्म जूली में नेहा धूपिया बोल्ड अवतार में नज़र आई थीं और अब इसके सीक्वल में राय लक्ष्मी अपनी बोल्डनेस से दर्शकों को दीवाना बनाने आ रही हैं. वैसे राय लक्ष्मी साउथ में काफी पॉपुलर हैं और कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. फिल्म जूली-2 का फर्स्ट लुक पोस्टर भी काफी बोल्ड है. वैसे जूली के सीक्वल के निर्देशक भी दीपक शिवदसानी ही हैं. वो विजय नायर के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. यह फिल्म 12 अगस्त 2016 को रिलीज़ होगी.

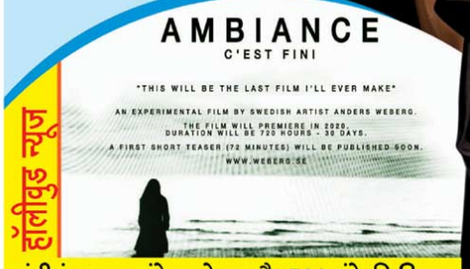

राय लक्ष्मी, मुरुगादास की सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म अकीरा में भी नज़र आएंगी. दक्षिण की सुपरहिट फिल्म मौनागुरु की इस रीमेक में वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक्शन करती दिखेंगी. 2005 में तमिल फिल्म के जरिए करियर शुरुआत करने वालीं राय लक्ष्मी को 2011 में रिलीज़ हुई फिल्म मनकथा के लिए बेस्ट निगेटिव एक्ट्रेस का खिताब भी मिल चुका है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

टाइगर श्रॉफ से क्यों नाराज हुए चीनी लोग

बाग़ी के जरिए धूम मचाने के लिए तैयार टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से चीन के लोग नाराज़ हो गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर टाइगर के लिए कई सवाल खड़े कर दिए. टाइगर ने कहा था कि कुंग-फु का जन्म भारत में हुआ है. बस क्या था इस बात से चीन के लोग नाराज़ हो गए. टाइगर के मुताबिक बौद्ध धर्म ने इस मार्शल आर्ट को ईज़ाद किया. बाद में जब इसे मानने वाले चीन गए, तो उन्होंने चीनियों को यह कला सिखाई. चीन के लोगों का मानना है कि इस मार्शल आर्ट का जन्म चीन में हुआ है. बाग़ी फिल्म के निर्देशक साबिर खान कहते हैं कि हां, ये बात सही है. कई लोगों ने आपत्ति जताई है. वैसे यह बहस बरसों पुरानी है कि कुंग-फु का जन्म चीन में हुआ है या भारत में. मार्शल आर्ट में माहिर टाइगर ने बाग़ी फिल्म में कई ऐसे करतब दिखाए हैं जो आज तक हिंदी फिल्म में नहीं देखे गए.■

एक्शन और रोमांच से भरपूर होगी बैंग-बैंग 2

ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की फिल्म बैंग बैंग ने बॉक्स ऑफिस पर जितना तहलका मचाया था, उससे उम्मीद थी कि यह जोड़ी फिर वापस आएगी. फैंस को इस एक्शन फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था. बहरहाल, बता दें कि इस फिल्म का सीक्वल तो आ रहा है, लेकिन पूरी नई स्टारकास्ट के साथ. बैंग बैंग 2 के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को फाइनल किया गया है और फिल्म में इनके साथ जैकलीन फर्नांडीस हो सकती हैं. फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि यह सही मायने में बैंग-बैंग फिल्म का सीक्वल नहीं है. यह फिल्म इंटेंस एक्शन फिल्म नहीं होगी. हां, इसमें एक्शन होगा, स्टाइल, थ्रिलर सब होगा.. लेकिन ह्यूमर के साथ. आप इसे एक्शन कॉमेडी कह सकते हैं.■

हॉलीवुड न्यूज़

एंबीयंसः सात घंटे का ट्रेलर और 720 घंटे की फिल्म

आम तौर पर फिल्मों का ट्रेलर दो से तीन मिनट का होता है, लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसी फिल्म के बारे में सुना हो, जिसका ट्रेलर 7 घंटे 20 मिनट का हो और पूरी फिल्म 720 घंटे की. हम आपको अब तक की सबसे लंबी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने में आपको पूरा एक महीना लग जाएगा. साल 2020 में हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म आ रही है. जिसका पहला शॉर्ट ट्रेलर 7 घंटे 20 मिनट का है. *एंबीयंस* नाम की इस फिल्म को देखने में आपको एक महीने का समय लगेगा. फिल्म का निर्देशन स्वीडन के एंडर्स वेबर्ग ने किया है. फिल्म का दूसरा ट्रेलर साल 2018 में लॉन्च किया जाएगा.

ये फिल्म दो परफॉर्मे आर्टिस्ट के संबंधों पर आधारित है, जो दक्षिणी स्वीडन में समंदर किनारे मिलते हैं और वहीं पर पूरी फिल्म बन जाती है. बताया जा रहा है कि फिल्म सिंगल शॉट में तैयार की गई है और इसमें कोई भी कट नहीं होगा. यानी इसे शूट करना आसान काम नहीं होगा.■

दीपिका नहीं बनेंगी सलमान की हीरोइन

पिछले कई सालों से दीपिका पादुकोण की सलमान ख़ान के साथ काम करने की इच्छा है और कुछ समय पहले अचानक मीडिया में ख़बर आई कि दीपिका का सपना पूरा होने जा रहा है. वह सलमान ख़ान की अगली फ़िल्म ट्यूबलाइट में उनके साथ काम करेंगी, जिसका निर्देशन कबीर ख़ान करेंगे. मगर ट्यूबलाइट के निर्देशक कबीर ख़ान ने इस ख़बर को ग़लत करार दिया और उनके मुताबिक दीपिका इस फ़िल्म की हीरोइन नहीं हैं. अब तक ये तय ही नहीं हुआ है कि फ़िल्म ट्यूबलाइट में सलमान ख़ान की हीरोइन कौन होगी? यहां तक कि सलमान ख़ान के अलावा किसी की कास्टिंग नहीं हुई है. कबीर ख़ान ने कहा कि मीडिया में जो भी ख़बरें आई हैं, दीपिका की कास्टिंग को लेकर, वो सब गलत हैं. मेरी अब तक दीपिका से इस फ़िल्म के बारे में कोई बात नहीं हुई है. मालूम नहीं कहां से ये ख़बर मीडिया में आई. कबीर से जब पूछा गया कि फ़िल्म ट्यूबलाइट की हीरोइन कौन होगी या दीपिका से वह इस फिल्म में काम करने के लिए बात करेंगे तो कबीर ने साफ कहा कि मेरी फिल्म में वही अभिनेत्री होगी जो किरदार को सूट करेगी. बजरंगी भाईजान के समय भी ऐसे ही कास्टिंग को लेकर कई अभिनेत्रियों के नाम जुड़े थे मगर करीना इसीलिए फिल्म में ली गई थीं. फिल्म ट्यूबलाइट में भी वही अभिनेत्री आएगी जो मेरी कहानी में फिट बैठेगी. यानी दीपिका फ़िल्म ट्यूबलाइट में काम नहीं करेंगी.■

फ्लैशबैक

सदाबहार अभिनेता देवानंद

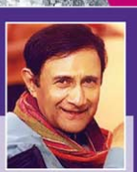

“देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेन्सर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़ कर सुनाना पड़ता था. इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपये मासिक वेतन के रूप में मिला करता था जिसमें से 45 रुपये वह अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे.”

Dev Anand

बॉलीवुड में कितने ही नायकों का दौर आया और गया. दिलीप कुमार हों या राजेश खन्ना सभी का एक दौर था. लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा अभिनेता भी है जिसने खुद को कभी उम्र के बंधन में बंधने नहीं दिया और वह सदाबहार अभिनेता देवानंद हैं. वक्त की करवटें उनकी हस्ती पर अपनी सिलवटें नहीं छोड़ पाईं. देवानंद ने करीब छह दशक से अधिक समय तक रुपहले परदे पर राज किया है. कभी अपनी एक फिल्म में उन्होंने एक गीत गुनगुनाया था *मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुंए में उड़ाता चला गया* और शायद यही गीत उनके जीवन को सबसे अच्छी तरह परिभाषित भी करता है.

देवानंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में 26 सितंबर, 1923 को हुआ था. उनके बचपन का नाम देवदत्त पिशोरीमल आनंद था. बचपन से ही उनका झुकाव अपने पिता के पेशे वकालत की ओर न होकर अभिनय की ओर था. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की. देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़ कर सुनाना पड़ता था. इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपये मासिक वेतन के रूप में मिला करता था जिसमें से 45 रुपये वह अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे. लगभग एक वर्ष तक मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद वह अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास मुंबई आ गए.

देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म *हम एक हैं* से मिला. लेकिन इस फिल्म के असफल होने से वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके. इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे. वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म *जिद्दी* देवानंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई. इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया और नवकेतन बैनर की स्थापना की. नवकेतन के बैनर तले उन्होंने वर्ष 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया जिसके निर्देशन की ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी. इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया का चयन किया जबकि अभिनेता के रूप में देवानंद खुद ही थे. यह फिल्म भी नहीं चली. इसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म *बाज़ी* के निर्देशन की ज़िम्मेदारी गुरूदत्त को सौंपी. *बाज़ी* फिल्म की सफलता के बाद देवानंद फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता के रूप में शुमार होने लगे. इस बीच देवानंद ने *मुनीम जी, दुश्मन, कालाबाजार, सी.आई.डी, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी* जैसी कई सफल फिल्मों में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया.

फिल्म अफसर के निर्माण के दौरान देवानंद का झुकाव फिल्म अभिनेत्री सुरैया की ओर हो गया था. एक गाने की शूटिंग के दौरान देवानंद और सुरैया की नाव पानी में पलट गई थी जिसमें उन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया. इसके बाद सुरैया देवानंद से बेइंतहा मोहब्बत करने लगीं लेकिन सुरैया की दादी की इजाजत न मिलने पर यह मोहब्बत परवान न चढ़ सकी. वर्ष 1954 में देवानंद ने उस जमाने की मशहूर

अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली.

देवानंद प्रख्यात उपन्यासकार आर. के. नारायण से काफी प्रभावित थे और उनके उपन्यास गाइड पर फिल्म बनाना चाहते थे. आर. के. नारायण की स्वीकृति के बाद देवानंद ने हॉलीवुड के सहयोग से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फिल्म गाइड का निर्माण किया जो देवानंद के करियर की पहली रंगीन फिल्म थी. इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए देवानंद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया. वर्ष 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से नकार दी गई, लेकिन बावजूद इसके

उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. वर्ष 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का भी निर्देशन किया जिसकी कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों का निर्देशन भी किया. इन फिल्मों में हीरा पन्ना, देश परदेस, लूटमार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर जैसी फिल्में शामिल हैं.

अपने दौर के सबसे सफल अभिनेता देवानंद अपने काले कोट की वजह से बहुत सुर्खियों में आए थे. बात उस समय की है जब देवानंद अपने अलग अंदाज और बोलने के तरीके के लिए काफी मशहूर थे. इसी समय एक ऐसा वाकया भी देखने को मिला जब न्यायालय ने उनके काले कोट को पहन कर घूमने पर पाबंदी लगा दी. वजह थी कुछ लड़कियों का उनके काले कोट के प्रति दीवानगी के कारण आत्महत्या कर लेना. दीवानगी में कई लड़कियों ने जान दे दी. इससे एक बात साफ थी कि देवानंद का किरदार हो या उनका पहनावा हमेशा सदाबहार ही रहा.

देवानंद को अपने अभिनय के लिए दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. देवानंद को सबसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म काला पानी के लिए दिया गया. उसके बाद वर्ष 1965 में भी देवानंद को फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वर्ष 2001 में देवानंद को भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. वर्ष 2002 में उनके द्वारा हिन्दी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.■